



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072026-273967
CG-DL-E-01072026-273967

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2026/आषाढ 2, 1948

No. 172]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ASHADHA 2, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2026

प्रकटीकरण विवरण

केस नंबर: एडी (ओआई)- 05/2025

विषय: जनवादी गणराज्य चीन ("चीन पीआर"), यूरोपीय संघ, सऊदी अरब साम्राज्य तथा ताइवान से उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित "एथिलीन डायमीन" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी (एंटी-डंपिंग) जांच।

सामान्य प्रकटीकरण

फा. सं. 6/05/2025-डीजीटीआर.—समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (डंपित वस्तुओं पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे आगे "प्रतिप्रतिषेध नियम" अथवा "नियम" कहा गया है) को दृष्टिगत रखते हुए, ...।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. बालाजी स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" कहा गया है) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा प्रतिप्रतिषेध नियमों के अनुसार, एथिलीन डायमाइन (जिसे आगे "विचारणाधीन उत्पाद", "संबंधित वस्तु" अथवा "ईडीए" कहा गया है) के चीन जनवादी गणराज्य (चीन पीआर), यूरोपीय संघ, सऊदी अरब साम्राज्य तथा ताइवान (जिन्हें आगे "संबंधित देश" कहा गया है) से होने वाले आयातों के संबंध में प्रतिप्रतिषेध जांच प्रारंभ किए जाने हेतु नामित प्राधिकरण (जिसे आगे "प्राधिकरण" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया।
2. और जबकि, आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत् प्रमाणित आवेदन के आधार पर, प्राधिकरण ने अधिसूचना फा. सं. 6/05/2025-डीजीटीआर दिनांक 25 मार्च, 2025 के माध्यम से, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, प्रतिप्रतिषेध नियमों के नियम 5 के अनुसार चीन पीआर, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब तथा ताइवान से विचारणाधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में प्रतिप्रतिषेध जांच प्रारंभ की। इसका उद्देश्य विचारणाधीन उत्पाद के कथित डंपिंग के अस्तित्व, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करना तथा ऐसे प्रतिप्रतिषेध शुल्क की मात्रा की सिफारिश करना था, जिसे यदि अधिरोपित किया जाए, तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हो।

ख. प्रक्रिया

3. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

3.1 प्रारंभ

- i. नियम 5(5) के अनुसार, प्राधिकरण ने जांच प्रारंभ करने की कार्यवाही से पूर्व वर्तमान प्रतिप्रतिषेध आवेदन की प्राप्ति के संबंध में भारत स्थित संबंधित देशों के दूतावासों को सूचित किया।
- ii. आवेदन की जांच करने पर प्राधिकरण को डंपिंग तथा उससे उत्पन्न क्षति के प्रथमदृष्टया साक्ष्य प्राप्त हुए। अतः, नियम 5 एवं 6 के अनुसार, अधिसूचना फा. सं. 6/05/2025-डीजीटीआर दिनांक 25 मार्च, 2025 के माध्यम से प्राधिकरण ने वर्तमान जांच कार्यवाही प्रारंभ की।
- iii. जांच अवधि (जांच की अवधि- पी ओ आई) को 1 अक्टूबर, 2023 से 30 सितंबर, 2024 (12 माह) तक माना गया। क्षति अवधि (Injury Period) के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022, 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023, 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तथा जांच अवधि को शामिल किया गया।
- iv. प्राधिकरण ने क्षति अवधि के लिए विचारणाधीन उत्पाद के लेन-देन-वार आयात आंकड़े प्राप्त करने हेतु प्रणाली एवं डेटा प्रबंधन महानिदेशालय (डीजी सिस्टम्स) से अनुरोध किया। प्राधिकरण को उक्त आंकड़े प्राप्त हुए तथा लेन-देन का विधिवत परीक्षण करने के पश्चात आवश्यक विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों पर भरोसा किया गया।

3.2 आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण का प्रसारण

- v. नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकरण ने आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर भारत में संबंधित देशों के दूतावासों, संबंधित देशों में विचारणाधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों एवं निर्यातकों, भारत में संबंधित वस्तु के ज्ञात आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षों को जांच प्रारंभ करने संबंधी अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराकर उन्हें जांच प्रारंभ होने की सूचना दी।
- vi. नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकरण ने भारत में स्थित संबंधित देशों के दूतावासों के माध्यम से उन देशों की सरकारों, संबंधित आयातकों के ज्ञात निर्यातकों तथा आवेदन की प्रति लिखित रूप में मांगने वाले अन्य हितबद्ध पक्षों को आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की एक प्रति उपलब्ध कराई।

- vi i. प्राधिकरण ने भारत में स्थित संबंधित देशों के दूतावासों के माध्यम से उन देशों की सरकारों को प्रश्नावली प्रेषित की। संबंधित देशों की सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे अपने देश में विचारणाधीन उत्पाद के उत्पादकों को जांच प्रारंभ करने संबंधी अधिसूचना तथा प्रश्नावली अग्रेषित करें और उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह दें।
- vi i i. प्राधिकरण ने नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु संबंधित वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली प्रेषित की।
- i x. प्राधिकरण ने नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत में संबंधित वस्तु के ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं को आयातक प्रश्नावली प्रेषित की।

3.3 संबंधित देशों के निर्यातकों तथा भारत के आयातकों/उपयोगकर्ताओं द्वारा भागीदारी

- x. निम्नलिखित उत्पादकों एवं निर्यातकों ने वर्तमान जांच में स्वयं को हितबद्ध पक्ष के रूप में पंजीकृत कराया है :

क्र. सं.	हितबद्ध पक्ष का नाम
क.	मेसर्स बीएएसएफ एंटवर्पेन एनवी, बेल्जियम
ख.	मेसर्स बीएएसएफ ईओओडी, बुल्गारिया
ग.	मेसर्स बीएएसएफ एस्पानोला एसएलयू, स्पेन
घ.	मेसर्स बीएएसएफ फ्रांस एस.ए.एस., फ्रांस
ङ.	मेसर्स बीएएसएफ हांगकांग लिमिटेड., हांगकांग
च.	मेसर्स बीएएसएफ हंगारिया केएफटी., हंगरी
छ.	मेसर्स बीएएसएफ-वाईपीसी कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर
ज.	मेसर्स बीएएसएफ आयरलैंड डीएसी, आयरलैंड
झ.	मेसर्स बीएएसएफ इटालिया एस.पी.ए., इटली
ञ.	मेसर्स बीएएसएफ नेदरलैंड बी.वी., नीदरलैंड
ट.	मेसर्स बीएएसएफ एसई, जर्मनी
ठ.	मेसर्स बीएएसएफ स्पोल एस.आर.ओ., चेक गणराज्य
ड.	मेसर्स बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड
ढ.	मेसर्स डॉव केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, दुबई शाखा, यूएई
ण.	मेसर्स डॉव सऊदी अरब प्रोडक्ट मार्केटिंग अरेबिया बी.वी., दुबई शाखा, यूएई
त.	मेसर्स डॉव केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड., दुबई शाखा, यूएई
थ.	मेसर्स सदारा केमिकल कंपनी, सऊदी अरब साम्राज्य
द.	बीएएसएफ बेल्जियम कोऑर्डिनेशन सेंटर, बेल्जियम

ध.	बीएएसएफ ओय, फिनलैंड
न.	बीएएसएफ एसआरएल, रोमानिया

- xi. विषय जांच की प्रारंभिक सूचना के प्रत्युत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/उपयोगकर्ताओं ने स्वयं को इस जांच में हितबद्ध पक्ष के रूप में पंजीकृत कराया है।

क्र. सं.	हितबद्ध पक्ष का नाम
क.	मेसर्स कार्डोलाइट स्पेशल्टी केमिकल्स इंडिया एलएलपी
ख.	मेसर्स कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड (सी आई एल)
ग.	मेसर्स डॉव केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (डीसीआईपीएल)
घ.	मेसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
ड.	मेसर्स ह्योसंग इंडिया प्रा. लि.
च.	मेसर्स इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

- xii. प्राधिकरण ने व्यापक अर्थव्यवस्था पर शुल्कों के प्रभाव एवं जनहित का आकलन करने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू की एक प्रति संबंधित देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों एवं उपयोगकर्ताओं तथा आवेदक को भेजी गई। ईआईक्यू को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया। निम्नलिखित हितबद्ध पक्षों ने अपने अभ्यावेदन/प्रस्तुतियाँ दाखिल की हैं:

क्र. सं.	हितबद्ध पक्ष का नाम
क.	बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड
ख.	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड
ग.	कार्डोलाइट स्पेशल्टी केमिकल्स इंडिया एलएलपी

- xiii. निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृत कराने वाले सभी हितबद्ध पक्षों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षों को यह निर्देश दिया गया कि वे वर्तमान कार्यवाही में अपने द्वारा दायर सभी अभ्यावेदनों के गैर-गोपनीय संस्करण को अन्य सभी हितबद्ध पक्षों के साथ परस्पर रूप से साझा (प्रसारित) करें।

3.4 आगे की प्रक्रियाएँ

- xiv. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकरण ने हितबद्ध पक्षों को 7 अक्टूबर 2025 को आयोजित एक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। तत्पश्चात, नामित प्राधिकरण में परिवर्तन के कारण 18 दिसंबर 2025 को एक अन्य मौखिक सुनवाई आयोजित की गई। दोनों मौखिक सुनवाइयों में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षों को निर्देश दिया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें तथा उसके पश्चात प्रत्युत्तर (rejoinder) प्रस्तुत करें। प्राधिकरण की स्वीकृत प्रथा के अनुसार, पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तरों के गैर-गोपनीय संस्करणों का परस्पर वितरण (प्रसार) नहीं किया गया।

- xv. नियम 6(8) के अनुसार, जहाँ किसी हितबद्ध पक्ष ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुँच से इनकार किया है या समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न की है, ऐसे पक्षों को प्राधिकरण द्वारा असहयोगी (असहयोगी) माना गया है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष अभिलिखित किए गए हैं।
- xvi. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना का प्राधिकरण द्वारा गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में परीक्षण किया गया। संतुष्ट होने पर, प्राधिकरण ने जहाँ आवश्यक समझा, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया और ऐसी जानकारी को गोपनीय मानते हुए अन्य हितबद्ध पक्षों को प्रकट नहीं किया गया। जहाँ संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षों को यह निर्देश दिया गया कि वे प्रस्तुत की गई गोपनीय सूचना का एक गैर-गोपनीय सारांश भी उपलब्ध कराएँ।
- xvii. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकरण ने वर्तमान कार्यवाही के लिए आवश्यक समझे जाने तक आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन (सत्यापन) किया। प्राधिकरण ने इस मामले में अपने विश्लेषण हेतु हितबद्ध पक्षों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
- xviii. प्राधिकरण ने यह निर्धारित करने के लिए कि क्या डंपिंग मार्जिन से कम शुल्क भी आवेदक को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त होगा, संबंधित उत्पाद के लिए गैर-हानिकारक मूल्य (गैर-हानिकारक मूल्य) की गणना की। एन आई पी की गणना भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन एवं बिक्री की इष्टतम लागत तथा उत्पादन लागत के आधार पर, आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए की गई है।
- xix. प्राधिकरण ने अंतिम निष्कर्ष निकालते समय कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों, प्रस्तुत की गई सूचनाओं तथा दिए गए अभ्यावेदनों का, जहाँ तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित थे और वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक थे, परीक्षण किया।
- xx. ‘***’ उन सूचनाओं को दर्शाता है जो किसी पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई हैं और जिन्हें प्राधिकरण द्वारा नियमों के अंतर्गत गोपनीय माना गया है।
- xxi. प्राधिकरण द्वारा विषय जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 84.27 है।

ग. उत्पाद जिसके संबंध में जांच की जा रही है एवं समान वस्तु

ग.1 अन्य इच्छुक पक्षों (निर्यातकों, आयातकों और उपयोगकर्ताओं) द्वारा प्रस्तुतियाँ

4. अन्य हितबद्ध पक्षों ने उत्पाद जिसके संबंध में जांच की जा रही है तथा समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं।
- i. इंडोरामा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने यह प्रस्तुत किया है कि आवेदक स्पैन्डेक्स यार्न के उत्पादन में प्रयुक्त एथिलीन डायमीन का उत्पादन नहीं करता है, और इसलिए उस सीमा तक उत्पाद जिसके संबंध में जांच की जा रही है, के दायरे से उपयोगकर्ता-आधारित छूट (उपयोगकर्ता-आधारित छूट) प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।
- ii. इंडोरामा को स्पैन्डेक्स यार्न के उत्पादन के लिए उच्च शुद्धता वाले एथिलीन डायमीन की आवश्यकता होती है, जहाँ थोड़ी सी भी अशुद्धियाँ उत्पाद के प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। एथिलीन डायमीन को शुद्धता और जल सामग्री के सटीक विनिर्देशों को पूरा करना आवश्यक है।
- iii. कई बार बातचीत और टेस्टिंग के बावजूद, आवेदक इन स्पेसिफिकेशन्स को पूरा करने वाला ईडीए सप्लायर नहीं कर पाया है। बालाजी ने अपनी जमा की गई टेस्ट रिपोर्ट्स में माना कि वे दूसरे पैरामीटर्स को तो पूरा कर सकते थे, लेकिन उनके ईडीए में पानी की मात्रा 0.28% थी, जो इंडोरामा की ज़रूरी सीमा से ज़्यादा थी।

- iv. ह्योसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के निर्माण के लिए विचाराधीन उत्पाद को दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया है। उनका तर्क है कि इससे इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न बनाने वालों की निर्यात मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होगी।
- v. थॉरिटी ने पहले चीन पीआर और तुर्की से आने वाले डाइमिथाइलएसीटामाइड (डीएमएसी) की मिड-टर्म समीक्षा (14.10.2020) में स्पैन्डेक्स बनाने वालों के लिए इसी तरह की खास कच्चे माल की ज़रूरतों को माना था, जहाँ असल इस्तेमाल करने वालों की ज़रूरतों के आधार पर कुछ उत्पादों को छूट दी गई थी।
- vi. डीजीटीआर ने असली यूज़र्स के लिए छूट देने की अनुमति भी नियमित रूप से दी है, जैसे कि “स्टेनलेस स्टील 300 और 400 सीरीज़ के कोल्ड रोल्ड फ़्लैट प्रोडक्ट्स” के मामले में 29.09.2025 की शुरुआत की सूचना में, जहाँ कुछ खास कामों के लिए कुछ चौड़ाई वाले प्रोडक्ट्स को छूट दी गई थी।
- vii. अगर आवेदक इस छूट को न मानने का अनुरोध करता है, तो अथॉरिटी उनसे एक अंडरटेकिंग (लिखित वचन) मांग सकती है जिसमें वे यह पुष्टि करें कि वे ज़रूरी स्पेसिफिकेशन वाला एथिलीन डाई-अमाइन सप्लाय कर सकते हैं। अगर वे ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं, तो अथॉरिटी को संबंधित ट्रेड नोटिस के तहत एक साल की 'कूलिंग-ऑफ अवधि' को हटा देना चाहिए ताकि बिना किसी रोक-टोक के इंपोर्ट किया जा सके।

ग.2 आवेदक द्वारा प्रस्तुति

5. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित बातें कही हैं:

- i. विचाराधीन उत्पाद 'एथिलीन डायमाइन' है और इसे 'ईडीए' के नाम से भी जाना जाता है।
- ii. जिस प्रोडक्ट की बात हो रही है, वह एक ऐसा केमिकल है जिसमें दो रिएक्टिव अमीन ग्रुप होते हैं, जो इसे कई तरह की इंडस्ट्रियल प्रक्रियाओं में एक ज़रूरी इंग्रीडिएंट बनाते हैं। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से स्पेशलिटी कंपाउंड, फंगीसाइड, एग्नोकेमिकल, कोटिंग और पॉलीमर जैसे केमिकल बनाने में किया जाता है। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल एग्नोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल जैसे उद्योगों में बड़े पैमाने पर किया जाता है।
- iii. आवेदक द्वारा बनाए गए समान उत्पाद और आयातित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है।
- iv. चीन पी आर और तुर्की से डाइमिथाइलएसीटामाइड (डीएमएसी) और स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ़्लैट प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर एंटी-डंपिंग जांच के संबंध में अन्य इच्छुक पार्टियों का भरोसा गलत है। दोनों मामलों में, प्रोडक्ट को बाहर रखने की छूट केवल तभी दी गई थी जब यूज़र्स ने टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के साथ, फंक्शनल रूप से एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल न हो पाने (कार्यात्मक रूप से प्रतिस्थापन-अक्षमता) का स्पष्ट, वेरिफ़ाई करने योग्य और साबित करने योग्य सबूत दिया हो। मौजूदा मामले में ऐसा कोई सबूत नहीं है।
- v. स बात पर कि आवेदक तय स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रोडक्ट सप्लाय नहीं कर पा रहा है, घरेलू इंडस्ट्री ने कहा है कि यूज़र्स जिन स्पेसिफिकेशन शीट का हवाला दे रहे हैं, वे पुरानी हो चुकी हैं। घरेलू इंडस्ट्री ने 2020-21 के बाद टेक्निकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए काफी रिसर्च और डेवलपमेंट का काम किया है, और अब स्पैन्डेक्स बनाने वाली दूसरी कंपनियों को हाई प्योरिटी वाला एथिलीन डाई-अमाइन सप्लाय किया जा रहा है। एचपीएलसी (हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी) टेस्ट रिपोर्ट पर भरोसा करने के मामले में, घरेलू इंडस्ट्री ने कहा है कि यूज़र्स जिन एचपीएलसी टेस्ट रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, उन्हें कभी भी घरेलू इंडस्ट्री के साथ शेयर नहीं किया गया, जबकि इसकी मांग की गई थी।
- vi. यूज़र-बेस्ड एक्सक्लूज़न (उपयोगकर्ता-आधारित छूट) के अनुरोध पर यह कहा गया है कि ऐसा अनुरोध उचित नहीं है, क्योंकि अगर इंडोरामा ऑर्डर दे, तो घरेलू उद्योग ज़रूरतों को पूरा करने वाला ईडीए बनाने और सप्लाय करने में सक्षम है। घरेलू उद्योग अन्य स्पैन्डेक्स यूज़र्स को भी यह प्रोडक्ट सप्लाय कर रहा है।

- vii. स्पेसिफिकेशन्स की तुलना से पता चलेगा कि घरेलू इंडस्ट्री का प्रोडक्ट सभी ज़रूरी पैरामीटर्स को पूरा करता है। इसके अलावा, उसी प्लांट का इस्तेमाल करके और बिना किसी अतिरिक्त मशीनरी के, कस्टमर की ज़रूरतों के हिसाब से स्पेसिफिकेशन्स में बदलाव किया जा सकता है। अगर ज़रूरत पड़ी, तो घरेलू इंडस्ट्री अथॉरिटी को अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार है।

ग.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

6. शुरुआत के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को इस प्रकार परिभाषित किया गया था:

“3. इस जांच में जिस प्रोडक्ट (पीयूसी) पर विचार किया जा रहा है, वह 'एथिलीन डायमाइन' है, जिसे शॉर्ट में 'ईडीए' कहा जाता है। यह प्रोडक्ट एक साफ़, रंगहीन लिक्विड है। इसका फ्रीज़िंग पॉइंट 11°C और बॉइलिंग पॉइंट 117°C है।”

ईडीए एक ऐसा केमिकल है जिसमें दो रिएक्टिव अमीन ग्रुप होते हैं, जो इसे कई तरह की इंडस्ट्रियल प्रक्रियाओं में एक ज़रूरी चीज़ बनाते हैं। ईडीए का इस्तेमाल मुख्य रूप से स्पेशल कंपाउंड, फंगीसाइड, एग्रोकेमिकल, कोटिंग और पॉलीमर जैसे केमिकल बनाने में किया जाता है। इसके अलावा, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल जैसे उद्योगों में बड़े पैमाने पर किया जाता है।

ईडीए को कस्टम्स टैरिफ एक्ट, 1975 के तहत चैप्टर 29, यानी "ऑर्गेनिक केमिकल्स" में, टैरिफ क्लासिफिकेशन के सब-हेडिंग 2921 21 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आवेदक ने बताया है कि ईडीए को एच एस कोड 2921 21 00 के तहत आयात किया जाता है। कस्टम्स क्लासिफिकेशन केवल संकेत देने वाला है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

7. स्पैन्डेक्स यार्न के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले एथिलीन डायमाइन को बाहर रखने के मामले में, घरेलू इंडस्ट्री ने कहा है कि उसने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए काफी रिसर्च और डेवलपमेंट किया है। घरेलू इंडस्ट्री ने माना है कि भले ही वह पहले स्पेसिफिकेशन पूरे नहीं कर पाती थी, लेकिन अब वह डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट सप्लाय कर सकती है। घरेलू इंडस्ट्री ने यह भी बताया है कि उसने दूसरे स्पैन्डेक्स प्रोड्यूसर्स को ईडीए सप्लाय किया है, और प्रोडक्ट यूज़र इंडस्ट्री की सभी टेक्निकल ज़रूरतों को पूरा करता है। कस्टमर की ज़रूरतों के आधार पर प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन में बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए किसी नई मशीन की ज़रूरत नहीं है, और पूरी प्रोसेस उसी प्लांट में की जा सकती है। घरेलू इंडस्ट्री ने टेक्निकल एनालिसिस सर्टिफिकेट भी दिया है, जिससे पता चलता है कि वह ज़रूरी स्पेसिफिकेशन वाला घरेलू प्रोडक्ट दे सकती है। सिर्फ़ एक टेक्निकल पैरामीटर में अंतर होने से यह साबित नहीं होता कि दोनों प्रोडक्ट एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, खासकर तब जब घरेलू इंडस्ट्री ने खुद स्पैन्डेक्स के दूसरे प्रोड्यूसर्स को यह प्रोडक्ट बेचा हो। इच्छुक पार्टियों का इसे बाहर रखने का दावा पूरी तरह से पानी सोखने की क्षमता पानी सोखना) पर आधारित है। हालाँकि, अथॉरिटी का मानना है कि घरेलू इंडस्ट्री ने इस बात के पर्याप्त सबूत दिए हैं कि वह ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जिसका इस्तेमाल स्पैन्डेक्स यार्न बनाने में किया जा सकता है और घरेलू इंडस्ट्री द्वारा सप्लाय किया गया प्रोडक्ट इम्पोर्ट किए गए प्रोडक्ट जैसा ही है। इसे देखते हुए, एंड-यूज़र के आधार पर कोई छूट देना भी सही नहीं लगता।
8. ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, अथॉरिटी जांच शुरू होने के समय तय किए गए प्रोडक्ट के दायरे को ही पक्का रखती है, जिसे नीचे दिया गया है।
- इस जांच में जिस प्रोडक्ट पर विचार किया जा रहा है, वह 'एथिलीन डायमाइन' है, जिसे 'ईडीए' के नाम से भी जाना जाता है।
9. जिस प्रोडक्ट की बात हो रही है, उसे बनाने की प्रक्रिया में मोनो इथेनॉलमाइन और अमोनिया की प्रतिक्रिया (रिएक्शन) शामिल है। यह प्रतिक्रिया हाइड्रोजन के माहौल में, एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में, लगभग 150 से 200

किग्रा/सेमी² के दबाव और 150 से 225 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होती है। इससे एथिलीन डायमाइन, डायथिलीन ट्रायमाइन, पाइपरज़ीन, अमीनो एथिल पाइपरज़ीन, हाइड्रॉक्सिल एथिल पाइपरज़ीन और अमीनो एथिल इथेनॉलमाइन का मिश्रण बनता है। यह प्रतिक्रिया एक कंटीन्यूअस फ्लो रिएक्टर में होती है। रिएक्टर से मिलने वाले रिएक्शन मिक्सचर को फिर प्रोडक्ट्स को अलग करने के लिए कई बार डिस्टिलेशन (आसवन) प्रक्रिया से गुजारा जाता है। बचे हुए कच्चे माल को वापस रिएक्शन स्टेज में भेज दिया जाता है ताकि उनसे ज़रूरी प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें।

10. जिस प्रोडक्ट की बात हो रही है, उसे कस्टम टैरिफ के चैप्टर 29 में "ऑर्गेनिक केमिकल्स" (कार्बनिक रसायन) के तहत रखा गया है। यह कस्टम टैरिफ एक्ट, 1975 के चैप्टर 29 और एच एस कोड 2921 21 00 के अंतर्गत आता है। अथॉरिटी ने कस्टम क्लासिफिकेशन को केवल संकेत के तौर पर माना है और इस जांच के दायरे के लिए इसे बाध्यकारी नहीं माना है। भारत में इस प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर कोई रोक नहीं है क्योंकि यह 'ओपन जनरल लाइसेंस' के तहत आता है। इस प्रोडक्ट पर लागू बेसिक कस्टम ड्यूटी 7.5% है। इस प्रोडक्ट के लिए माप की तय इकाई मीट्रिक टन (मीट्रिक टन) है, और इस जांच के लिए भी इसी इकाई को अपनाया गया है।

11. नियमों के नियम 2(घ) में "समान वस्तु (समान वस्तु)" की परिभाषा निम्नानुसार दी गई है:

"एक जैसी वस्तु" (like article) का मतलब है ऐसी वस्तु जो भारत में डंपिंग के लिए जांच की जा रही वस्तु के बिल्कुल समान या हर तरह से वैसी ही हो; या अगर ऐसी वस्तु न हो, तो कोई दूसरी वस्तु जो भले ही हर तरह से वैसी न हो, लेकिन उसकी विशेषताएं जांच की जा रही वस्तु की विशेषताओं से काफी मिलती-जुलती हों।"

12. अथॉरिटी का मानना है कि ऊपर बताई गई परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि दो वस्तुओं को 'एक जैसा' मानने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वे हर तरह से बिल्कुल एक जैसी हों। अगर दो वस्तुओं की विशेषताएं काफी हद तक मिलती-जुलती हैं, तो इतनी समानता ही उन्हें 'एक जैसा' मानने के लिए काफी है। यह तय करने के लिए कि क्या दो वस्तुओं की विशेषताएं काफी हद तक मिलती-जुलती हैं, अथॉरिटी उत्पादों की तकनीकी और व्यावसायिक रूप से एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकने की क्षमता (प्रतिस्थापन) को अहम पैमाना मानती है। दो उत्पाद उत्पादन की तकनीक, डिज़ाइन, स्टाइल, क्वालिटी आदि के मामले में अलग-अलग दिख सकते हैं, फिर भी जांच के मकसद से उन्हें 'एक जैसा' माना जा सकता है, बशर्ते वे बाज़ार में एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकें और बदले जा सकें—ऐसा उनके एक जैसे अंतिम इस्तेमाल और ग्राहकों की पसंद के कारण हो सकता है।

13. अथॉरिटी का मानना है कि संबंधित देशों से एक्सपोर्ट किए गए प्रोडक्ट और घरेलू इंडस्ट्री द्वारा सप्लाई किए गए समान प्रोडक्ट के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू इंडस्ट्री द्वारा बनाए गए और संबंधित देशों से इम्पोर्ट किए गए प्रोडक्ट, फिजिकल और केमिकल विशेषताओं जैसे गुणों के मामले में एक-जैसे हैं। कंज्यूमर घरेलू और इम्पोर्टेड दोनों तरह के मटीरियल का इस्तेमाल एक-दूसरे की जगह कर रहे हैं और एक्सपोर्टर तथा घरेलू इंडस्ट्री ने एक ही तरह के कस्टमर्स को वही प्रोडक्ट बेचा है। इसलिए, अथॉरिटी का यह मानना है कि घरेलू इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट के समान ही है।

14. अथॉरिटी ने जांच शुरू करने के नोटिस में विचाराधीन प्रोडक्ट के दायरे और पीसीएन मैथडोलॉजी के बारे में बताया। संबंधित पक्षों से कहा गया कि अगर उनके पास पीयूसी-पीसीएन मैथडोलॉजी पर कोई टिप्पणी है, तो वे जांच शुरू होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर उसे दें।

15. अथॉरिटी ने विचाराधीन प्रोडक्ट के दायरे और पीसीएन मैथडोलॉजी पर संबंधित पक्षों की टिप्पणियों पर विचार किया। हालाँकि, अथॉरिटी का मानना था कि मौजूदा जांच में किसी चीज़ को बाहर रखने या पीसीएन बनाने का कोई ठोस आधार नहीं था। इसलिए, जवाब दाखिल करने के मकसद से विचाराधीन प्रोडक्ट का दायरा और पीसीएन मैथडोलॉजी वही रखी गई, जो 25 मार्च, 2025 के शुरुआती नोटिफिकेशन में बताई गई थी।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्टैंडिंग

घ.1 विरोधी हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन

16. विरोधी हितबद्ध पक्षों ने घरेलू उद्योग के दायरे एवं उसकी स्थिति (खड़ा) के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं।
- आवेदक ने एक और घरेलू उत्पादक के होने का दावा किया है, लेकिन उसका नाम या उत्पादन से जुड़ी जानकारी नहीं बताई है, जिससे उसके 'स्टैंडिंग' दावे की सटीकता पर गंभीर संदेह पैदा होता है।

घ.2 आवेदक द्वारा प्रस्तुति

17. आवेदक ने घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित बातें कही हैं:
- आवेदक, विचाराधीन उत्पाद 'एथिलीन डायमाइन' (ईडीए) का भारत में एकमात्र उत्पादक है।
 - आवेदक के अलावा, 'डायमाइन्स एंड केमिकल्स लिमिटेड' भी इसी तरह के उत्पाद का एक और निर्माता है, जिसकी क्षमता 2500 मीट्रिक टन है। हालाँकि, आवेदक का मानना है कि यह निर्माता अभी कोई उत्पादन नहीं कर रहा है।
 - आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान संबंधित देशों में से किसी से भी विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
 - आवेदक का संबंधित देशों के किसी निर्यातक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से कोई संबंध नहीं है।

घ.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

18. नियमों का नियम 2(b) 'घरेलू उद्योग' शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है:

"(b) "घरेलू उद्योग" का मतलब है वे घरेलू उत्पादक जो कुल मिलाकर वैसी ही वस्तु के निर्माण और उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल हैं, या जिनका उस वस्तु का सामूहिक उत्पादन, उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है; सिवाय तब, जब ऐसे उत्पादक कथित तौर पर डंप की गई वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से जुड़े हों या खुद उसके आयातक हों—ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' शब्द का अर्थ बाकी उत्पादकों से माना जा सकता है।"

19. यह आवेदन बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड ने दायर किया है। रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी के अनुसार, भारत में संबंधित सामान का एक और उत्पादक है, जिसका नाम डायमाइन्स एंड केमिकल्स लिमिटेड है। इस जांच को शुरू करने से पहले अथॉरिटी ने डायमाइन्स एंड केमिकल्स लिमिटेड को सूचना भेजी थी। हालाँकि, उस उत्पादक ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। घरेलू उद्योग का दावा है कि नुकसान की अवधि के दौरान वह उत्पादक संबंधित उत्पाद का उत्पादन नहीं कर रहा था।
20. अथॉरिटी ने डीजी सिस्टम के ट्रांज़ैक्शन-वाइज़ डेटा की जांच की है, और यह पाया गया है कि बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। यह भी देखा गया है कि बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड का संबंध संबंधित देशों से विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से नहीं है।

21. रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी के आधार पर, अथॉरिटी ने जांच की अवधि के लिए भारतीय उत्पादन और भारतीय उत्पादन में बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड की हिस्सेदारी इस प्रकार तय की है:

क्र. सं.	विवरण	उत्पादन (मीट्रिक टन)	हिस्सा (%)
1	आवेदक का उत्पादन	***	100
2	कुल/सकल भारतीय उत्पादन	***	100

22. बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड नियम 2(ख) के अर्थ में एक पात्र घरेलू उद्योग है तथा नियम 5(3) के अनुसार स्थिति (स्थिति) की आवश्यक शर्तों को पूरा करता है। अतः प्राधिकरण यह मानता है कि बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करता है।

ड. गोपनीयता एवं विविध अभ्यावेदन

ड.1 विरोधी हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन

23. विरोधी हितबद्ध पक्षों ने निम्नलिखित विविध अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं:
- उनके उत्तरों में की गई सभी गोपनीयता संबंधी दावे एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 7 तथा प्राधिकरण द्वारा जारी ट्रेड नोटिस संख्या 10/2018 दिनांक 27 सितंबर 2018 के अनुरूप हैं, क्योंकि ये दावे केवल ऐसी स्वामित्व वाली व्यावसायिक जानकारी (स्वामित्व वाली व्यावसायिक जानकारी) के संबंध में किए गए हैं, जिनका प्रकटीकरण होने पर कंपनी को गंभीर व्यावसायिक क्षति हो सकती है तथा उसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
 - उत्पादों की सूची का प्रकटीकरण ट्रेड नोटिस संख्या 10/2018 के अनुबंध-II के अंतर्गत कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। तथापि, उत्पादों की सूची कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
 - कंपनियों ने उत्पाद जिसके संबंध में जांच की जा रही है, के उत्पादन में शामिल सभी संबंधित पक्षों (संबंधित पक्ष) के नामों का विधिवत प्रकटीकरण किया है।
 - वित्तीय एवं लेखा प्रणाली (वित्तीय एवं लेखा प्रणाली) से संबंधित सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है तथा ट्रेड नोटिस के अनुबंध-II के अनुसार इसका प्रकटीकरण आवश्यक भी नहीं है।
 - सदारा केमिकल कंपनी ने यह प्रस्तुत किया है कि उत्पाद जिसके संबंध में जांच की जा रही है, की निर्माण प्रक्रिया अत्यंत स्वामित्वाधीन (स्वामित्वाधीन) है तथा यह उत्पादक के तकनीकी ज्ञान (तकनीकी ज्ञान) और व्यापारिक गोपनीयता (व्यापारिक गोपनीय जानकारी) का एक मूलभूत घटक है। तथापि, कंपनी ने उत्पादन प्रक्रिया का गैर-गोपनीय सार (गैर-गोपनीय सारांश) प्रदान किया है।
 - निर्यात मूल्य में किए गए समायोजनों (समायोजन) के गैर-प्रकटीकरण के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि विरोधी पक्षों द्वारा निर्यात मूल्य की गणना में दावा किए गए समायोजन प्रभावली के उत्तर के परिशिष्ट 3ए/3बी के गैर-गोपनीय संस्करण में पारदर्शी रूप से प्रकट किए गए हैं। ये समायोजन कंपनी-विशिष्ट वाणिज्यिक डेटा से संबंधित हैं, जिनमें वित्तीय एवं लेन-देन संबंधी विवरण शामिल हैं, जो प्रकृति में गोपनीय हैं। यद्यपि समायोजनों की पूर्ण कार्यप्रणाली (कार्यप्रणाली) एवं उनकी मात्रा (मात्रा) को गोपनीय रखा गया है, तथापि समायोजनों के प्रकार को परिशिष्टों के गैर-गोपनीय संस्करण में पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया गया है।
 - आवेदक ट्रेड नोटिस 10/2018 का पालन करने में विफल रहा। एनआईपी और नेट सेल्स रियलाइजेशन का खुलासा करने में विफल रहा।

viii. रदर्शिता और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, अथॉरिटी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मेट में ही इम्पोर्ट डेटा तक पहुँच का अनुरोध करने के लिए एक्सॉटिक डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के फैसले और ट्रेड नोटिस नंबर 07/2018 का हवाला दिया गया।

इ.2 आवेदक द्वारा प्रस्तुति

24. आवेदक ने निम्नलिखित विविध बातें कही हैं:

- i. विरोधी पक्ष उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादित उत्पादों की सूची, संबंधित कंपनियों की सूची और कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वित्तीय और अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा गोपनीयता का दावा करते हैं। ट्रेड नोटिस के अनुसार संबंधित पक्षों का खुलासा किया जाना चाहिए।
- ii. एक्सपोर्ट करने वालों ने नॉर्मल वैल्यू और नेट एक्सपोर्ट प्राइस की गणना के लिए ज़रूरी एडजस्टमेंट की जानकारी नहीं दी है। नॉर्मल वैल्यू और एक्सपोर्ट प्राइस में एडजस्टमेंट की लिस्ट की जानकारी अथॉरिटी द्वारा फ़ाइनल नतीजों में बताई जाती है। इसलिए, प्रोड्यूसर/एक्सपोर्टर ने जो जानकारी दी है, उसे बाद में सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इस वजह से, इस मामले में गोपनीयता का दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है।
- iii. वितरण चैनलों को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है।
- iv. संबंधित आयातकों ने सभी एग्ज़िबिट और एनेक्ज़र को गोपनीय बताया है और उनके ट्रेड्स का भी खुलासा नहीं किया है, जिससे आवेदक के लिए सार्थक टिप्पणी करना मुश्किल हो गया है।
- v. कार्डोलाइट और इंडोरामा ने विचाराधीन प्रोडक्ट की खरीद, कुल बिक्री टर्नओवर, पीयूसी के इस्तेमाल की जानकारी, लागत का ब्योरा और प्रोडक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसके अलावा, इंडोरामा ने प्रोडक्शन प्रोसेस को भी गोपनीय बताया है।
- vi. अन्य इच्छुक पक्षों ने आरोप लगाया कि घरेलू उद्योग ट्रेड नोटिस 10/2018 का पालन करने में विफल रहा; हालाँकि, घरेलू उद्योग ने आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण में एनआईपी (रेंज में) और नेट सेल्स रियलाइज़ेशन (इंडेक्स/ट्रेड के रूप में) सहित सभी संबंधित जानकारी का खुलासा किया है।

इ.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

25. अथॉरिटी ने नियम 6(7) के अनुसार, अलग-अलग पक्षों द्वारा दी गई जानकारी का वह वर्शन (संस्करण) सभी दूसरे इच्छुक पक्षों को उपलब्ध कराया जो गोपनीय नहीं था। इच्छुक पक्षों द्वारा सौंपी गई जानकारी की गोपनीयता के संबंध में, नियमों का नियम 7 इस प्रकार है:

“7. गोपनीय जानकारी:

(1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उप-नियम (4) में दी गई किसी भी बात के बावजूद, नियम 5 के उप-नियम (1) के तहत मिलीं अर्जियों की कॉपी, या जांच के दौरान किसी पक्ष द्वारा तय अधिकारी को गोपनीय तौर पर दी गई कोई भी जानकारी—जब तय अधिकारी उसकी गोपनीयता के बारे में संतुष्ट हो जाए—तो उसे गोपनीय ही माना जाएगा और ऐसी जानकारी देने वाले पक्ष की खास मंजूरी के बिना ऐसी कोई भी जानकारी किसी दूसरे पक्ष को नहीं बताई जाएगी।

(2) तय अधिकारी, गोपनीय आधार पर जानकारी देने वाली इच्छुक पार्टियों से उस जानकारी का गैर-गोपनीय सारांश देने के लिए कह सकता है। अगर जानकारी देने वाली पार्टी की राय में उस जानकारी का सारांश नहीं बनाया जा सकता है, तो वह पार्टी तय अधिकारी को यह बताते हुए एक बयान दे सकती है कि सारांश क्यों नहीं बनाया जा सकता।

(3) उप-नियम (2) में दी गई किसी भी बात के बावजूद, अगर तय अधिकारी को यह लगता है कि जानकारी को गोपनीय रखने का अनुरोध सही नहीं है, या जानकारी देने वाला व्यक्ति जानकारी को सार्वजनिक करने या उसे सामान्य या संक्षिप्त रूप में बताने की अनुमति देने को तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी को नज़रअंदाज़ कर सकता है।

26. देखा गया है कि घरेलू उद्योग और संबंधित पक्षों ने कई तरह की जानकारी को गोपनीय रखने का दावा किया है, जैसे कि उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, बाजार में हिस्सेदारी, स्टॉक, बिक्री मूल्य, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर रिटर्न, गैर-हानिकारक मूल्य, उत्पादन लागत से जुड़ी जानकारी, सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य, डंपिंग मार्जिन, लैंडेड मूल्य, नुकसान का मार्जिन, मूल्य समायोजन, लाभ से जुड़ी जानकारी, बिक्री के चैनल, बिक्री और खरीद के दस्तावेज, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम आदि। यह भी देखा गया है कि जहां भी जानकारी नुकसान की अवधि से संबंधित है, उसे इंडेक्स के आधार पर दिया गया है। जहां जानकारी किसी एक वर्ष से संबंधित है, उसे एक रेंज में बताया गया है, बशर्ते ऐसी जानकारी देने से उसकी गोपनीयता पर कोई असर न पड़े। संबंधित पक्षों ने कई सहायक दस्तावेजों और जानकारी को गोपनीय रखने का दावा किया है, जिन्हें उन्होंने सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया है। जिन मामलों में किसी संबंधित पक्ष ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहीं किए हैं, उन्हें गोपनीय माना गया है। जहां भी संबंधित पक्षों ने किसी दस्तावेज को गोपनीय बताया है, वहां यह देखा गया है कि उनका कहना है कि इन दस्तावेजों का सारांश नहीं बनाया जा सकता और उन्होंने इसके कारण भी बताए हैं। संबंधित पक्षों का दावा था कि घरेलू उद्योग ने गैर-हानिकारक मूल्य की रेंज का खुलासा नहीं किया। बाद में देखा गया कि वही जानकारी सार्वजनिक कर दी गई थी।
27. अथॉरिटी ने सभी जांचों में घरेलू उद्योगों, विदेशी उत्पादकों और अन्य संबंधित पक्षों द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेजों के मामले में संबंधित पक्षों को गोपनीयता का दावा करने की लगातार अनुमति दी है। अथॉरिटी ने देखा है कि सभी संबंधित पक्षों ने अपनी कारोबार से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को गोपनीय बताया है। संतुष्ट होने पर, अथॉरिटी ने जहां भी जरूरी समझा, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना है तथा उसे अन्य संबंधित पक्षों के सामने उजागर नहीं किया है।
28. आवेदक या डीजीटीआर द्वारा ट्रांज़ैक्शन-वाइज़ डेटा के खुलासे के संबंध में, अथॉरिटी का मानना है कि आवेदक के लिए जरूरी जानकारी में आयात की मात्रा और मूल्य तथा जानकारी का स्रोत शामिल है। नियमों के तहत अथॉरिटी के लिए आयात की मात्रा और कीमत से जुड़ी जानकारी महत्वपूर्ण है। ट्रांज़ैक्शन-वाइज़ डेटा केवल आवेदक द्वारा किए गए दावों की पर्याप्तता और सटीकता के लिए सहायक जानकारी के रूप में काम आता है। इसी तरह, डीजी सिस्टम से इकट्ठा की गई जानकारी का मकसद केवल आयात की मात्रा और मूल्य का पता लगाना है, और इसे मौजूदा डिस्कलोज़र स्टेटमेंट में सही ढंग से बताया गया है। संबंधित पक्षों को जांच और निर्णय से जुड़ी जानकारी पर अपने हितों की रक्षा करने का पर्याप्त मौका मिला है।

च. डंपिंग का आकलन और सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य तथा डंपिंग मार्जिन का निर्धारण

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन

29. विरोधी हितबद्ध पक्षों ने डंपिंग के आकलन तथा सामान्य मूल्य (सामान्य मूल्य), निर्यात मूल्य (निर्यात मूल्य) और डंपिंग मार्जिन (डंपिंग अंतर) के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं।
- i. सदारा केमिकल कंपनी सऊदी अरब से उत्पाद जिसके संबंध में जांच की जा रही है, की एक सहकारी उत्पादक एवं निर्यातक है, जो अपने संबंधित ट्रेडर्स के माध्यम से भारत को निर्यात करती है। यह दावा किया गया है कि डंपिंग मार्जिन का निर्धारण सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए वास्तविक अभिलेखों एवं सूचनाओं के आधार पर किया जाना चाहिए।

- ii. सऊदी अरब के लिए आरोपित डंपिंग मार्जिन (75-85%) अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है और इसका कोई विश्वसनीय आधार नहीं है, क्योंकि यह एक त्रुटिपूर्ण (त्रुटिपूर्ण) सामान्य मूल्य (सामान्य मान) गणना पर आधारित है।
- iii. घरेलू इंडस्ट्री द्वारा बताई गई 'नॉर्मल वैल्यू' असल में बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसे उनके अपने कम कुशल और कम प्रतिस्पर्धी कॉस्ट स्ट्रक्चर के आधार पर तय किया गया है। घरेलू इंडस्ट्री की लागत कई ढांचागत कमियों की वजह से बढ़ी हुई है: यह एक नई कंपनी है (जिसने 2019 में प्रोडक्शन शुरू किया) और इसके पास बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का फ़ायदा (पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं) नहीं है; यह वर्टिकली इंटीग्रेटेड नहीं है और इम्पोर्ट किए गए कच्चे माल (एमईए) पर निर्भर है; और सोलापुर में प्लांट होने के कारण इसे देश के अंदर सामान लाने-ले जाने (इनलैंड लॉजिस्टिक्स) पर काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। यह कॉस्ट स्ट्रक्चर सदारा (Sadara) जैसे कुशल ग्लोबल प्रोड्यूसर के हिसाब से सही नहीं है।
- iv. डंपिंग मार्जिन की गणना, उत्तरदाताओं द्वारा अपने प्रश्नावली के जवाबों में सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के बारे में दिए गए वास्तविक और सत्यापित डेटा के आधार पर की जानी चाहिए।

च.2 आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन

30. आवेदक ने डंपिंग के आकलन तथा सामान्य मूल्य (सामान्य मान), निर्यात मूल्य (निर्यात मूल्य) और डंपिंग मार्जिन (डंपिंग मार्जिन) के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं:
 - i. चीन (पीआरसी) को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए।
 - ii. अगर यह तर्क दिया जाए कि चीन पीआर के एक्सेसियन प्रोटोकॉल का आर्टिकल 15(a)(ii) पहले ही खत्म हो चुका है और इसलिए इसे मौजूदा मामले में लागू नहीं किया जा सकता, तो भी आर्टिकल 15(a)(i) लागू रहता है और चीन पीआर के लिए 'नॉर्मल वैल्यू' तय करने के लिए उस पर विचार किया जाना चाहिए।
 - iii. चीन पीआर के एक्सेसियन प्रोटोकॉल के 15(a)(i) के तहत यह ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट, नियमों के एनेक्शर I के पैरा 8 में बताई गई शर्तों को पूरा करे।
 - iv. चूँकि चीनी उत्पादक बाज़ार अर्थव्यवस्था उपचार (बाज़ार अर्थव्यवस्था उपचार) के लिए पात्र नहीं हैं, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकरण को सामान्य मूल्य (सामान्य मूल्य) के निर्धारण हेतु नियमों के अनुबंध I के पैराग्राफ 7 का पालन करना चाहिए।
 - v. आवेदक वास्तविक बिक्री मूल्य या किसी तीसरे देश की बाज़ार अर्थव्यवस्था में उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं कर सका, क्योंकि वास्तविक बिक्री मूल्य का कोई भी सत्यापन योग्य प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं था।
 - vi. आवेदक किसी तीसरे देश से दूसरे देश (भारत सहित) को बेचे गए सामान की कीमत के आधार पर 'सामान्य मूल्य' तय नहीं कर सका, क्योंकि भले ही संबंधित सामान के लिए भारत में एक खास कोड है, लेकिन दुनिया भर में इसके लिए कोई खास कोड नहीं है।
 - vii. आवेदक ने 'किसी अन्य उचित आधार' के तहत सामान्य मूल्य तय किया था। यह आधार दूसरे देशों को किए गए निर्यात की कीमत (क्योंकि ये निर्यात मात्रा में काफ़ी हैं और इनसे मुनाफ़ा भी होता है) और उचित मुनाफ़े को जोड़कर उत्पादन लागत (जिसमें कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमत को ध्यान में रखा गया था) पर आधारित था।
 - viii. अगर अथॉरिटी को लगता है कि चीन के एक्सेसियन प्रोटोकॉल के आर्टिकल 15 के सभी प्रावधान अब लागू नहीं हैं और नियमों के पैरा 1-6 के अनुसार सामान्य मूल्य तय करने की ज़रूरत है, तो भी चीनी घरेलू लागत और कीमतों

को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक चीनी एक्सपोर्टर कई मानकों को पूरा न कर लें, जैसे कि (i) लागत और कीमतों को तय करने में सरकारी दखल न होना, (ii) मुख्य इनपुट की कीमतें काफी हद तक बाजार मूल्य को दर्शाती हों, (iii) एक्सपोर्टर के खातों की ऑडिटिंग चीनी आम तौर पर स्वीकृत अकाउंटिंग सिद्धांतों (जीएएपी) और अंतरराष्ट्रीय अकाउंटिंग मानकों के अनुसार की गई हो, और (iii) एक्सपोर्टर के संगठनात्मक ढांचे के कारण लागत का उचित होना।

- ix. पूरी कोशिश करने के बाद भी, आवेदक को यूरोपीय संघ में उत्पादकों की वास्तविक लेन-देन कीमत के बारे में कोई सबूत नहीं मिल सका।
- x. आवेदक ने सामान्य मूल्य तय करने के लिए यूरोपीय संघ के अंदर की कीमतों पर विचार किया है; यह वह कीमत है जिस पर उत्पाद का व्यापार यूरोपीय संघ में खपत के लिए किया जाता है।
- xi. ताइवान में उत्पादकों की वास्तविक लेन-देन कीमत के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। चूंकि उस देश में इस उत्पाद के लिए एक खास कोड है, इसलिए आवेदक ने ताइवान में होने वाले आयात के आधार पर सामान्य मूल्य तय किया है।
- xii. सऊदी अरब के मामले में भी, देश में उत्पादकों की वास्तविक लेन-देन कीमत या उत्पादन की वास्तविक लागत के बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि देश में इस उत्पाद के लिए एक खास कोड है, लेकिन कोई प्रकाशित डेटा न होने के कारण, आवेदक ने मार्जिन में उचित बढ़ोतरी के साथ अपनी उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य तय किया है।
- xiii. जांच की अवधि के दौरान, संबंधित देशों के डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन न केवल 'डी-मिनिमस' (न्यूनतम सीमा) से ऊपर हैं, बल्कि अभूतपूर्व रूप से महत्वपूर्ण भी हैं।

च.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

31. प्राधिकरण ने विषय देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली (प्रश्नावली) भेजी, जिसमें उन्हें प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रूप एवं तरीके से सूचना प्रदान करने की सलाह दी गई। विषय देशों के निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने, उनके संबंधित निर्यातकों एवं भारत में आयातकों सहित, निर्धारित प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत किए हैं।

क्र. सं.	हितबद्ध पक्ष का नाम
क.	एम/एस बीएएसएफ एंटवर्पेन एनवी, बेल्जियम
ख.	एम/एस बीएएसएफ ईओओडी, बुल्गारिया
ग.	एम/एस बीएएसएफ एस्पान्योला एसएलयू, स्पेन
घ.	एम/एस बीएएसएफ फ्रांस एस.ए.एस., फ्रांस
ङ.	एम/एस बीएएसएफ हांगकांग लिमिटेड, हांगकांग
च.	एम/एस बीएएसएफ हंगारिया केएफटी., हंगरी
छ.	एम/एस बीएएसएफ-वाईपीसी कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर
ज.	एम/एस बीएएसएफ आयरलैंड डीएसी, आयरलैंड
झ.	एम/एस बीएएसएफ इटालिया एस.पी.ए., इटली

अ.	एम/एस बीएएसएफ नेदरलैंड बी.वी., नीदरलैंड्स
ट.	एम/एस बीएएसएफ एसई, जर्मनी
ठ.	एम/एस बीएएसएफ स्पोल एस.आर.ओ., चेक गणराज्य
ड.	एम/एस बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड, भारत
ढ.	एम/एस डॉव केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, दुबई शाखा, यूएई
ण.	एम/एस डॉव सऊदी अरबिया प्रोडक्ट मार्केटिंग अरेबिया बी.वी., दुबई शाखा, यूएई
त.	एम/एस डॉव केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, दुबई शाखा

32. विषय देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य (सामान्य मान) और निर्यात मूल्य (निर्यात मूल्य) निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं,

च.4 सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य का निर्धारण

क. चीन पीआर से सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य।

- सामान्य मान

33. WTO में चीन के शामिल होने से जुड़े प्रोटोकॉल का आर्टिकल 15 इस प्रकार है:

गैट 1994 का आर्टिकल VI, 'टैरिफ और ट्रेड पर जनरल एग्रीमेंट 1994' के आर्टिकल VI को लागू करने का एग्रीमेंट ("एंटी-डंपिंग एग्रीमेंट") और एससीएम एग्रीमेंट, WTO के किसी सदस्य देश में चीन से होने वाले इंपोर्ट से जुड़ी कार्यवाही में नीचे दी गई बातों के अनुसार लागू होंगे:

(क) गैट 1994 के आर्टिकल VI और एंटी-डंपिंग एग्रीमेंट के तहत कीमत की तुलना तय करते समय, आयात करने वाला विश्व व्यापार संगठन सदस्य या तो जांच के दायरे में आने वाली इंडस्ट्री के लिए चीनी कीमतों या लागतों का इस्तेमाल करेगा, या फिर ऐसी कार्यप्रणाली अपनाएगा जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित न हो; और यह सब निम्नलिखित नियमों के आधार पर किया जाएगा:

(i) अगर जांच के दायरे में आने वाले उत्पादक यह साफ तौर पर दिखा सकें कि उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के मामले में, उसी तरह का उत्पाद बनाने वाली इंडस्ट्री में मार्केट इकॉनमी की स्थितियां मौजूद हैं, तो आयात करने वाला विश्व व्यापार संगठन सदस्य देश, कीमतों की तुलना करने के लिए जांच के दायरे में आने वाली इंडस्ट्री के मामले में चीनी कीमतों या लागत का इस्तेमाल करेगा;

(ii) अगर जांच के दायरे में आने वाले प्रोड्यूसर यह साफ तौर पर नहीं दिखा पाते हैं कि उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और बिक्री के मामले में, उस प्रोडक्ट को बनाने वाली इंडस्ट्री में मार्केट इकॉनमी की स्थितियां मौजूद हैं, तो इंपोर्ट करने वाला विश्व व्यापार संगठन सदस्य ऐसी कार्यप्रणाली अपना सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित न हो।

(ख) एससीएम समझौते (एससीएम समझौता) के भाग II, III और V के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों में, जब अनुच्छेद 14(a), 14(b), 14(c) और 14(d) में वर्णित सब्सिडी (सब्सिडी) पर विचार किया जाता है, तो एससीएम समझौते के संबंधित प्रावधान लागू होंगे; तथापि, यदि इन प्रावधानों के अनुप्रयोग में विशेष कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, तो आयात करने वाला विश्व व्यापार संगठन सदस्य सब्सिडी लाभ (सब्सिडी का लाभ) की पहचान और मापन के लिए ऐसी कार्यप्रणालियाँ अपना सकता है, जो इस संभावना को ध्यान में

रखें कि चीन में प्रचलित शर्तें और परिस्थितियाँ हमेशा उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी कार्यप्रणालियों को लागू करते समय, जहाँ व्यावहारिक हो, आयात करने वाला विश्व व्यापार संगठन सदस्य चीन के बाहर प्रचलित शर्तों और परिस्थितियों का उपयोग करने से पहले चीन में प्रचलित शर्तों और परिस्थितियों को समायोजित (समायोजित करना) करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला विश्व व्यापार संगठन सदस्य, उप-पैराग्राफ (a) के अनुसार इस्तेमाल किए गए तरीकों की जानकारी 'एंटी-डॉपिंग प्रैक्टिस कमेटी' को देगा और उप-पैराग्राफ (b) के अनुसार इस्तेमाल किए गए तरीकों की जानकारी 'सब्सिडी और काउंटरवेलिंग मेज़र्स कमेटी' को देगा।

(घ) जब चीन, आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत, यह स्थापित कर लेता है कि वह एक बाज़ार अर्थव्यवस्था (बाज़ार अर्थव्यवस्था) है, तो उप-अनुच्छेद (a) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि उस आयातक सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्रवेश (परिग्रहण) की तिथि पर बाज़ार अर्थव्यवस्था के मानदंड (मानदंड) शामिल हों। किसी भी स्थिति में, उप-अनुच्छेद (a)(ii) का प्रावधान प्रवेश की तिथि के 15 वर्षों बाद समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि चीन, आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसार यह स्थापित करता है कि किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र में बाज़ार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियाँ प्रचलित हैं, तो उप-अनुच्छेद (a) के गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था (गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था) संबंधी प्रावधान उस उद्योग या क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे।

34. आवेदक ने चीन के 'एक्सेशन प्रोटोकॉल' के आर्टिकल 15(a)(i) और 'एनेक्शर I' के पैरा 7 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि चीन पीआर में संबंधित प्रोडक्ट बनाने वाले प्रोड्यूसर्स को यह साबित करना चाहिए कि उनके उद्योग में मार्केट इकॉनमी की स्थितियाँ मौजूद हैं, खासकर उस प्रोडक्ट के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के मामले में जिस पर विचार किया जा रहा है। आवेदकों का कहना है कि अगर जवाब देने वाले चीनी प्रोड्यूसर्स यह साबित नहीं कर पाते हैं कि उनकी लागत और कीमत की जानकारी मार्केट-आधारित है, तो 'नॉर्मल वैल्यू' की गणना नियमों के 'एनेक्शर-I' के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।
35. यह ध्यान दिया गया है कि जहाँ अनुच्छेद 15 (a)(ii) में दिया गया प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गया है, वहीं विश्व व्यापार संगठन एंटी-डॉपिंग समझौते के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान और एक्सेसियन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(a)(i) के तहत दायित्व के अनुसार, मार्केट इकॉनमी ट्रीटमेंट का दावा करने के लिए सप्लीमेंट्री प्रश्नावली में दी जाने वाली जानकारी/डेटा के माध्यम से नियमों के एनेक्शर I के पैराग्राफ 8 में बताए गए मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। यह ध्यान दिया गया है कि चूंकि चीन PR के जवाब देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने सप्लीमेंट्री प्रश्नावली का जवाब नहीं दिया है, इसलिए नियमों के एनेक्शर I के पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के अनुसार सामान्य मूल्य की गणना करना आवश्यक है, जो इस प्रकार है:

नॉन-मार्केट इकॉनमी वाले देशों से इंपोर्ट के मामले में, नॉर्मल वैल्यू का पता मार्केट इकॉनमी वाले किसी तीसरे देश में कीमत या अनुमानित वैल्यू के आधार पर लगाया जाएगा, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को की गई बिक्री की कीमत के आधार पर, या जहाँ ऐसा करना संभव न हो, वहाँ किसी अन्य उचित आधार पर—जिसमें भारत में उसी तरह के प्रोडक्ट के लिए वास्तव में चुकाई गई या चुकाने योग्य कीमत शामिल हो सकती है (और ज़रूरत पड़ने पर उचित प्रॉफ़िट मार्जिन शामिल करने के लिए उसमें उचित बदलाव किया जा सकता है)—तय किया जाएगा। संबंधित देश और प्रोडक्ट के विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए, डेज़िग्रेटेड अथॉरिटी उचित तरीके से मार्केट इकॉनमी वाले किसी तीसरे देश का चयन करेगी और चयन के समय उपलब्ध किसी भी विश्वसनीय जानकारी को ध्यान में रखेगी। साथ ही, समय-सीमा के भीतर, यदि किसी अन्य मार्केट इकॉनमी वाले तीसरे देश के संबंध में इसी तरह के

मामले में कोई जांच की गई हो, तो उसे भी उचित होने पर ध्यान में रखा जाएगा। जांच में शामिल पक्षों को मार्केट इकोनॉमी वाले तीसरे देश के उक्त चयन के बारे में बिना किसी अनुचित देरी के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणी देने के लिए उचित समय दिया जाएगा।”

36. पैरा 7 में 'सामान्य मूल्य' (सामान्य मान) तय करने के लिए एक क्रम (पदानुक्रम) बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण इन आधारों पर किया जाएगा: मार्केट इकोनॉमी वाले किसी तीसरे देश में कीमत या 'कन्स्ट्रक्टेड वैल्यू' (निर्मित मूल्य); या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को की गई बिक्री की कीमत; या यदि ये संभव न हो, तो किसी भी उचित आधार पर—जिसमें भारत में उसी तरह की वस्तु के लिए वास्तव में चुकाई गई या देय कीमत शामिल हो सकती है (और यदि जरूरी हो, तो उचित मुनाफ़े के मार्जिन को शामिल करने के लिए उसमें उचित समायोजन/एडजस्टमेंट किया जा सकता है)। इस प्रकार, अथॉरिटी का मानना है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण पैरा 7 में दिए गए विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।
37. अथॉरिटी यह भी नोट करती है कि नॉन-मार्केट इकोनॉमी के मामले में 'नॉर्मल वैल्यू' तय करने से जुड़े मौजूदा कानूनी सिद्धांत कई फैसलों में दिए गए हैं। ये फैसले नियमों के एनेक्ज़र 1 के पैरा 7 को लागू करने के बारे में निर्देश देते हैं, जिसमें सही विकल्प चुनने और उससे जुड़ी जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है।
38. अथॉरिटी का कहना है कि किसी भी इच्छुक पक्ष ने किसी उपयुक्त मार्केट-इकोनॉमी वाले तीसरे देश में प्रोडक्ट की घरेलू कीमत या अनुमानित कीमत (निर्मित मूल्य) के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अथॉरिटी यह भी कहती है कि उसे इच्छुक पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई जानकारी और सबूतों के आधार पर एक उपयुक्त देश चुनना है। यह दावा किया गया है कि जिस प्रोडक्ट पर विचार किया जा रहा है, उसके लिए ज़्यादातर देशों में कोई खास कोड नहीं है। चूंकि ज़्यादातर देशों में इस प्रोडक्ट के लिए कोई खास कोड नहीं है, इसलिए अथॉरिटी ने इस आधार पर सामान्य मूल्य (सामान्य मान) तय नहीं किया है।
39. अथॉरिटी ने चीन (पीआर) के लिए 'सामान्य मूल्य' (सामान्य मान) का निर्धारण भारत में उसी तरह की वस्तु के लिए वास्तव में चुकाई गई या चुकाने योग्य कीमत के आधार पर किया है। यह सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत को ध्यान में रखकर तय किया गया है; इसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों तथा उचित मुनाफ़े को जोड़कर और जरूरी समायोजन (समायोजन) करके इसे निकाला गया है। इस तरह तय किया गया 'निर्मित सामान्य मूल्य' (निर्मित सामान्य मूल्य) डंपिंग मार्जिन टेबल में दिया गया है।

• निर्यात मूल्य

बीएसएफ - वाईपीसी कंपनी लिमिटेड

40. बीएसएफ - वाईपीसी कंपनी लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद की निर्माता है और उसने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** MT निर्यात किया है। निर्माता ने दावा किया है कि उसने संबंधित ट्रेडर के माध्यम से संबंधित भारतीय ग्राहक को उत्पाद का अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात किया, जिसने इसे आगे गैर-संबंधित भारतीय ग्राहकों को बेच दिया। निर्माता ने समुद्री माल-भाड़े, देश के भीतर परिवहन आदि के आधार पर समायोजन का दावा किया है।
41. अथॉरिटी ने डेस्क वेरिफिकेशन किया है और प्रतिवादी द्वारा किए गए दावों की जांच की है। डेस्क वेरिफिकेशन के बाद प्रतिवादी द्वारा किए गए एडजस्टमेंट को मंजूरी दे दी गई है। इस तरह तय की गई नेट एक्सपोर्ट प्राइस नीचे डंपिंग मार्जिन टेबल में दी गई है।

चीन (पीआर) के सहयोग न करने वाले उत्पादक

42. अथॉरिटी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सहयोग न करने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के लिए नेट एक्सपोर्ट प्राइस तय किया है। तय किया गया एक्स-फैक्ट्री एक्सपोर्ट प्राइस नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन टेबल में दिखाया गया है।

ख. यूरोपीय संघ से सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य

बीएसएफ एंटरप्रेन एनवी और उससे जुड़े ट्रेडर (जिन्हें बीएसएफ ग्रुप कहा जाता है)

• **सामान्य मान**

43. बीएसएफ एंटरप्रेन एनवी यूरोपीय संघ में संबंधित सामान का उत्पादक है। उत्पादक ने अपने संबंधित निर्यातकों और आयातक के साथ मिलकर, ज़रूरी जानकारी देते हुए निर्यातक प्रश्नावली का जवाब जमा किया है। अथॉरिटी ने देखा है कि उत्पादक/निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान संबंधित ग्राहकों को *** मीट्रिक टन की घरेलू बिक्री की जानकारी दी है; इन ग्राहकों ने इसे या तो गैर-संबंधित ग्राहकों को फिर से बेचा या खुद इस्तेमाल किया।
44. सामान्य मूल्य तय करने के लिए, अथॉरिटी ने संबंधित सामान की उत्पादन लागत के आधार पर मुनाफ़ा कमाने वाले घरेलू बिक्री लेन-देन का पता लगाने के लिए 'सामान्य व्यापार प्रक्रिया' (ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ़ ट्रेड) का टेस्ट किया। अगर मुनाफ़ा कमाने वाले लेन-देन 80% से ज़्यादा हैं, तो अथॉरिटी ने सामान्य मूल्य तय करने के लिए घरेलू बाज़ार में हुए सभी लेन-देन को ध्यान में रखा है। जहाँ मुनाफ़े वाले लेन-देन 80% से कम हैं, वहाँ सामान्य मूल्य तय करने के लिए सिर्फ़ मुनाफ़े वाली घरेलू बिक्री को ही ध्यान में रखा जाता है। 'सामान्य व्यापार प्रक्रिया' टेस्ट के आधार पर यह देखा गया है कि संबंधित उत्पादक इस टेस्ट में सफल नहीं हो पाया है क्योंकि बिक्री का *** हिस्सा ही मुनाफ़ा कमाने वाला है, और इसलिए, अथॉरिटी ने इस मामले में मुनाफ़े वाले लेन-देन के आधार पर सामान्य मूल्य तय करना सही समझा है।
45. अथॉरिटी ने डेस्क वेरिफिकेशन किया है और प्रतिवादी द्वारा किए गए दावों की जांच की है, जिसमें इनलैंड फ्रेट, ओशन फ्रेट आदि से संबंधित एडजस्टमेंट शामिल हैं। डेस्क वेरिफिकेशन के बाद सत्यापित दावों को स्वीकार कर लिया गया है। इस तरह तय की गई सामान्य वैल्यू नीचे डंपिंग मार्जिन टेबल में दी गई है।

• **निर्यात मूल्य**

46. बीएसएफ एंटरप्रेन एनवी, यूरोपीय संघ में विचाराधीन उत्पाद का निर्माता है। बीएसएफ एंटरप्रेन एनवी ने इस उत्पाद का निर्यात सीधे संबंधित आयातक को और अपने संबंधित निर्यातकों - जैसे बीएसएफ बेल्जियम कोऑर्डिनेशन सेंटर कॉमबी, बीएसएफ ईओओडी, बीएसएफ एस्पानोला एसएलयू, बीएसएफ ओए, बीएसएफ फ़्रांस एस.ए.एस., बीएसएफ हंगेरिया केएफटी., बीएसएफ आयरलैंड डीएसी, बीएसएफ इटली एस.पी.ए., बीएसएफ नीदरलैंड्स बी.वी., बीएसएफ एस.आर.एल., बीएसएफ स्पोल एस.आर.ओ., बीएसएफ एस ई, बीएसएफ हॉन्ग कॉन्ग लिमिटेड- के माध्यम से किया है। इन संबंधित निर्यातकों ने आगे यह उत्पाद अपने संबंधित आयातक, बीएसएफ इंडिया लिमिटेड को बेचा, जिसने बदले में ये सामान भारत में गैर-संबंधित ग्राहकों को बेचे।
47. बीएसएफ एंटरप्रेन एनवी विचाराधीन उत्पाद की निर्माता है और उसने प्रश्नावली का जवाब दाखिल किया है। निर्माता ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के *** मीट्रिक टन निर्यात की सूचना दी है। निर्माता ने दावा किया है कि उसने संबंधित व्यापारियों के माध्यम से संबंधित भारतीय ग्राहकों को उत्पाद का अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात किया, जिन्होंने इसे असंबद्ध भारतीय ग्राहकों को फिर से बेच दिया। निर्माता ने समुद्री माल-भाड़े, अंतर्देशीय परिवहन आदि के आधार पर समायोजन का दावा किया है।

48. अथॉरिटी ने डेस्क वेरिफिकेशन किया है और प्रतिवादी द्वारा किए गए दावों की जांच की है। डेस्क वेरिफिकेशन के बाद प्रतिवादी द्वारा किए गए एडजस्टमेंट को मंजूरी दे दी गई है। इस तरह तय की गई नेट एक्सपोर्ट प्राइस नीचे डंपिंग मार्जिन टेबल में दी गई है।

यूरोपीय संघ के सहयोग न करने वाले उत्पादक।

49. प्राधिकरण ने गैर-सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों (असहयोगी उत्पादक/निर्यातक) के लिए उपलब्ध तथ्यों (उपलब्ध तथ्य) के आधार पर शुद्ध निर्यात मूल्य (शुद्ध निर्यात मूल्य) निर्धारित किया है। निर्धारित किया गया एक्स-फैक्ट्री निर्यात मूल्य नीचे दिए गए डंपिंग मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ग. सऊदी अरब से सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य

सदारा केमिकल कंपनी, डाउ केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, दुबई ब्रांच, डाउ सऊदी अरब प्रोडक्ट मार्केटिंग अरेबिया बी.वी., डाउ केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

• सामान्य मान

50. सदारा केमिकल कंपनी ("सदारा") सऊदी अरब में उत्पाद जिसके संबंध में जांच की जा रही है, की उत्पादक है। सदारा ने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली (निर्यातक प्रश्नावली) प्रारूप में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हुए आवश्यक जानकारी प्रदान की है। प्राधिकरण ने नोट किया है कि जांच अवधि (पीओआई) के दौरान सदारा ने घरेलू बाजार में केवल एक घरेलू बिक्री लेन-देन (घरेलू बिक्री का लेन-देन) किया था, जो *** मीट्रिक टन (मीट्रिक टन) ऑफ-ग्रेड (बंद ग्रेड) उत्पाद का था और एक असंबंधित ग्राहक को किया गया था। चूंकि यह एकमात्र घरेलू बिक्री लेन-देन ऑफ-ग्रेड गुणवत्ता का था तथा मात्रा में पर्याप्त नहीं था, इसलिए इसे सामान्य मूल्य (सामान्य मान) के निर्धारण के लिए विचार में नहीं लिया जा सकता।
51. ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, अथॉरिटी ने जांच के दौरान उचित मुनाफ़े के मार्जिन को जोड़कर 'नॉर्मल वैल्यू' तय की है। यह वैल्यू जांच के तहत आने वाले प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट के आधार पर तय की गई है, जिसकी जानकारी सदारा (सदारा) ने अपेंडिक्स-8 में दी थी और जांच के दौरान जिसकी ठीक से पुष्टि की गई थी। इस तरह तय की गई 'नॉर्मल वैल्यू' का ज़िक्र डंपिंग मार्जिन टेबल में किया गया है।

• निर्यात मूल्य

52. सदारा केमिकल कंपनी सऊदी अरब में विचाराधीन उत्पाद की निर्माता है। पीओआई के दौरान, सदारा ने संबंधित निर्यातक, डाउ सऊदी अरब प्रोडक्ट मार्केटिंग अरेबिया बी.वी. ("डाउ मार्केटिंग) को संबंधित सामान बेचा। इसके बाद, डाउ मार्केटिंग ने वह सामान एक अन्य संबंधित ट्रेडर, डाउ केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, दुबई ब्रांच ("डाउ सिंगापुर) को बेचा। बाद में, डाउ सिंगापुर ने वह सामान भारत में संबंधित आयातक, डाउ केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ("डी.सी.आई.पी.एल इंडिया") को बेचा। अंत में, डी.सी.आई.पी.एल इंडिया ने वह सामान भारत में गैर-संबंधित ग्राहकों को बेचा।
53. डाउ मार्केटिंग ने डाउ केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, दुबई ब्रांच ("डी.सी.आई.पी.एल दुबई") को भी एक एक्सपोर्ट ट्रांज़ैक्शन किया है। इसके बाद डी.सी.आई.पी.एल दुबई ने संबंधित सामान का यह एक ट्रांज़ैक्शन भारत में एक ऐसे कस्टमर को बेचा है जिसका उनसे कोई संबंध नहीं है। सभी 5 एंटीटी - सदारा, डाउ मार्केटिंग, डाउ सिंगापुर, डी.सी.आई.पी.एल दुबई और डी.सी.आई.पी.एल इंडिया - ने इस जांच में हिस्सा लिया है और तय किए गए सवाल-जवाब के फ़ॉर्मेट में ज़रूरी जानकारी दी है।

54. अथॉरिटी ने डाउ मार्केटिंग, डाउ सिंगापुर और डी.सी.आई.पी.एल दुबई की तरफ से दिए गए जवाबों से यह देखा है कि पीओआई के दौरान, सदारा द्वारा बनाए और एक्सपोर्ट किए गए सामान को डाउ ग्रुप ने कुल मिलाकर मुनाफे पर दोबारा बेचा था।
55. सदारा ने समुद्री माल-भाड़े, बीमा, देश के भीतर परिवहन, बंदरगाह से जुड़े खर्चों, क्रेडिट लागत और मार्केटिंग शुल्क के लिए एडजस्टमेंट का दावा किया। अथॉरिटी ने उचित जांच-पड़ताल के बाद इन एडजस्टमेंट की समीक्षा की और उन्हें मंजूरी दी।
56. इस तरह तय की गई एक्स-फ़ैक्ट्री एक्सपोर्ट कीमत को डंपिंग मार्जिन की गणना के लिए ध्यान में रखा गया है और इसे नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन तालिका में दिखाया गया है।

सऊदी अरब के असहयोगी उत्पादक।

57. अथॉरिटी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सहयोग न करने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के लिए नेट एक्सपोर्ट प्राइस तय किया है। तय किया गया एक्स-फ़ैक्ट्री एक्सपोर्ट प्राइस नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन टेबल में दिखाया गया है

घ. ताइवान से सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य।

58. चूंकि किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने इस जांच में हिस्सा नहीं लिया है, इसलिए ताइवान के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य का निर्धारण एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के नियम 6(8) के तहत उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर किया गया है।

ड. डंपिंग मार्जिन

59. वर्तमान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य (सामान्य मान), निर्यात मूल्य (निर्यात मूल्य) और डंपिंग मार्जिन (डंपिंग मार्जिन) निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	विवरण	सीएनवी/एनवी (यूएसडी/एमटी)	एनईपी (यूएसडी/एमटी)	डंपिंग मार्जिन (यूएसडी/एमटी)	डंपिंग मार्जिन %	डंपिंग मार्जिन सीमा
क.	चीन पीआर					
1	बीएसएफ - वाईपीसी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	40-50
ख.	यूरोपीय संघ					
1	बीएसएफ एंटरप्राइस एनवी	***	***	***	***	80-90
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	120-130
ग.	सऊदी अरब					
1	सदारा केमिकल कंपनी	***	***	***	***	10-20
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	20-30

घ.	ताइवान					
1	कोई उत्पादक	***	***	***	***	30-40

छ. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध

छ.1 अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुति

60. विपक्षी हित-धारकों ने नुकसान के आकलन और कारण-संबंध के बारे में निम्नलिखित बातें कही हैं:

- i. आयात केवल मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए बढ़ाए गए हैं, जबकि आवेदक के उत्पादन और बिक्री में कमी उनकी परिचालन संबंधी अक्षमताओं के कारण है।
- ii. डाउनस्ट्रीम यूजर्स मुख्य रूप से घरेलू सप्लाई में कमी के कारण इंपोर्ट पर निर्भर हैं, न कि कीमत की प्राथमिकता के कारण। जांच की अवधि के दौरान एप्लिकेंट की कम क्षमता के इस्तेमाल और बीच-बीच में प्रोडक्शन रुकने की वजह से यूजर्स के पास दूसरे देशों से संबंधित प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
- iii. ईडीए एक मानकीकृत वस्तु है जिसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव अमोनिया और मोनोएथेनॉलमाइन (एमईए) जैसे प्रमुख कच्चे माल में होने वाले उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। आयातित और घरेलू उत्पादों के बीच आवधिक मूल्य अंतर बाजार-प्रेरित होते हैं और इन्हें मूल्यह्रास नहीं माना जा सकता।
- iv. आवेदक की लागत संरचना अधिक होने का कारण उसकी अपनी अक्षमताएं और कच्चे माल के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भरता है। आयात की कम कीमतें वैश्विक उत्पादकों के 'बैकवर्ड इंटीग्रेशन' को दर्शाती हैं, न कि नुकसान पहुंचाने वाली कीमतों को।
- v. 2023-24 और पीओआई के दौरान कीमतों में आई गिरावट, विचाराधीन उत्पाद की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आई गिरावट के साथ मेल खाती है।
- vi. विचाराधीन प्रोडक्ट की कीमतें ग्लोबल सप्लाई और डिमांड से तय होती हैं। चीन और यूरोपीय संघ में प्लांट बंद होने के कारण 2021-22 और 2022-23 में कीमतें बढ़ीं और प्रोडक्शन सामान्य होने पर 2023-24 में कीमतें गिर गईं। आवेदक की कीमतों में आई गिरावट इसी ग्लोबल ट्रेंड के अनुरूप है, और इस पर इम्पोर्ट का कोई असर नहीं पड़ा है।
- vii. आवेदक ने माना कि 2022-23 में उत्पादन में बढ़ोतरी ज़्यादा एक्सपोर्ट की वजह से हुई थी, और उसके बाद उत्पादन में आई कमी किसी संरचनात्मक अक्षमता के बजाय एक रणनीतिक फैसले का नतीजा है।
- viii. आवेदक ने उचित कीमतों पर "राजस्व के नुकसान" का भी जिक्र किया है। यह हिसाब-किताब काल्पनिक है और इसके समर्थन में कोई विस्तृत गणना या सत्यापित डेटा नहीं दिया गया है।
- ix. अलग-अलग देशों से होने वाले आयात की लैंडेड कीमत में काफी अंतर दिखता है; सबसे ज़्यादा और सबसे कम कीमत के बीच लगभग 17,000 रुपये प्रति MT का अंतर है, जिससे पता चलता है कि आयात एक जैसी कीमत पर मुकाबला नहीं करते हैं।
- x. आवेदक की क्षमता का उपयोग तेज़ी से घटा, जिससे प्रति-इकाई निश्चित लागत बढ़ गई।
- xi. इस अवधि के दौरान कच्चे माल की कीमतों में काफी बदलाव आया, जिससे लागत मार्जिन में भी बदलाव हुआ।
- xii. 2023-24 के चेयरमैन के भाषण में जियोपॉलिटिकल तनाव, सप्लाई चेन में रुकावट और जलवायु से जुड़े जोखिमों जैसी चुनौतियों पर ज़ोर दिया गया, लेकिन डंपिंग को एक बड़ी चिंता के तौर पर नहीं बताया गया।

- xiii. आवेदक पूरी तरह से आयातित मोनोएथेनॉलमाइन (एम ई ए) पर निर्भर है, जिसकी कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे होती रहती हैं। इस निर्भरता और कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण आवेदक की इनपुट और इन्वेंट्री लागत काफी बढ़ गई है। दुनिया भर के उन उत्पादकों के विपरीत जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हैं, आवेदक एक नॉन-इंटीग्रेटेड प्लांट चलाता है, जिससे उसे लागत के मामले में काफी नुकसान उठाना पड़ता है।
- xiv. महाराष्ट्र के सोलापुर में आवेदक की सुविधा बंदरगाहों और पेट्रोकेमिकल हब से दूर है, जिसके कारण लॉजिस्टिक्स और इनलैंड फ्रेट (देश के भीतर माल ढुलाई) की लागत ज़्यादा आती है; इससे आयात से अलग, उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है।
- xv. आवेदक ने जून 2019 में ही कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया। नुकसान की अवधि उसके कामकाज के शुरुआती सालों से मेल खाती है, जिसमें प्रोसेस को स्थिर करने, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने और सप्लाय चैन बनाने जैसी शुरुआती कमियां शामिल थीं।
- xvi. एथिलीन डायमाइन की ज़्यादा लागत एग्रीकेमिकल सेक्टर में निवेश और इनोवेशन पर असर डालेगी, जिससे ग्लोबल लेवल पर भारत की कॉम्पिटिटिवनेस कमज़ोर होगी।
- xvii. इस मामले में, जापान, यूएसए और कोरिया आरपी जैसे देशों का अलग-अलग हिस्सा 3% से कम है, लेकिन उनका कुल हिस्सा 7.28% है, जो तय सीमा से ज़्यादा है। इसलिए, इन देशों को जांच में शामिल किया जाना चाहिए था।
- xviii. इन देशों को बाहर रखना भेदभाव है, यह विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के खिलाफ है और किसी भी एंटी-डंपिंग उपाय की प्रभावशीलता को कम करता है।
- xix. आवेदक को कथित तौर पर हुए किसी भी नुकसान का मुख्य कारण चीन (पीआर) से होने वाला आयात है, न कि सऊदी अरब से।
- xx. नुकसान के विश्लेषण में सभी ज़रूरी आर्थिक कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें आवेदक का निर्यात प्रदर्शन भी शामिल है। जांच की अवधि के दौरान आवेदक के निर्यात की मात्रा में कमी आई है। निर्यात की कीमतों में भी 35% की गिरावट आई है, जो अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में भारी दबाव का संकेत है।
- xxi. जांच की अवधि के दौरान वेतन और मजदूरी 2021-22 की तुलना में 2.4 गुना से अधिक हैं।
- xxii. इसी अवधि में लगाई गई पूंजी में 13% की वृद्धि हुई है, जबकि क्षमता का कोई विस्तार नहीं हुआ है।
- xxiii. संबंधित देशों पर लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क से केवल उन देशों को फ़ायदा होगा जिन पर ये शुल्क नहीं लगाए गए हैं, और इससे आवेदन करने वाले को कोई खास राहत नहीं मिलेगी। घरेलू मांग और आपूर्ति के बीच काफ़ी अंतर है, इसलिए आयात करना ज़रूरी है।
- xxiv. जापान, यूएसए, कोरिया आर पी, सिंगापुर और यूई जैसे देशों से मिलने वाली कीमतें तुलना करने लायक या उनसे भी ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हैं। इसका मतलब है कि जिन देशों पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, उनसे होने वाले आयात पर कोई भी रोक लगाने से सिर्फ़ आयात का स्रोत बदल जाएगा, लेकिन कीमतों पर दबाव कम नहीं होगा।
- xxv. काम या ज़िम्मेदारियों के बावजूद, आवेदक को वैसी ही प्रतिस्पर्धी चुनौतियों का सामना करना जारी रहेगा।
- xxvi. घरेलू उद्योग का नुकसान होने का दावा बेबुनियाद है और यह नुकसान के बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए मार्जिन (सऊदी अरब के लिए 50-60% होने का दावा) पर आधारित है, जो एक गलत आधार से निकाला गया है।

- xxvii. चोट या नुकसान का पूरा विश्लेषण 'नॉन-इंजुरियस प्राइस' (एन आई पी) पर आधारित है, जो अनुचित और कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया है। दावा किया गया एन आई पी, सभी एक्सपोर्ट करने वाले देशों (जिनमें वे देश भी शामिल हैं जिन पर जांच लागू नहीं है) से होने वाले इम्पोर्ट की 'लैंडेड प्राइस' से काफी ज़्यादा है।
- xxviii. इससे यह साबित होता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत असल में अव्यावहारिक है और उस पर वित्तीय दबाव आयात से मिलने वाली निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं, बल्कि उसकी अपनी संरचनात्मक कमियों का नतीजा है।
- xxix. इसके अलावा, जो भी नुकसान हुआ है, वह खुद की वजह से हुआ है। 2021-22 की तुलना में पी ओ आई के दौरान डी आई का सैलरी और वेज पर खर्च लगभग 2.5 गुना बढ़ गया और उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड में 13% की बढ़ोतरी हुई, जबकि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में कोई बदलाव नहीं हुआ और प्रोडक्शन घट गया। लागत में यह बेहिसाब और संदिग्ध बढ़ोतरी उसके फाइनेंशियल दबाव का मुख्य कारण है और इसकी जांच होनी चाहिए।
- xxx. सऊदी अरब से होने वाले आयात और कथित नुकसान के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। नुकसान की अवधि के दौरान सऊदी अरब से आयात की मात्रा 20% से ज़्यादा कम हुई है – यह 2021-22 में 13,587 मीट्रिक टन से घटकर पी ओ आई में 10,773 मीट्रिक टन हो गई है।
- xxxi. भारत के कुल आयात में सऊदी अरब से होने वाले आयात की हिस्सेदारी भी 2021-22 के 42.01% से घटकर पी ओ आई में 25.27% रह गई है।
- xxxii. नुकसान की असल वजह चीन (पी आर) से होने वाले आयात में भारी बढ़ोतरी है; नुकसान की अवधि के दौरान यह आयात सात गुना से ज़्यादा बढ़ गया और अब यह आयात का सबसे बड़ा स्रोत (36.50% हिस्सेदारी) बन गया है। संबंधित देश से आयात में हुई पूरी बढ़ोतरी के लिए सिर्फ चीन (पी आर) ही जिम्मेदार है।
- xxxiii. भारत में ईडीए के लिए मांग और आपूर्ति के बीच एक बड़ा और बढ़ता हुआ अंतर है। घरेलू उद्योग की क्षमता इतनी नहीं है कि वह मांग का आधा हिस्सा भी पूरा कर सके, इसलिए डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए आयात करना ज़रूरी हो जाता है।
- xxxiv. घरेलू उद्योग की अपनी निर्यात बिक्री की मात्रा और कीमतों में आई भारी गिरावट यह संकेत देती है कि कीमतों पर दबाव का कारण वैश्विक कीमतों में गिरावट है, न कि सऊदी अरब से डंप किया गया आयात।

छ.2 आवेदक द्वारा प्रस्तुति

61. आवेदक ने चोट के आकलन और कारण-संबंध के बारे में निम्नलिखित बातें कही हैं:

- i. चीन में उत्पादकों ने अपनी घरेलू मांग से ज़्यादा क्षमता स्थापित की है। यह अतिरिक्त उत्पादन क्षमता भारतीय बाज़ार की कुल मांग से भी अधिक है, जिससे पता चलता है कि इसे निर्यात के लिए विकसित किया गया है।
- ii. चीन और ताइवान से बहुत ज़्यादा और आक्रामक तरीके से हो रहे इंपोर्ट का पैटर्न साफ़ दिखाता है कि उनका बिज़नेस मॉडल अनुचित व्यापार तरीकों से दूसरे देशों के बाज़ार पर कब्ज़ा करना है, और अगर एंटी-डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई गई, तो उनकी अतिरिक्त क्षमता भारत की ओर मोड़ दी जाएगी।
- iii. इस मामले में कुल मिलाकर किए जाने वाले मूल्यांकन (संचयी मूल्यांकन) की कानूनी ज़रूरतें पूरी होती हैं। चूंकि किसी भी विरोधी पक्ष ने इस तरह के मूल्यांकन पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, इसलिए अथॉरिटी से अनुरोध है कि वह आयात के प्रभावों के कुल मूल्यांकन पर विचार करे।

- iv. संबंधित देशों से विचाराधीन उत्पाद के डंप किए गए आयात की मात्रा में काफी बढ़ोतरी हुई है। नुकसान की अवधि के दौरान मांग में हुई बढ़ोतरी की तुलना में संबंधित देशों से आयात में कहीं ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है।
- v. आयात की कीमत में बदलाव, उत्पादन लागत में हुए बदलाव के हिसाब से नहीं हुआ है। भारतीय बाज़ार पर कब्ज़ा करने के लिए निर्यातकों ने लागत में हुई कमी से कहीं ज़्यादा अपनी कीमतें कम की हैं।
- vi. कम कीमत वाले आयात की भारी आवक के कारण, घरेलू उद्योग अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, जबकि उसके पास घरेलू मांग का 60% पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता मौजूद है।
- vii. दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की कीमत भारतीय बाज़ार की कीमतों से ज़्यादा है। संबंधित देशों के प्रोड्यूसर चुनिंदा डंपिंग करते हैं और दूसरे एक्सपोर्ट बाज़ारों की तुलना में भारतीय बाज़ार में कम कीमतें ऑफ़र करते हैं।
- viii. भारतीय बाज़ार में एथिलीन डाई-अमाइन की कीमतें न तो भारत में विदेश मंत्रालय के आयात मूल्य को दर्शाती हैं और न ही वैश्विक विदेश मंत्रालय कीमतों को। घरेलू उद्योग ने यह भी स्थापित किया है कि भारतीय बाज़ार में कीमतें चुनिंदा रूप से कम हैं।
- ix. घरेलू उद्योग के नुकसान पर बिक्री करने के बावजूद, कीमतों और लागत में काफी हद तक 'अंडरकटिंग' (यानी प्रतिस्पर्धियों से कम कीमत या लागत रखना) देखी जा रही है।
- x. आयात की कीमत घरेलू उद्योग की वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है। डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही हैं।
- xi. घरेलू उद्योग के पास काफी मात्रा में अप्रयुक्त क्षमता मौजूद है।
- xii. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता का उपयोग कम हो गया। नुकसान की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में लगातार गिरावट आई है।
- xiii. बिक्री मूल्य में गिरावट, बिक्री की लागत में आई गिरावट से ज़्यादा थी, जिसके कारण कीमतों में भारी कमी आई और नुकसान हुआ। ऐसा डंपिंग और उससे हुए नुकसान की वजह से हुआ, न कि किसी आंतरिक नुकसान की वजह से।
- xiv. संबंधित देशों से बड़े पैमाने पर डंपिंग के कारण घरेलू उद्योग अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहा है। योगदान नकारात्मक होने की वजह से, घरेलू उद्योग अपनी फिक्स्ड कॉस्ट (स्थिर लागत) भी वसूलने की स्थिति में नहीं है, और इसलिए इस उत्पाद का उत्पादन करने का कोई प्रोत्साहन नहीं है।
- xv. संबंधित देशों से कम कीमत पर होने वाले आयात के कारण घरेलू उद्योग को समय-समय पर अपना उत्पादन रोकना पड़ा है।
- xvi. घरेलू उद्योग का इन्वेंटरी (स्टॉक) काफी बढ़ गया।
- xvii. घरेलू उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। कैश प्रॉफ़िट और निवेश पर रिटर्न में गिरावट आई है।
- xviii. संबंधित देशों से डंप किए गए आयात में वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई।
- xix. संबंधित देशों से डंप किए गए आयात का कुल विकास पर नकारात्मक असर पड़ता है, जिससे घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता प्रभावित होती है।
- xx. घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत घरेलू कीमत से अधिक है और निर्यात से होने वाला लाभ घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को स्थापित करता है।

- xxi. घरेलू उद्योग का लागत ढांचा भारत में मौजूदा बाज़ार की स्थितियों और इनपुट की कीमतों को पूरी तरह से दर्शाता है। हालांकि नुकसान की अवधि के दौरान कच्चे माल की आयात कीमतों में गिरावट आई, लेकिन एथिलीन डार्ड अमीन की आयात कीमत में आई गिरावट, इनपुट की लागत में आई गिरावट से दोगुनी से भी ज़्यादा थी।
- xxii. जब आयात की कीमत ज़्यादा थी, तब घरेलू उद्योग मुनाफ़े में था। आयात की कीमतों में लागत से भी कहीं ज़्यादा असामान्य गिरावट साफ़ तौर पर दिखाती है कि यह विदेशी उत्पादकों की नुकसान पहुँचाने वाली कीमत तय करने की नीति का नतीजा है, न कि घरेलू उद्योग की किसी अंदरूनी अक्षमता का।
- xxiii. इस बात पर कि जापान, यूएसए और कोरिया आर पी का अलग-अलग हिस्सा 3% से कम है, लेकिन उनका कुल हिस्सा तय सीमा से ज़्यादा है। जापान और कोरिया आर पी से होने वाले इंपोर्ट की कीमत ज़्यादा है और वे कुल मांग का सिर्फ़ [4.5%] हिस्सा हैं, जबकि सऊदी अरब का हिस्सा [21%] है; इससे पता चलता है कि नुकसान इन देशों की वजह से हो रहा है, न कि उन देशों की वजह से जो इस दायरे में नहीं आते।
- xxiv. हालांकि डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ का कहना है कि सप्लाय की कमी के कारण वे इम्पोर्ट पर निर्भर हैं, लेकिन घरेलू इंडस्ट्री के पास मांग का एक बड़ा हिस्सा पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। यूज़र्स ने माना है कि इम्पोर्ट मुख्य रूप से विदेशी उत्पादकों द्वारा दी जाने वाली बहुत कम कीमतों के कारण किया गया था। ग्राहक अक्सर इन कम कीमत वाले इम्पोर्ट का इस्तेमाल बातचीत के एक टूल के तौर पर करते थे, ताकि घरेलू इंडस्ट्री पर कीमतें टिकाऊ स्तर से नीचे लाने का दबाव बनाया जा सके।
- xxv. इस बात पर कि घरेलू इंडस्ट्री की कीमतों में बदलाव ग्लोबल ट्रेंड्स के हिसाब से नहीं हैं, यह कहा गया है कि नुकसान वाली अवधि के दौरान इम्पोर्ट की लैंडेड कीमत में प्रति मीट्रिक टन 1,46,778 रुपये की भारी गिरावट आई, जबकि विदेश मंत्रालय इम्पोर्ट की कीमतों में प्रति मीट्रिक टन केवल 25,338 रुपये की कमी हुई, जिससे घरेलू इंडस्ट्री को अपनी कीमतें कम करने और नुकसान उठाने पर मजबूर होना पड़ा।
- xxvi. यह आरोप लगाया जाता है कि घरेलू उद्योग की लागत संरचना (लागत संरचना) के ऊंचे होने का कारण अक्षमताएं और बैकवर्ड इंटीग्रेशन की कमी है। हालांकि, यह लागत संरचना भारत में मौजूदा बाज़ार की स्थितियों और इनपुट की कीमतों को दर्शाती है। यदि उच्च लागत संरचना नुकसान का कारण होती, तो घरेलू उद्योग को जांच की अवधि से पहले ही नुकसान उठाना पड़ता।
- xxvii. इस तर्क पर कि "रेवेन्यू का नुकसान" काल्पनिक है, एंटी-डंपिंग नियमों के तहत, डंप किए गए इम्पोर्ट के बुरे असर का आकलन असल और संभावित बिक्री में गिरावट के आधार पर किया जाना चाहिए, और कानून बिक्री की मात्रा और मूल्य के बीच कोई अंतर नहीं करता है।
- xxviii. जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग को रुपये [***] करोड़ का वास्तविक नुकसान हुआ, क्योंकि उचित कीमतों पर रुपये [***] करोड़ की संभावित बिक्री के मुकाबले वास्तविक बिक्री रुपये [***] करोड़ तक ही सीमित रही।
- xxix. इस तर्क के जवाब में कि घरेलू उद्योग को नुकसान ज़्यादा लॉजिस्टिक्स और स्टार्ट-अप लागत की वजह से हुआ है, यह कहा जाता है कि ये हालात नुकसान वाली अवधि के दौरान भी बने रहे। ये कारक पहले के सालों में भी मौजूद थे, जब घरेलू उद्योग स्थिर और मुनाफ़े वाला बना रहा।
- xxx. इस दावे के जवाब में कि सालाना रिपोर्ट घरेलू उद्योग पर असर डालने वाली दूसरी चुनौतियों को उजागर करती है, यह कहा जाता है कि 2024-25 की सालाना रिपोर्ट में साफ़ तौर पर बताया गया है

कि डंप किए गए इंपोर्ट की वजह से घरेलू उद्योग के कामकाज पर असर पड़ा। इसलिए, इस नुकसान की वजह कोई और कारक नहीं हो सकता।

- xxxi. इस तर्क पर कि सैलरी और मज़दूरी बढ़ गई हैं और यही नुकसान का कारण हैं: जांच की अवधि के दौरान सैलरी और मज़दूरी 2023-24 की तुलना में कम थीं (जब घरेलू इंडस्ट्री ने मुनाफ़ा कमाया था), इसलिए नुकसान के लिए सिर्फ़ सैलरी और मज़दूरी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
- xxxii. यह कहना गलत है कि बिना किसी विस्तार के भी इस्तेमाल की गई क्षमता बढ़ गई, क्योंकि वर्किंग कैपिटल सिर्फ़ उस प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं करती जिस पर विचार किया जा रहा है। नेट फिक्स्ड एसेट्स में बढ़ोतरी का मतलब हमेशा ज़्यादा क्षमता नहीं होता, क्योंकि इसका संबंध दूसरे ज़रूरी हिस्सों से भी हो सकता है जिनसे क्षमता नहीं बढ़ती। जांच की अवधि के दौरान, जिस प्रोडक्ट पर विचार किया जा रहा है, उसके लिए नेट फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल दोनों में कुल मिलाकर कमी आई। घरेलू और एक्सपोर्ट ऑपरेशन्स के बीच बंटवारा सेल्स वैल्यू के आधार पर किया जाता है।

छ.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

62. एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 11 और उसके साथ एनेक्शर II के अनुसार, नुकसान का पता लगाने के लिए उन कारकों की जांच की जानी चाहिए जिनसे घरेलू उद्योग को नुकसान का संकेत मिल सकता है। इसमें "...सभी संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा, जैसे डंप किए गए आयात की मात्रा, घरेलू बाजार में वैसी ही वस्तुओं की कीमतों पर उनका असर, और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयात का नतीजा..."। कीमतों पर डंप किए गए आयात के असर पर विचार करते समय, यह जांचना ज़रूरी है कि क्या भारत में वैसी ही वस्तु की कीमत की तुलना में डंप किए गए आयात के कारण कीमतों में भारी कमी (प्राइस अंडरकटिंग) आई है, या क्या ऐसे आयात का असर कीमतों को काफी हद तक कम करने या कीमतों में होने वाली संभावित बढ़ोतरी को काफी हद तक रोकने वाला रहा है। भारत में घरेलू उद्योग पर डंप किए गए आयात के असर की जांच के लिए, नियमों के एनेक्शर II के अनुसार उद्योग की स्थिति से जुड़े संकेतकों पर विचार किया गया है, जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, इन्वेंट्री, लाभप्रदता, शुद्ध बिक्री से प्राप्ति, डंपिंग का स्तर और मार्जिन आदि।
63. यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग 'बैकवर्ड इंटीग्रेटेड' नहीं है, जिससे लागत बढ़ रही है और घरेलू उद्योग को हो रहे नुकसान की वजह बैकवर्ड इंटीग्रेशन का न होना है। अथॉरिटी का कहना है कि घरेलू उद्योग ने 2020-21 और 2021-22 में मुनाफ़ा कमाया था। अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन का न होना घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर असर डालने वाला कोई कारण होता, तो घरेलू उद्योग को पहले भी नुकसान हुआ होता। अथॉरिटी ने 'यूरोपियन यूनियन – बायोडीज़ल (अर्जेंटीना)' मामले में अपीलेंट बाँडी के फ़ैसले पर ध्यान दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि अथॉरिटी को उन विशेषताओं के संबंध में 'नॉन-एट्रिब्यूशन एनालिसिस' (कारणों का विश्लेषण) करने की ज़रूरत नहीं है जो किसी उद्योग का स्वाभाविक हिस्सा हैं और नुकसान की अवधि के दौरान उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हिस्सा लेने वाले उत्पादकों द्वारा दिए गए जवाबों से पता चला है कि उत्पाद को 'डंप की गई कीमतों' पर भारत में निर्यात किया गया है। इसी तरह, यह तथ्य कि सोलापुर, महाराष्ट्र में आवेदक की फ़ैसिलिटी बंदरगाहों और पेट्रोकेमिकल हब से दूर है - जिससे लॉजिस्टिक्स और इनलैंड फ्रेट (देश के भीतर हुलाई) की लागत बढ़ जाती है और उत्पादन लागत भी ज़्यादा हो जाती है - जांच की अवधि में हुए नुकसान और पहले हुए मुनाफ़े को सही नहीं ठहराता है। इसलिए, अथॉरिटी का यह मानना नहीं है कि बताया गया नुकसान इस वजह से हुआ है कि घरेलू उद्योग 'बैकवर्ड इंटीग्रेटेड' नहीं है या इसकी लोकेशन (जगह) की वजह से ऐसा हुआ है।
64. इस बात पर कि घरेलू इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कम हुआ है, जिससे प्रोडक्शन की लागत बढ़ी है और नतीजतन नुकसान हुआ है, अथॉरिटी का मानना है कि प्रोडक्शन में कमी खुद घरेलू मार्केट में संबंधित सामान की डंपिंग का सीधा नतीजा

है। जब घरेलू इंडस्ट्री को डंप किए गए इम्पोर्ट की वजह से वॉल्यूम पर बुरा असर पड़ रहा हो, तो इससे होने वाले नुकसान या बढ़ी हुई लागत को सिर्फ अंदरूनी कमियों या कम प्रोडक्शन से जोड़ना सही नहीं होगा। वॉल्यूम पर ऐसे बुरे असर डंप किए गए इम्पोर्ट की मौजूदगी से सीधे तौर पर जुड़े हैं, जिन्होंने घरेलू प्रोडक्शन को कम किया है और कैपेसिटी के इस्तेमाल को दबाया है। अथॉरिटी ने यह भी गौर किया कि संबंधित सामान की इम्पोर्ट कीमतें घरेलू इंडस्ट्री की प्रोडक्शन लागत से कम थीं, जिससे नुकसान और बढ़ गया। इन बातों को देखते हुए, अथॉरिटी का मानना है कि प्रोडक्शन में कमी और उसके कारण लागत में बढ़ोतरी को डंप किए गए इम्पोर्ट के असर से अलग नहीं किया जा सकता।

65. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने अपनी सालाना रिपोर्ट में हुए नुकसान का मुख्य कारण भू-राजनीतिक तनाव, सप्लाई चेन में रुकावट और जलवायु से जुड़े जोखिमों को बताया है, और डंप किए गए इम्पोर्ट को नुकसान का एक अहम कारण नहीं माना है। अथॉरिटी का मानना है कि संबंधित पक्षों ने सालाना रिपोर्ट का चुनिंदा हवाला दिया है; घरेलू उद्योग की 2024-25 की सालाना रिपोर्ट की जांच करने पर यह साफ है कि घरेलू उद्योग ने यह भी कहा है कि डंप किए गए इम्पोर्ट की वजह से उसके कामकाज पर बुरा असर पड़ा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, अथॉरिटी का मानना है कि संबंधित पक्षों का तर्क सही साबित नहीं होता है और इसलिए, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
66. इस बात पर कि जापान, कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से होने वाला आयात कुल आयात का 7% है, आयात के आंकड़ों की जांच की गई है और यह पाया गया है कि इन आयातों का कुल हिस्सा कुल आयात के 6% से भी कम है।
67. इस बात पर कि दी जाने वाली सैलरी और वेज (मज़दूरी) में बढ़ोतरी हुई है, जिससे घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता था, अथॉरिटी ने पाया है कि घरेलू इंडस्ट्री में वेज 2023-24 तक तो बढ़े, लेकिन जांच की अवधि में इनमें कमी आई है। जांच की अवधि में सैलरी और वेज 2023-24 की तुलना में कम हैं और घरेलू इंडस्ट्री को जांच की अवधि में ज़्यादा नुकसान हुआ है। घरेलू इंडस्ट्री को हुए वित्तीय नुकसान की वजह सिर्फ वेज और सैलरी को नहीं माना जा सकता।
68. नियमों के अनुलग्नक II का पैरा (iii) आयात के सामूहिक विश्लेषण से संबंधित है। यह इस प्रकार है:

(iii) ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात पर एक साथ एंटीडंपिंग जांच चल रही हो, नामित प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन तभी करेगा, जब वह यह निर्धारित करे कि, -

(क) प्रत्येक देश से आयात के संबंध में स्थापित डंपिंग मार्जिन निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाने पर दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत है या जहां व्यक्तिगत देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, वहां आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात का सात प्रतिशत से अधिक है; और

(ख) आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों और आयातित उत्पादों तथा उसी तरह के घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए, आयात के प्रभावों का सामूहिक मूल्यांकन करना उचित है।

69. यह पता लगाने के लिए कि क्या आयातित वस्तु और वैसी ही घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयात के असर का सामूहिक मूल्यांकन उचित है, निम्नलिखित पैमानों की जांच की गई है: -

क. अलग-अलग पार्टियों द्वारा सप्लाई किए गए उत्पाद एक जैसी वस्तुएं हैं और गुणों में उनकी तुलना की जा सकती है।

ख. देश में बने उत्पाद और आयातित उत्पाद एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

ग. घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद के बीच सीधा मुकाबला है, और आयातित उत्पादों के आपस में भी मुकाबला है।

घ. उपभोक्ता घरेलू और आयातित सामग्री का एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं और निर्यातक तथा घरेलू उद्योग ने एक ही तरह के ग्राहकों को वही उत्पाद बेचा है।

ङ. संबंधित देशों से आयात की कीमतें एक साथ बदली हैं।

70. ऊपर दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए, अथॉरिटी यह उचित समझती है कि संबंधित देशों से विचार-धीन उत्पाद के डंप किए गए आयात का घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले प्रभावों का सामूहिक रूप से आकलन किया जाए।

छ.3.1 मांग/प्रतीत खपत का आकलन

71. इस जांच के मकसद से, भारत में वैसी ही वस्तु की मांग या स्पष्ट खपत को इस तरह परिभाषित किया गया है: घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, भारत के दूसरे उत्पादक की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से विचाराधीन उत्पाद के आयात का कुल योग। इस तरह आंकी गई मांग नीचे दी गई तालिका में बताई गई है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	एम टी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूची	100	95	90	66
3	अन्य भारतीय उत्पादक की बिक्री	एम टी	-	-	-	-
4	प्रवृत्ति	सूची	-	-	-	-
5	विषय देशों से आयात	एम टी	24,304	19,729	27,583	36,207
6	प्रवृत्ति	सूची	100	81	113	149
7	अन्य देशों से आयात	एम टी	1,545	952	1,682	2,302
8	प्रवृत्ति	सूची	100	62	109	149
9	मांग/उपभोग	एम टी	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूची	100	85	106	124

72. देखा गया है कि 2021-22 की तुलना में 2022-23 में मांग में कमी आई। 2023-24 में मांग बढ़ी और जांच की अवधि के दौरान इसमें और वृद्धि हुई। नुकसान की अवधि के दौरान मांग में बढ़ोतरी हुई है।

छ.3.2 डंप किए गए आयात का मात्रात्मक प्रभाव

73. आयात की मात्रा के संबंध में, अथॉरिटी को यह विचार करना होगा कि क्या संबंधित देश से डंप किए गए आयात में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है - चाहे वह कुल मात्रा के संदर्भ में हो या भारत में उत्पादन या खपत के अनुपात में। इसका विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में किया गया है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	विषय देशों से आयात	एम टी	24,304	19,729	27,583	36,207
2	अन्य देशों से आयात	एम टी	1,545	952	1,682	2,302

3	विषय देश से आयात निम्न के संबंध में					
क	भारत उत्पादन	%	***	***	***	***
ख	प्रवृत्ति	सूची	100	63	152	236
ग	भारतीय मांग	%	***	***	***	***
घ	प्रवृत्ति	सूची	100	96	107	120
ङ	कुल आयात	%	94%	95%	94%	94%

74. भारतीय उत्पादन के मुकाबले आयात 2022-23 में घटा, लेकिन 2023-24 में बढ़ गया। जांच की अवधि में आयात और भी बढ़ा। इसी तरह, भारतीय मांग के मुकाबले आयात 2022-23 में घटा, लेकिन 2023-24 में बढ़ा और उसके बाद जांच की अवधि में और भी बढ़ गया। यह देखा गया है कि नुकसान की अवधि के दौरान उत्पादन और मांग के मुकाबले आयात में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए अर्थोपरीति का मानना है कि भारत में मांग में हुई बढ़ोतरी की तुलना में आयात में बढ़ोतरी ज्यादा थी।
75. नुकसान की अवधि के दौरान, कुल आयात के मुकाबले संबंधित देशों से आयात का स्तर लगभग एक जैसा ही बना रहा है।

छ.3.3 डंप किए गए आयात का कीमत पर असर

76. एसोसिएटेड इंपोर्ट के ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज़ पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे समझने के लिए संबंधित देश से जुड़े इंपोर्ट की वजह से फ्लोरिडा अंडरकटिंग, पीएआरएम सप्लेशन और वैल्युएशन न्यूट्रिशन (यदि कोई हो) की जांच की गई है। इस एनालिसिस के लिए, घरेलू उद्योग के प्रोडक्शन कास्ट, नेट सेल रियलाइजेशन (एनएसआर) और नॉन-इंजुरियस प्रॉपर्टीज (एनआईपी) की तुलना संबंधित देश से आने वाले संबंधित सामान के इंपोर्ट की लैंड्रेड प्रॉजेक्ट से की गई है।

क. आयात मूल्य में बदलाव

77. नीचे दी गई तालिका में आयात मूल्य और कच्चे माल की कीमत में बदलाव को दिखाया गया है। विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए मुख्य कच्चा माल 'मोनोएथेनॉल एमाइन्स' है और घरेलू उद्योग ने भारत में इन उत्पादों के आयात मूल्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	मोनोएथेनॉल अमाइन्स	रुपये/ एम टी	1,23,463	1,48,801	1,00,006	1,02,139
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	121	81	83
3	आयात मूल्य	रुपये/ एम टी	2,22,039	3,49,881	1,69,299	1,30,886
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	158	76	59

78. देखा गया है कि 2022-23 में कच्चे माल की कीमतें बढ़ीं और इस दौरान आयात की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई। 2023-24 में कच्चे माल की कीमतें घटीं और जांच की अवधि के दौरान स्थिर रहीं। हालांकि, 2023-24 में आयात की कीमत में गिरावट आई और उसके बाद जांच की अवधि में इसमें और कमी आई है।

79. नुकसान वाली अवधि में कच्चे माल की कीमतों में 17% की गिरावट आई, जबकि जांच की अवधि में आयात की कीमतों में 41% की गिरावट आई है। अथॉरिटी का मानना है कि आयात की कीमतें कच्चे माल की कीमतों के हिसाब से नहीं बदली हैं, और उनमें कच्चे माल की कीमतों में आई गिरावट की तुलना में कहीं ज़्यादा गिरावट आई है। इसलिए, यह तर्क सही नहीं है कि विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में बदलाव, अमोनिया और मोनोएथेनॉलमाइन (विदेश मंत्रालय) जैसे मुख्य कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के अनुरूप है।

ख. कीमत कम करना

80. प्राइस अंडरकटिंग (कीमत कम करने) के विश्लेषण के लिए, घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री कीमत की तुलना संबंधित देशों से होने वाले आयात की लैंडेड कीमत से की गई है। इसके अनुसार, संबंधित देशों से डंप किए गए आयात की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	चीन पी आर	यूरोपीय संघ	सऊदी अरब	ताइवान	भारत औसत
1	आयात मात्रा	MT	12,414	11,615	10,691	1,486	36,207
2	शुद्ध बिक्री	रुपये/ एम टी	***	***	***	***	***
3	लैंडेड मूल्य	रुपये/ एम टी	1,43,206	1,45,544	1,34,946	1,47,265	1,41,684
4	मूल्य अंडरकटिंग	रुपये/ एम टी	***	***	***	***	***
5	मूल्य अंडरकटिंग	%	10%	8%	16%	7%	11%

81. प्राधिकरणका मानना है कि जिन सामानों का आयात किया जा रहा है, वे घरेलू इंडस्ट्री की कीमतों से कम कीमत पर बेचे जा रहे हैं और यह कीमत का अंतर (प्राइस अंडरकटिंग) पॉजिटिव और काफी ज़्यादा है। यह कीमत का अंतर तब भी पॉजिटिव है, जब घरेलू इंडस्ट्री इस प्रोडक्ट को नुकसान उठाकर बेच रही है।

ग. कीमतों को दबाना/कम करना

82. यह पता लगाने के लिए कि क्या डंप किए गए आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयात का असर कीमतों को काफी हद तक दबाने या उन कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने का है जो सामान्य तौर पर होतीं, नुकसान की अवधि के दौरान लागत और कीमतों में हुए बदलावों की तुलना नीचे दिए गए तरीके से की जाती है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	विक्रय मूल्य	रुपये/ एम टी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	125	68	59
3	परिवर्तन	रुपये/ एम टी	***	***	***	***
4	बिक्री लागत	रुपये/ एम टी	***	***	***	***
5	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	121	90	89

6	परिवर्तन	रुपये/ एम टी	***	***	***	***
7	लैंडेड मूल्य	रुपये/ एम टी	2,40,358	3,78,746	1,83,266	1,41,684
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	158	76	59
9	परिवर्तन	रुपये/ एम टी				

83. यह देखा गया है कि,

क. 2022-23 में, बिक्री की लागत 21 इंडेक्स पॉइंट बढ़ी, जबकि बिक्री मूल्य भी 25 इंडेक्स पॉइंट बढ़ा।

ख. 2023-24 में, बिक्री की लागत में 31 इंडेक्स पॉइंट की कमी आई, जबकि बिक्री मूल्य में 57 इंडेक्स पॉइंट की गिरावट हुई। इस साल घरेलू उद्योग को मामूली नुकसान उठाना पड़ा।

ग. जांच की अवधि में, जहां बिक्री की लागत में 1 इंडेक्स पॉइंट की कमी आई है, वहीं बिक्री मूल्य में 9 इंडेक्स पॉइंट की कमी आई है।

घ. हालांकि 2022-23 और 2023-24 के दौरान इंपोर्ट की 'लैंडेड कीमत' (देश में पहुँचने पर कुल लागत) घरेलू इंडस्ट्री की लागत और बिक्री कीमत से ज़्यादा बनी रही, लेकिन 'जांच की अवधि' (पीओआई) के दौरान इसमें भारी गिरावट आई। खास तौर पर, लैंडेड कीमत 2023-24 की पहली छमाही में ₹2,22,342 प्रति मीट्रिक टन से गिरकर उसी साल की दूसरी छमाही में ₹1,37,460 प्रति मीट्रिक टन हो गई (जो पीओआई की पहली छमाही भी है, जिससे एक ओवरलैपिंग अवधि बनती है)। इसके उलट, पीओआई की दूसरी छमाही के दौरान लैंडेड कीमत में थोड़ी रिकवरी हुई और यह बढ़कर ₹1,43,965 प्रति मीट्रिक टन हो गई।

ङ. ठीक पिछले साल की तुलना में, जांच की अवधि के दौरान बिक्री मूल्य में गिरावट आई, लेकिन लैंडेड प्राइस (आयातित माल की लागत) में गिरावट की दर ज़्यादा थी। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतें कम बनी हुई हैं।

84. प्राधिकरणका का मानना है कि जांच की अवधि के दौरान, आयातित सामान की 'लैंडेड कीमत' (आयात लागत) के कारण घरेलू उद्योग उचित और लाभकारी कीमतें नहीं वसूल पाया। इसलिए, आयातित सामान की लैंडेड कीमत ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबाया और कम किया है। 2023-24 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में लैंडेड कीमत, 2023-24 की दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) की तुलना में काफी ज़्यादा है; ये दोनों ही जांच की अवधि (POI) का हिस्सा हैं। इस अवधि के दौरान बिक्री की कीमत लैंडेड कीमत से कम रही है, जिससे नुकसान और बढ़ गया है।

छ.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक पैरामीटर

85. नियमों के अनुलग्नक II के अनुसार, नुकसान का पता लगाने के लिए ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर डंप किए गए आयात के असर की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर डंप किए गए आयात के असर के संबंध में, नियम यह भी कहते हैं कि घरेलू उद्योग पर डंप किए गए आयात के असर की जांच में उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सभी संबंधित आर्थिक कारकों और सूचकांकों का निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। इसमें बिक्री, मुनाफ़े, उत्पादन, बाज़ार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर रिटर्न या क्षमता के इस्तेमाल में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों पर असर डालने वाले कारक; डंपिंग मार्जिन का स्तर; और कैश फ़्लो, इन्वेंट्री, रोज़गार, वेतन, विकास और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक असर शामिल हैं। घरेलू उद्योग से जुड़े नुकसान के विभिन्न पैमानों पर नीचे चर्चा की गई है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग और बिक्री की मात्रा।

86. नुकसान की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता के उपयोग का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	क्षमता	एम टी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	100	100
3	उत्पादन	एम टी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	130	75	63
5	क्षमता उपयोग - संयंत्र	%	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	129	75	64
7	घरेलू बिक्री	एम टी	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	96	90	66
9	निर्यात बिक्री	एम टी	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	244	12	8

87. यह देखा गया है कि:

- क. नुकसान की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता एक जैसी बनी रही। यह देखा गया है कि क्षमता केवल विचाराधीन उत्पाद के लिए ही समर्पित नहीं है।
- ख. जब प्लांट पूरी क्षमता से काम करता है, तो आवेदक का प्लांट इतना प्रोडक्ट बना सकता है कि घरेलू बाज़ार की 60% मांग पूरी हो सके। घरेलू इंडस्ट्री ने सबूत दिए हैं कि नया प्लांट लगाने के लिए उन्हें पर्यावरण मंजूरी तो मिल गई थी, लेकिन नुकसान होने की वजह से इस प्लान को रोक दिया गया है।
- ग. 2021-22 की तुलना में 2022-23 में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता के इस्तेमाल में बढ़ोतरी हुई। 2023-24 में, संबंधित देश से आयात की मात्रा बढ़ने के साथ घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता के इस्तेमाल में गिरावट आई। जांच की अवधि के दौरान, 2023-24 की तुलना में उत्पादन और क्षमता के इस्तेमाल में और गिरावट आई है।
- घ. 2021-22 की तुलना में 2022-23 में घरेलू इंडस्ट्री की घरेलू बिक्री में गिरावट आई। 2023-24 और जांच की अवधि के दौरान घरेलू बिक्री में और गिरावट आई। जहां मांग बढ़ी है, वहीं घरेलू बिक्री में कमी आई है। यह देखा गया है कि घरेलू इंडस्ट्री की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है, जबकि वे अपनी काफी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे (यानी काफी क्षमता खाली पड़ी थी)।
- ङ. नुकसान की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में गिरावट आई है।
- च. घरेलू उद्योग की एक्सपोर्ट बिक्री में भी गिरावट आई है, लेकिन यह अब भी मुनाफ़े वाली बनी हुई है। अथॉरिटी ने घरेलू उद्योग के इस तर्क पर ध्यान दिया है कि वह एक्सपोर्ट बिक्री पर निर्भर नहीं है और ऐसा केवल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वे घरेलू बाज़ार में बिक्री करने में असमर्थ हैं।

ख. सभी सप्लायर्स की मार्केट हिस्सेदारी

88. घरेलू उद्योग, भारत में अन्य उत्पादकों और भारत में उत्पादों के आयात का बाज़ार हिस्सा नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	113	85	53
3	अन्य घरेलू उत्पादक	%	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	-	-	-	-
5	विषय देशों से आयात	%	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	96	107	120
7	अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	73	102	120

89. ऊपर दी गई बातों के आधार पर, अथॉरिटी यह नोट करती है कि:

- क. घरेलू उद्योग की बाज़ार हिस्सेदारी 2022-23 में बढ़ी, 2023-24 में घटी और उसके बाद जांच की अवधि में फिर से घट गई।
- ख. 2022-23 में संबंधित आयात का बाज़ार हिस्सा मामूली रूप से घटा, उसके बाद 2023-24 में बढ़ा और जांच की अवधि में और भी बढ़ गया।
- ग. मांग का [***] हिस्सा पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग घरेलू बाज़ार का केवल [***] % ही पूरा कर पा रहा है।
- घ. घरेलू उद्योग ने कहा है कि हालांकि उसने क्षमता बढ़ाने के लिए ज़रूरी मंजूरी ले ली है, लेकिन ऐसा विस्तार नहीं किया गया है, क्योंकि मौजूदा क्षमता का बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है।

ग. इन्वेंटरी

90. इन्वेंटरी से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	प्रारंभिक स्टॉक	एम टी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	92	228	109
3	समापन स्टॉक	एम टी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	248	254	509
5	औसत स्टॉक	एम टी	***	***	***	***

6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	167	240	301
---	-----------	---------	-----	-----	-----	-----

91. यह देखा गया है कि नुकसान की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत इन्वेंट्री में बढ़ोतरी हुई है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत इन्वेंट्री तब भी बढ़ी, जब संबंधित उत्पाद की मांग में बढ़ोतरी हुई थी। घरेलू उद्योग ने बताया है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान उनके पास मौजूद इन्वेंट्री में 200% की बढ़ोतरी हुई है।

घ. मुनाफ़ा कमाने की क्षमता, नकद मुनाफ़ा और लगाई गई पूंजी पर रिटर्न।

92. नुकसान की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, लगाई गई पूंजी पर रिटर्न और नकद लाभ नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं: -

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	लाभ/(हानि)	रुपये/ एम टी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	137	-1	-30
3	लाभ/(हानि)	रुपये लाख	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	132	-0	-20
5	PBIT (ब्याज एवं कर पूर्व लाभ)	रुपये लाख	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	123	3	-15
7	नकद लाभ	रुपये लाख	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	128	11	-7
9	निवेश पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति (Trend)	सूचकांक	100	116	2	-14

93. यह देखा गया है कि,

क. 2022-23 में जब इंपोर्ट कम हुआ, तो घरेलू इंडस्ट्री का प्रति यूनिट प्रॉफ़िट बढ़ गया। 2023-24 में प्रॉफ़िट में भारी गिरावट आई और यह नुकसान में बदल गया, और जांच की अवधि में यह नुकसान और भी बढ़ गया है।

ख. 2022-23 में मुनाफ़ा बढ़ा और उसके बाद जांच की अवधि तक इसमें गिरावट आई, जिसके चलते भारी नुकसान हुआ।

ग. घरेलू उद्योग का ब्याज और टैक्स से पहले का मुनाफ़ा और कैश मुनाफ़ा 2022-23 में बढ़ा, लेकिन उसके बाद जांच की अवधि तक इसमें गिरावट आई; जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को कैश नुकसान और ब्याज से पहले नुकसान उठाना पड़ा।

घ. घरेलू उद्योग के निवेश पर रिटर्न 2022-23 में बढ़ा, 2023-24 में इसमें भारी गिरावट आई और यह नेगेटिव हो गया, और उसके बाद जांच की अवधि में इसमें और गिरावट आई।

ड. घरेलू उद्योग की मौजूदा कीमतें उत्पादन लागत से कम हैं, जिसके कारण नुकसान हो रहा है।

ड. रोज़गार, उत्पादकता और वेतन

94. नीचे दी गई तालिका में नुकसान की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग में रोज़गार, उत्पादकता और मज़दूरी का विवरण दिया गया है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	131	142	144
3	प्रति दिन उत्पादकता	एम टी /दिन	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	113	113	111
5	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एम टी /संख्या	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	संख्या	100	99	42	44
7	मजदूरी	रुपये लाख	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	158	312	241

95. यह देखा गया है कि:

क. नुकसान की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई।

ख. 2022-23 में प्रति दिन उत्पादकता बढ़ी, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आई है।

ग. चोट लगने की अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता में लगातार गिरावट आई है।

घ. घरेलू उद्योग द्वारा दी जाने वाली मजदूरी में 2021-22 की तुलना में POI के दौरान बढ़ोतरी हुई है।

च. विकास

96. नीचे दी गई तालिका नुकसान की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के विकास के पैरामीटर दिखाती है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	POI
1	उत्पादन	%	30%	-42%	-16%
2	क्षमता उपयोग	%	29%	-42%	-14%
3	घरेलू बिक्री	%	-4%	-6%	-28%
4	प्रति इकाई PBT	%	37%	-100%	-5718%

5	प्रति इकाई नकद लाभ	%	33%	-91%	-186%
6	प्रति इकाई PBIT	%	28%	-98%	-876%
7	निवेश पर प्रतिफल	%	16%	-98%	-844%
8	स्टॉक	%	67%	44%	25%

97. जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग के वॉल्यूम पैरामीटर और सभी प्राइस पैरामीटर (जैसे मुनाफ़ा, कैश मुनाफ़ा, ब्याज और टैक्स से पहले का मुनाफ़ा और लगाई गई पूंजी पर रिटर्न) में काफी नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। ये पैरामीटर उस स्तर के आस-पास भी नहीं रहे, जिस पर उन्हें होना चाहिए था। घरेलू उद्योग ने सबसे पहले 2023-24 में वॉल्यूम और प्राइस पैरामीटर दोनों में नकारात्मक वृद्धि का अनुभव किया, जो जांच की अवधि के दौरान भी जारी रही।

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

98. अथॉरिटी ने देखा है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है। यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई पूंजी पर रिटर्न नेगेटिव है, जिससे पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता पर असर पड़ेगा।
99. प्रोडक्ट की बढ़ती मांग को देखते हुए, घरेलू इंडस्ट्री ने अपनी कुल क्षमता को [***] मीट्रिक टन (जिसमें विचाराधीन प्रोडक्ट के अलावा अन्य प्रोडक्ट भी शामिल हैं) तक बढ़ाने की मंजूरी ले ली थी। घरेलू इंडस्ट्री भारी निवेश करके अपनी क्षमता बढ़ाना चाहती है। इतने बड़े वित्तीय नुकसान के कारण, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों के लिए पूंजी जुटाने की क्षमता पर भी असर पड़ा है।

ज. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

100. अथॉरिटी ने पाया कि जांच की अवधि के दौरान, संबंधित आयात की 'लैंडेड कीमत' (आयातित माल की देश में पहुंचने पर कुल लागत) घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री मूल्य से कम थी। संबंधित आयात की इस लैंडेड कीमत ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया है, जिससे घरेलू उद्योग को मात्रा और कीमत, दोनों ही पैमानों पर काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए, डंप किए गए आयात ही घरेलू उद्योग की कीमतों पर असर डालने वाले मुख्य कारक हैं। घरेलू उद्योग ने ग्राहकों के साथ हुई बातचीत के ऐसे सबूत पेश किए हैं जिनसे पता चलता है कि ग्राहकों ने घरेलू उद्योग के साथ मोल-भाव करने के लिए आयातित माल की कीमत का हवाला दिया और उन पर आयातित माल की कीमतों के बराबर अपनी कीमतें कम करने का दबाव डाला।

झ. डंपिंग का पैमाना

101. डंपिंग की मात्रा इस बात का संकेत है कि भारत में किस हद तक आयात की डंपिंग हो रही है। जांच से पता चला है कि जांच की अवधि के दौरान डंपिंग मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

छ.3.5 चोट के संबंध में अवलोकन

102. विचाराधीन उत्पाद के आयात और घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की जांच से पता चलता है कि:

- क. संबंधित देशों से आयात आधार वर्ष के 24,304 MT से बढ़कर 36,207 MT हो गया है। आयात में वास्तविक मात्रा के हिसाब से वृद्धि हुई है।
- ख. प्रोडक्शन के मुकाबले इंपोर्ट, बेस ईयर में ***% से बढ़कर जांच की अवधि में ***% हो गया। खपत के मुकाबले इंपोर्ट, बेस ईयर में ***% से बढ़कर जांच की अवधि में ***% हो गया। रिलेटिव टर्म्स में इंपोर्ट बढ़ा है।

- ग. लैंडेड कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, जिसके परिणामस्वरूप पॉजिटिव प्राइस अंडरकटिंग होती है।
- घ. जांच की अवधि के दौरान, लैंडेड कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही है। नतीजतन, घरेलू उद्योग लागत में आए बदलावों के हिसाब से अपनी कीमतें समायोजित नहीं कर पाया है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतें कम बनी रहीं।
- ङ. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता के उपयोग में गिरावट आई।
- च. नुकसान की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाज़ार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
- छ. इंजरी की अवधि के दौरान औसत इन्वेंट्री में वृद्धि हुई।
- ज. 2022-23 में घरेलू उद्योग का मुनाफ़ा कम हुआ है और जांच की अवधि में यह नुकसान में बदल गया है। प्रति यूनिट मुनाफ़ा *** रुपये प्रति मीट्रिक टन से घटकर *** रुपये प्रति MT का नुकसान हो गया है।
- झ. इसी तरह, 2022-23 में घरेलू उद्योग के कैश प्रॉफ़िट और लगाई गई पूंजी पर रिटर्न में गिरावट आई और उसके बाद जांच की अवधि में ये नेगेटिव हो गए।
- ञ. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वॉल्यूम और कीमत, दोनों पैमानों पर बढ़ोतरी के मामले में नुकसान उठाना पड़ा।
- ट. घरेलू उद्योग की पूंजी जुटाने की क्षमता पर बुरा असर पड़ा है।
- ठ. डंप किए गए आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।
- ड. जांच की अवधि के दौरान डंपिंग मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

ज. श्रेय न देना और कारण-संबंध

103. नियमों के अनुसार, डंप किए गए आयात के अलावा अन्य ज्ञात कारकों की भी जांच करना ज़रूरी है जो घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हों, ताकि इन अन्य कारकों से होने वाले नुकसान को डंप किए गए आयात के कारण हुआ नुकसान न माना जाए। नीचे इस बात की जांच की गई है कि क्या डंप किए गए आयात के अलावा अन्य कारकों ने भी घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने में भूमिका निभाई है। अथॉरिटी शुरू में यह नोट करती है कि एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए न तो एक्ट और न ही नियमों में यह ज़रूरी है कि डंपिंग ही घरेलू उद्योग को नुकसान का एकमात्र कारण हो।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

104. अथॉरिटी का कहना है कि संबंधित देशों के अलावा, जापान, कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से होने वाला कुल आयात, कुल आयात का 6% से भी कम है।

ख. मांग में संकुचन

105. प्राधिकरण का मानना है कि नुकसान की अवधि के दौरान मांग बढ़ी है, इसलिए घरेलू उद्योग को हुए नुकसान का कारण मांग में कमी नहीं है।

ग. उपभोग के पैटर्न में बदलाव

106. प्राधिकरण का मानना है कि विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है, जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचा हो।

घ. व्यापार को सीमित करने वाले तौर-तरीके

107. प्राधिकरण का मानना है कि विचाराधीन उत्पाद की बिक्री पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है और प्राधिकरण के ध्यान में ऐसी कोई प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया नहीं लाई गई है।

ड. टेक्नोलॉजी में विकास

108. प्राधिकरण यह नोट करता है कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन हेतु प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।"

च. उत्पादकता

109. उत्पादन में कमी के साथ-साथ, प्रति कर्मचारी उत्पादन में भी कमी आई है।

छ. निर्यात प्रदर्शन

110. प्राधिकरण का मानना है कि ऊपर बताई गई नुकसान की जानकारी सिर्फ घरेलू बाज़ार में घरेलू इंडस्ट्री के परफॉर्मंस से जुड़ी है। इसलिए, घरेलू इंडस्ट्री को हुए नुकसान का कारण उसके एक्सपोर्ट परफॉर्मंस को नहीं माना जा सकता। अथॉरिटी ने देखा है कि पिछले साल की तुलना में जांच की अवधि में एक्सपोर्ट बिक्री में कमी आई है। हालांकि, एक्सपोर्ट से अभी भी मुनाफ़ा हो रहा है। इसलिए, घरेलू बाज़ार में बताए गए नुकसान का कारण एक्सपोर्ट परफॉर्मंस नहीं हो सकता।

ज. अन्य उत्पादों का प्रदर्शन

111. प्राधिकरण ने केवल संबंधित सामान के परफॉर्मंस से जुड़े डेटा पर विचार किया है। इसलिए, घरेलू इंडस्ट्री को हुए नुकसान का कारण अन्य उत्पादित और बेचे गए उत्पादों का परफॉर्मंस नहीं हो सकता है।

झ. चोट की गंभीरता का स्तर

112. प्राधिकरण ने नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के साथ एनेक्ज़र III में बताए गए सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए 'नॉन-इंजुरियस प्राइस' (ऐसा मूल्य जिससे नुकसान न हो) तय किया है। संबंधित सामान का नॉन-इंजुरियस प्राइस, जांच की अवधि के दौरान उत्पादन लागत से जुड़ी वेरिफाइड जानकारी/डेटा का इस्तेमाल करके तय किया गया है। 'इंजुरी मार्जिन' (नुकसान का अंतर) की गणना करने के लिए संबंधित देशों से आने वाले सामान की 'लैंडेड प्राइस' (आयातित सामान की लागत) से तुलना करने के लिए नॉन-इंजुरियस प्राइस को आधार माना गया है। नॉन-इंजुरियस प्राइस तय करने के लिए, नुकसान वाली अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सबसे अच्छे इस्तेमाल को ध्यान में रखा गया है। यूटिलिटीज़ (जैसे बिजली, पानी आदि) के मामले में भी यही तरीका अपनाया गया है। नुकसान वाली अवधि के दौरान प्रोडक्शन कैपेसिटी (उत्पादन क्षमता) के सबसे अच्छे इस्तेमाल को भी ध्यान में रखा गया है। यह पक्का किया गया है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण या बार-बार न होने वाला खर्च शामिल न किया जाए। नियमों के एनेक्ज़र III में बताए अनुसार, नॉन-इंजुरियस प्राइस तक पहुंचने के लिए संबंधित सामान पर इस्तेमाल की गई औसत पूंजी (यानी औसत नेट फिक्स्ड एसेट्स और औसत वर्किंग कैपिटल) पर 22% का उचित रिटर्न (ब्याज, टैक्स और मुनाफे के लिए) माना गया है।

113. सहयोग करने वाले निर्यातकों के लिए 'लैंडेड प्राइस' (आयातित माल की लागत) का निर्धारण उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर किया गया है। आयात की लैंडेड प्राइस तय करने के लिए लागू कस्टम ड्यूटी को इसमें जोड़ा गया है। संबंधित देशों के उन उत्पादकों/निर्यातकों के लिए जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, अथॉरिटी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर लैंडेड प्राइस तय की है।

114. ऊपर तय की गई लैंडेड कीमत और नॉन-इंजुरियस कीमत के आधार पर, अथॉरिटी ने संबंधित देशों के प्रोड्यूसर्स/एक्सपोर्टर्स के लिए इंजुरी मार्जिन तय किया है और इसे नीचे दी गई टेबल में बताया गया है:

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक	अहानिकर मूल्य	अवतरित मूल्य	क्षति मार्जिन	%	सीमा
क	चीन					
1	बीएसएफ-वाईपीसी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	30-40
ख	यूरोपीय संघ					
1	बीएसएफ एंटरप्रेन एनवी	***	***	***	***	20-30
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	50-60
ग	सऊदी अरब					
1	सदारा केमिकल कंपनी	***	***	***	***	10-20
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	20-30
घ	ताइवान					
1	कोई भी उत्पादक	***	***	***	***	10-20

ज. भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे

ज.1 विरोधी हितधारक पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन

115. विरोधी पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित बातें कही हैं:

- क. डाउनस्ट्रीम यूज़र्स मुख्य रूप से घरेलू सप्लाय में कमी के कारण इंपोर्ट पर निर्भर हैं। जांच की अवधि के दौरान एप्लिकेंट की कम क्षमता के इस्तेमाल और बीच-बीच में प्रोडक्शन रुकने की वजह से यूज़र्स के पास विदेश से सामान मंगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा।
- ख. ईडीए की ज्यादा लागत एग्रोकेमिकल सेक्टर में निवेश और इनोवेशन पर असर डालेगी, जिससे ग्लोबल लेवल पर भारत की कॉम्पिटिटिवनेस कमज़ोर होगी।
- ग. ईडीए कई उद्योगों के लिए एक ज़रूरी इनपुट है, जिनमें फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट, टेक्सटाइल्स और एडहेसिव्स शामिल हैं। ईडीए पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने से मैनकोज़ेब बनाने वालों सहित आगे के मैन्युफैक्चरर्स के लिए इनपुट लागत बढ़ जाएगी; ये मैन्युफैक्चरर्स बड़ी हुई लागत का बोझ किसानों पर नहीं डाल सकते, जिससे उनकी कॉम्पिटिटिवनेस पर असर पड़ेगा।
- घ. मात्रात्मक सबूत बताते हैं कि 20-30% का एडीडी डाउनस्ट्रीम यूज़र्स को काफी नुकसान पहुँचाएगा, जिससे मुनाफ़े, उत्पादन और एक्सपोर्ट मार्केट शेयर में कमी आएगी।

- ड. एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने से व्यापार का रुख बदल जाएगा। जिन देशों पर ये ड्यूटी लगाई गई है, उनसे होने वाले आयात की जगह जापान, यूएसए और कोरिया आरपी जैसे देशों से आयात होगा, जो पहले से ही प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सामान सप्लाई कर रहे हैं।
- च. इससे घरेलू उद्योग को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसे वैसे ही प्रतिस्पर्धी दबावों का सामना करना पड़ेगा, जिससे यह ड्यूटी बेअसर हो जाएगी।
- छ. विरोधी पक्षों का मानना है कि यह जांच कानूनी रूप से दोषपूर्ण और भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें जापान, यूएसए और कोरिया आरपी को संबंधित देशों के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। हालांकि अलग-अलग तौर पर इनका आयात हिस्सा **3%** की सीमा से कम है, लेकिन सामूहिक रूप से ये देश कुल आयात का **7.28%** हिस्सा रखते हैं, जो एंटी-डंपिंग नियमों के नियम **14(डी)** के तहत शामिल किए जाने के लिए तय **7%** की सीमा से अधिक है।
- ज. इन 'नॉन-सब्जेक्ट' देशों से आयात की कीमतें 'सब्जेक्ट' देशों के बराबर हैं और घरेलू उद्योग के एनआईपी से काफी कम हैं, जिससे पता चलता है कि ये भी डंप किए गए और नुकसान पहुंचाने वाले आयात का स्रोत हैं। इन्हें बाहर रखना विश्व व्यापार संगठन के एंटी-डंपिंग समझौते के भेदभाव न करने के सिद्धांत का उल्लंघन है।

ज.2 आवेदक द्वारा प्रस्तुति

116. आवेदक ने भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित बातें कही हैं:

- क. इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल एग्नोकेमिकल और फार्मास्युटिकल कामों में किया जाता है, जैसे कि मैनकोज़ेब और सिटाग्लिप्टिन। मैनकोज़ेब के प्रोडक्शन में ईडीए का इस्तेमाल बहुत कम होता है, और मैनकोज़ेब के कुल प्रोडक्शन का **80%** से ज़्यादा हिस्सा एक्सपोर्ट किया जाता है, जिस पर कोई ड्यूटी नहीं लगती है।
- ख. सिटाग्लिप्टिन का इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों के इलाज के लिए किया जाता है। डॉक्टर सिटाग्लिप्टिन की लगभग **25-50** एमजी की डोज़ लिखते हैं। चूंकि सिटाग्लिप्टिन पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी सिर्फ **0.002%** है, इसलिए अंतिम उपभोक्ता पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी का कोई असर नहीं पड़ेगा।
- ग. प्रस्तावित उपायों का डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर असर न के बराबर है।
- घ. पहले कीमतें ज़्यादा थीं। प्रस्तावित एंटी-डंपिंग ड्यूटी को जोड़ने के बाद भी, आयात की कीमत इन पुराने स्तरों से कम ही रहेगी। इसलिए, एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने से यूज़र्स पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है।
- ड. **2022-23** में आयात की कीमत बढ़ने के बावजूद, घरेलू उद्योग ने जनहित को ध्यान में रखते हुए कीमतें बढ़ाने से परहेज किया।
- च. **2022-23** में अमोनिया और विदेश मंत्रालय की लागत बढ़ने के कारण आयात की कीमतें तेज़ी से बढ़ीं, जिससे कीमतों में **13%** की नेगेटिव अंडरकटिंग (कीमतों में अंतर) हुई; फिर भी, जनहित को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग ने उसी अनुपात में अपनी कीमतें नहीं बढ़ाईं।
- छ. इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल मुख्य रूप से एग्नोकेमिकल और फार्मास्युटिकल सेक्टर में होता है, जो 'पास-श्रू' इंडस्ट्री की तरह काम करते हैं। एंटी-डंपिंग ड्यूटी की वजह से लागत में होने वाली किसी भी बढ़ोतरी का बोझ आखिर में ग्राहकों पर डाले जाने की संभावना है, और इससे मांग पर बहुत कम असर पड़ेगा।
- ज. संबंधित देशों के एक्सपोर्टर्स की भारतीय बाज़ार के प्रति कोई लंबी अवधि की प्रतिबद्धता नहीं होगी और वे सप्लाई को ज़्यादा मुनाफ़े वाले बाज़ारों की ओर मोड़ सकते हैं। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग स्थिर सप्लाई और

उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखता है, साथ ही इससे इन्वेंट्री और वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतें भी कम रहती हैं।

- झ. एकमात्र भारतीय उत्पादक होने के नाते, घरेलू उद्योग को स्थिरता से जुड़ी गंभीर चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसने पहले ही काफी समय से उत्पादन कम कर दिया है। एंटी-डंपिंग ड्यूटी न होने पर प्लांट बंद होने का वास्तविक खतरा है, जिससे रोजगार और आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा।
- ञ. घरेलू इंडस्ट्री का मौजूदा प्रदर्शन देश में नए निवेश को सही नहीं ठहराता है और दूसरे भारतीय उत्पादकों के लिए इस बिज़नेस में आना आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं है।
- ट. घरेलू उद्योग ने 2023-24 में जनहित से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां चलाकर समाज को लाभ पहुंचाने के लिए सीएसआर के तहत 2.88 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

ज.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

117. प्राधिकरण ने यह परीक्षण किया कि क्या प्रस्तावित एंटी-डंपिंग शुल्क का आरोपण सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण अभिलेख पर उपलब्ध सूचनाओं तथा विभिन्न पक्षों, जिनमें घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादक एवं उपभोक्ता शामिल हैं, के हितों पर विचार के आधार पर किया गया है।
118. प्राधिकरण ने एक गैज़ेट नोटिफिकेशन जारी करके इम्पोर्टर्स, कंज्यूमर्स और अन्य इच्छुक पार्टियों से उनकी राय मांगी। अथॉरिटी ने यूज़र्स के लिए एक प्रश्नावली भी तय की ताकि वे मौजूदा जांच से जुड़ी ज़रूरी जानकारी दे सकें, जिसमें एंटी-डंपिंग ड्यूटी का उनके कामकाज पर संभावित असर भी शामिल है। अथॉरिटी ने कई बातों पर जानकारी मांगी, जैसे कि अलग-अलग देशों के सप्लायर्स से मिलने वाले प्रोडक्ट की अदला-बदली की क्षमता, सोर्स बदलने की क्षमता, कंज्यूमर्स पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी का असर, और वे कारक जो एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगने से बनी नई स्थिति के अनुसार ढलने की प्रक्रिया को तेज़ या धीमा कर सकते हैं।
119. प्राधिकरण का मानना है कि एंटी-डंपिंग ड्यूटी का मकसद आम तौर पर डंपिंग जैसे अनुचित व्यापार तरीकों से घरेलू उद्योग को होने वाले नुकसान को खत्म करना है, ताकि भारतीय बाज़ार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से कायम की जा सके।
120. प्राधिकरण ने आर्थिक हित से जुड़ा एक सवालनामा तैयार किया था, जिसे इस जांच में शामिल सभी इच्छुक पक्षों को भेजा गया था। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडोरामा इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, कार्डोलाइट स्पेशलिटी केमिकल्स इंडिया एलएलपी और घरेलू उद्योग ने आर्थिक हित से जुड़ा सवालनामा जमा किया है। यूज़र्स का दावा है कि एंटी-डंपिंग ड्यूटी का उनके कामकाज पर बुरा असर पड़ेगा। यूज़र्स ने एंटी-डंपिंग ड्यूटी के असर का हिसाब नीचे दिए अनुसार लगाया है।

उपयोगकर्ता	कार्डोलाइट	कोरोमंडल	इंडोरामा
उत्पाद	एपाॅक्सी क्योरिंग एजेंट	मैन्कोजेब	इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न
एफजी में पीयूसी की लागत	रुपये/किग्रा	***	***
एफजी की कुल लागत	रुपये/किग्रा	***	***
एफजी का विक्रय मूल्य	रुपये/किग्रा	***	***
लाभप्रदता	रुपये/किग्रा	***	***

एफजी की कीमत में पीयूसी का हिस्सा	%	***	***
पीयूसी में काल्पनिक मूल्य वृद्धि	%	***	***
पीयूसी की लागत में वृद्धि	रुपये/किग्रा	***	***
एफजी की कीमत पर वृद्धि का प्रभाव	%	5.96%	2.91%

121. घरेलू उद्योग ने एंटी-डंपिंग ड्यूटी के असर का आकलन नीचे दिए गए तरीके से किया है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	मैन्कोजेब
1	मैन्कोजेब तकनीकी 85% न्यूनतम	रुपये/किग्रा	250
2	डाउनस्ट्रीम उत्पाद के लिए ईडीए (अनुमान)	किग्रा	0.20
3	1 किग्रा के लिए ईडीए मूल्य	रुपये/किग्रा	134
4	ईडीए पर एडीडी (काल्पनिक 20%)	रुपये/किग्रा	26.80
5	डाउनस्ट्रीम उद्योग (एपीआई उत्पादक) के लिए लागत वृद्धि	रुपये/किग्रा	5.36
6	तकनीकी उत्पादक पर एडीडी का प्रभाव	%	2.14%
7	मैन्कोजेब फॉर्मूलेशन मूल्य प्रति 1 किग्रा	रुपये	571
8	मैन्कोजेब की सांद्रता	%	75%
9	फॉर्मूलेशन उत्पादक के लिए लागत वृद्धि	रुपये	4.02
10	फॉर्मूलेशन उत्पादक पर एडीडी का प्रभाव	%	0.70%
11	1 किग्रा मैन्कोजेब द्वारा आवृत क्षेत्र	एकड़	1.25
12	प्रति एकड़ प्रभाव	रुपये	5

क्र.सं.	विवरण	इकाई	सिटाग्लिप्टिन
1	1 किग्रा उत्पाद की औसत कीमत	रुपये/किग्रा	7,500
2	डाउनस्ट्रीम उत्पाद के लिए ईडीए (अनुमान)	किग्रा	0.15
3	1 किग्रा के लिए ईडीए मूल्य	रुपये/किग्रा	134
4	ईडीए पर एंटी-डंपिंग शुल्क (काल्पनिक 20%)	रुपये/किग्रा	26.80
5	डाउनस्ट्रीम उद्योग (एपीआई उत्पादक) के लिए लागत वृद्धि	रुपये/किग्रा	4.02

6	टैबलेट निर्माता पर एंटी-डॉपिंग शुल्क का प्रभाव	%	0.05%
7	1 स्ट्रिप की कीमत	रुपये	85
8	1 टैबलेट की कीमत	रुपये/स्ट्रिप	8.50
9	सिट्राग्लिफ्टिन की प्रति टैबलेट खुराक	मि.ग्रा.	50
10	1 मि.ग्रा. की कीमत	रुपये/मि.ग्रा.	0.17
11	1 किग्रा की कीमत	रुपये/किग्रा	1,70,000
12	टैबलेट निर्माता के लिए लागत वृद्धि (मानते हुए कि पूरी लागत पास की जाती है)	रुपये/किग्रा	4.02
13	टैबलेट निर्माता पर एंटी-डॉपिंग शुल्क का प्रभाव	%	0.002%
14	प्रति स्ट्रिप प्रभाव	रुपये	0.002

122. घरेलू उद्योग और यूज़र इंडस्ट्री द्वारा जमा किए गए डेटा की जांच करने पर यह पाया गया है कि ईडीए, डाउनस्ट्रीम उत्पादों की लागत का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, और इसलिए अंतिम उत्पादों की कीमत पर इसका असर भी सीमित है।

123. नीचे दी गई तालिका आयात की लैंडेड कीमत दिखाती है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि (पी ओ आई)
1	अवतरित मूल्य	रुपये/मीट्रिक टन	2,40,358	3,78,746	1,83,266	1,41,684

124. देखा गया है कि पहले लैंडेड कीमत ज़्यादा थी और जांच की अवधि में इसमें कमी आई है। घरेलू इंडस्ट्री ने कहा है कि प्रस्तावित एंटी-डॉपिंग झूठी सहित इंपोर्ट की लैंडेड कीमत पहले की कीमतों से कम होगी। इसलिए, जब इन ज़्यादा कीमतों का यूज़र पर कोई असर नहीं पड़ा, तो एंटी-डॉपिंग झूठी लगाने से भी कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है। अथॉरिटी का मानना है कि भले ही एंटी-डॉपिंग झूठी लगाने से भारत में प्रोडक्ट की कीमत के स्तर पर असर पड़ सकता है, लेकिन ऐसे एंटी-डॉपिंग उपायों से भारतीय बाज़ार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, एंटी-डॉपिंग उपाय डॉपिंग प्रैक्टिस से मिलने वाले अनुचित फ़ायदे को कम कर सकते हैं, जिससे घरेलू इंडस्ट्री को होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा और संबंधित सामान के उपभोक्ताओं के लिए ज़्यादा विकल्प उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा, जांच में यह बात सामने नहीं आई है कि डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री लागत में बढ़ोतरी के हिसाब से अपनी कीमतें तय करने में असमर्थ रही है।

125. मांग और आपूर्ति के अंतर के कारण ज़रूरी इंपोर्ट के मामले में, रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी से पता चलता है कि घरेलू इंडस्ट्री अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रही है (काफी क्षमता खाली पड़ी है) और उसने क्षमता बढ़ाने के लिए ज़रूरी मंजूरी ले ली है। हालांकि मांग और आपूर्ति में अभी भी अंतर है, लेकिन अथॉरिटी का मानना है कि भारी नुकसान उठाने के बावजूद किसी प्रोड्यूसर से बड़े निवेश की उम्मीद नहीं की जा सकती। अथॉरिटी यह भी मानती है कि एंटी-डॉपिंग झूठी लगाने से भारत में संबंधित सामान की कमी नहीं होगी। यह ध्यान दिया गया है कि एंटी-डॉपिंग झूठी देश में इंपोर्ट पर रोक नहीं लगाती, बल्कि यह पक्का करती है कि इंपोर्ट उचित कीमतों पर उपलब्ध हों। इसलिए, झूठी लगाने से प्रोडक्ट की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अथॉरिटी का मानना है कि घरेलू बाज़ार में निवेश उचित बाज़ार सिद्धांतों के आधार पर किया गया था। जब बड़े पैमाने पर डॉपिंग हो रही हो, तो

घरेलू इंडस्ट्री का विस्तार नहीं हो सकता; साथ ही, यूज़र इंडस्ट्री ने डंप किए गए इंपोर्ट मिलने की उम्मीद में अपना कामकाज शुरू नहीं किया था।

ट. प्रकटीकरण-पश्चात् टिप्पणियाँ

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ

126. अन्य हितबद्ध पक्षों ने प्रकटीकरण विवरण पर निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:

- i. यह प्रस्तुत किया गया है कि प्राधिकरण ने संबंधित रेखा मंत्रालयों से जानकारी मांगकर घरेलू उद्योग की पात्रता (स्थिति) का स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं किया है, जो कि पिछली जांचों में अपनाई जाने वाली सुसंगत प्रथा है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि घरेलू उद्योग की पात्रता के संबंध में जानकारी सही हो और प्राधिकरण द्वारा विकृत आंकड़ों पर विचार किए जाने के किसी भी भौतिक जोखिम को रोका जा सके। विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय के निर्णय ईसी-फास्टनर्स (चीन) का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सक्षम प्राधिकरण पर यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि जिस तरह से वह घरेलू उद्योग को परिभाषित करता है, वह आर्थिक आंकड़ों को विकृत करने और परिणामस्वरूप, उद्योग की स्थिति के अपने विश्लेषण को विकृत करने का कोई भौतिक जोखिम पेश न करे।
- ii. यह प्रस्तुत किया गया है कि 'प्रमुख अनुपात' (प्रमुख अनुपात) परीक्षण पूरी तरह से गणितीय परीक्षण नहीं है और इसके मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों अर्थ हैं। एक परीक्षण जो पूरी तरह से मात्रात्मक होगा, यह आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित नहीं करेगा कि उस आधार पर परिभाषित घरेलू उद्योग कुल घरेलू उत्पादन को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित करता है। आवेदन 'प्रमुख अनुपात' परीक्षण के गुणात्मक पहलू को संतुष्ट करने में विफल रहता है क्योंकि बाजार में मौजूद स्थापित उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा गया है। विश्व व्यापार संगठन पैनल ने चीन - संयुक्त राज्य अमेरिका से ब्रायलर उत्पादों पर एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटी उपायों के मामले में कहा था कि एक जांच प्राधिकरण को अपने नुकसान के निर्धारण में अन्य घरेलू उत्पादकों की स्थिति को नजरअंदाज करने की अनुमति नहीं है।
- iii. यह प्रस्तुत किया गया है कि जापान, यूएसए और कोरिया आरपी से होने वाले आयात, जबकि व्यक्तिगत रूप से 3% की सीमा से कम हैं, सामूहिक रूप से आवेदन में दिए गए आंकड़ों के अनुसार कुल आयात के 7.28% से अधिक हैं। विश्व व्यापार संगठन एंटी-डंपिंग समझौते के अनुच्छेद 5.8 और प्रतिप्रतिषेध नियमों के नियम 14(डी) के तहत, ऐसे आयातों का सामूहिक रूप से आकलन किया जाना चाहिए था और इस जांच के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए था। इन देशों को जांच के दायरे से बाहर रखना अनिवार्य कानूनी सीमाओं की अवहेलना करता है, नुकसान के विश्लेषण को भौतिक रूप से अधूरा और त्रुटिपूर्ण बनाता है, तथा सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र उपचार खंड में निहित गैर-भेदभाव के सिद्धांत के विपरीत है।
- iv. जापान और यूएसए जैसे गैर-विषय देशों से आयात प्रतिस्पर्धी कीमतों पर किया जाता है, जो अक्सर निर्मित गैर-हानिकारक मूल्य से भी कम होता है। इन आयातों को छोड़कर, नुकसान का विश्लेषण पूरे नुकसान का भार अनुचित रूप से विषय देशों पर डालता है, जिससे एक बढ़ा हुआ क्षति मार्जिन और एक त्रुटिपूर्ण कारणात्मक संबंध बनता है। केवल विषय देशों पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने से अनिवार्य रूप से व्यापार का रुख उन बाहर किए गए देशों की ओर मुड़ जाएगा, जिससे शुल्क के सुरक्षात्मक उद्देश्य को नकार दिया जाएगा।
- v. यह प्रस्तुत किया गया है कि घरेलू उद्योग को कथित रूप से कोई भी नुकसान विषय आयातों के अलावा अन्य कारकों के कारण है। घरेलू उद्योग महत्वपूर्ण संरचनात्मक नुकसानों के साथ काम करता है, जिसमें

अपने मुख्य कच्चे माल के रूप में आयातित मोनोएथेनॉलमाइन (एमईए) पर निर्भरता, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का अभाव, महाराष्ट्र के सोलापुर में अपने स्थान के कारण उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, और अपेक्षाकृत छोटी उत्पादन क्षमता के कारण पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का अभाव शामिल है। इसके अलावा, जून 2019 में ही व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के कारण, घरेलू उद्योग को नुकसान की अवधि के दौरान अभी भी प्रारंभिक परिचालन अक्षमताओं, प्रक्रिया स्थिरीकरण के मुद्दों और उच्च उत्पादन लागतों का सामना करना पड़ रहा था। इन कारकों ने, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, घरेलू उद्योग के प्रदर्शन को भौतिक रूप से प्रभावित किया है और इसे विषय देशों से आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

- vi. यह प्रस्तुत किया गया है कि चीन पीआर से आयात में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान सात गुना से अधिक की तीव्र वृद्धि हुई है, और चीन पीआर भारत को विचाराधीन उत्पाद का सबसे बड़ा एकल निर्यातक बनकर उभरा है। चीन पीआर से आयात में उछाल के बिना, विषय देशों से कुल आयात में वास्तव में कमी आई होती। इसके विपरीत, नुकसान की अवधि के दौरान सऊदी अरब से आयात की मात्रा में कमी आई है। तदनुसार, नुकसान के विश्लेषण को विषय देशों के व्यक्तिगत योगदानों के बीच सावधानीपूर्वक अंतर करना चाहिए, और सऊदी अरब से आयात को चीन पीआर के साथ एकत्रित करने से नुकसान का गलत आरोपण होगा।
- vii. यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रकटीकरण विवरण में गैर-विषय देशों से ईडीए के आयात आंकड़ों को विषय देशों के आयात आंकड़ों में संशोधन की तुलना में काफी अधिक सीमा तक नीचे की ओर संशोधित किया गया है। इस असममित नीचे की ओर संशोधन के परिणामस्वरूप, गैर-विषय देशों से आयात का कुल आयात में हिस्सा जांच की अवधि में 7% से अधिक से घटकर 7% से कम हो गया है। इस विषम संशोधन के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह गैर-विषय देशों से आयात आंकड़ों की फिर से जांच करे क्योंकि यह मुद्दा सीधे इस निर्धारण को प्रभावित करता है कि क्या उन देशों को जांच के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए था।
- viii. यह प्रस्तुत किया गया है कि एचएस कोड 29212100 के तहत ईडीए के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क को सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 12/2026 दिनांक 1 अप्रैल 2026 के माध्यम से वापस ले लिया गया है, जाहिर तौर पर मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति और उसके परिणामी मूल्य दबावों को देखते हुए। ऐसी स्थिति में, ईडीए पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क की सिफारिश करना सीधे तौर पर इन सरकारी उपायों के अंतर्निहित नीति उद्देश्य का प्रतिकार करेगा। प्राधिकरण को ऐसे उपाय की सिफारिश नहीं करनी चाहिए जो सरकार के स्वयं के सार्वजनिक हित में किए गए टैरिफ उदारीकरण कदमों के प्रभाव को निष्क्रिय कर दे।
- ix. यह प्रस्तुत किया गया है कि भारत में ईडीए के लिए एक महत्वपूर्ण और बढ़ता हुआ मांग-आपूर्ति अंतर मौजूद है। घरेलू उद्योग की क्षमता स्पष्ट रूप से भारत की कुल मांग का आधा हिस्सा भी पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। जापान, यूएसए, कोरिया आरपी, सिंगापुर और यूएई जैसे गैर-विषय देशों से आयात पहले से ही भारतीय बाजार में विषय देशों के बराबर या उससे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर प्रवेश कर रहा है। विषय देशों से आयात पर कोई भी प्रतिबंध केवल आयात के स्रोत में बदलाव को ट्रिगर करेगा, जिससे घरेलू उद्योग को कोई स्पष्ट लाभ नहीं होगा।
- x. घरेलू उद्योग के लिए सही और स्थायी उपाय व्यापार संरक्षण में नहीं है, बल्कि मौलिक संरचनात्मक सुधार करने में है, जिसमें ऊर्ध्वाधर एकीकरण, क्षमता विस्तार और अपनी लागत संरचना को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्तर पर लाने के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं प्राप्त करना शामिल है।
- xi. यह प्रस्तुत किया गया है कि ईडीए कई आवश्यक कृषि रासायनिक उत्पादों जिनमें मैन्कोजेब शामिल है, के लिए एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। ईडीए आयातों पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने से

अनिवार्य रूप से कच्चे माल की लागत में वृद्धि होगी, जो मूल्य श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ेगी, जिससे डाउनस्ट्रीम कृषि रासायनिक सूत्रीकरणों की कीमतें बढ़ जाएंगी। इस तरह की बढ़ी हुई लागत महत्वपूर्ण फसल सुरक्षा रसायनों की कीमतों को बढ़ाकर किसानों पर सीधा बोझ डालेगी, संभावित रूप से कृषि पैदावार और किसानों की आय को कम करेगी, तथा देश के व्यापक आर्थिक और सार्वजनिक हित के उद्देश्यों के विपरीत होगी।

- xii. यह भी अनुरोध किया गया है कि आयात डेटा उसी प्रारूप और तरीके में प्रदान किया जाए, जिसमें इसे जांच के उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड पर लिया गया था, जो माननीय सीईएसटीएटी के निर्णय एक्सोटिक डेकोर प्रा. लि. बनाम नामित प्राधिकरण (प्रतिप्रतिषेध अपील संख्या 52233/2018) दिनांक 12 जून 2020 के अनुरूप है।
- xiii. यदि प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाना उचित है, तो यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसा शुल्क केवल दो (2) वर्षों की सीमित अवधि के लिए अनुशंसित किया जाना चाहिए, ताकि एक अनुचित उपाय अनावश्यक रूप से लंबी अवधि के लिए लागू न रहे।
- xiv. यह प्रस्तुत किया गया है कि प्राधिकरण ने 'ऑफ-ग्रेड गुणवत्ता' और 'पर्याप्त मात्रा में नहीं' के आधार पर एक उत्पादक के एकमात्र घरेलू बिक्री लेनदेन को अनुचित रूप से खारिज कर दिया, बिना एंटी-डंपिंग समझौते के अनुच्छेद 2.2 और नियमों के नियम 10 के तहत आवश्यक विश्लेषण किए। किसी उत्पाद को 'ऑफ-ग्रेड' के रूप में वर्गीकृत करना, बिना आगे की जांच के, उसे व्यापार के सामान्य क्रम के बाहर नहीं रखता है।
- xv. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सऊदी अरब से आयात जांच की अवधि के दौरान 20% से अधिक घट गया, और जब सऊदी आयात की मात्रा अधिक थी, तब घरेलू उद्योग लाभदायक था, जो किसी भी कारणात्मक संबंध को नकारता है। डीजीटीआर ने निम्नलिखित के संबंध में एंटी-डंपिंग समझौते के अनुच्छेद 3.5 के तहत उचित गैर-आरोपण विश्लेषण करने में विफलता दिखाई है: (क) घरेलू उद्योग के निर्यात प्रदर्शन में 92% की गिरावट; (ख) एमईए की कीमतों में उतार-चढ़ाव; तथा (ग) 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किए गए भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और जलवायु परिवर्तन। तदनुसार, जांच को जहां तक यह सऊदी अरब से संबंधित है, समाप्त किया जाना चाहिए।
- xvi. कुछ डाउनस्ट्रीम आयातकों/उपयोगकर्ताओं द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि सामूहिक मूल्यांकन अनुपयुक्त है क्योंकि विभिन्न विषय देशों से आयात विभिन्न शर्तों के तहत, विभिन्न मूल्य स्तरों पर, विभिन्न व्यापार चैनलों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- xvii. लगभग 10-11% का भारित औसत मूल्य अंडरकटिंग नाममात्र है और यह महत्वपूर्ण मूल्य क्षति का प्रमाण नहीं है। मूल्य में गिरावट कोविड-19 के बाद वैश्विक ईडीए कीमतों में व्यापक सुधार के साथ मेल खाती है।
- xviii. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने रोजगार (44% की वृद्धि), प्रति दिन उत्पादकता (11% की वृद्धि), और कुल मजदूरी (141% की वृद्धि) में सकारात्मक रुझान दिखाया, जो भौतिक क्षति के निष्कर्ष के अनुरूप नहीं हैं।
- xix. मैन्कोजेब पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क का प्रभाव विश्लेषण गलत उपभोग मान्यताओं पर आधारित है। सत्यापित उत्पादन अभिलेख विभिन्न वास्तविक उपभोग अनुपात दिखाते हैं। 20-30% का प्रतिप्रतिषेध शुल्क कम मार्जिन वाले उद्योगों में लाभप्रदता को नष्ट कर देगा।

- xx. प्रतिप्रतिषेध शुल्क के आरोपण से आपूर्ति की कमी पैदा होगी और एकमात्र घरेलू उत्पादक को अनुचित मूल्य निर्धारण शक्ति प्रदान होगी, जिससे एक एकाधिकारी परिणाम का जोखिम होगा, मुद्रास्फीति संबंधी प्रभाव होंगे तथा भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर होगी।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

127. घरेलू उद्योग ने प्रकटीकरण विवरण पर निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:

- i. कि प्राधिकरण ने प्रकटीकरण विवरण में स्पैन्डेक्स यार्न के उत्पादन में प्रयुक्त एथिलीन डायमीन को बाहर नहीं करने का प्रस्ताव सही रूप से दिया है। अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा भरोसा किए गए विनिर्देश 2020-21 में उन्हें दिए गए नमूने पर आधारित थे। 2020-21 के बाद, घरेलू उद्योग ने तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास प्रयास किए हैं, और उत्पाद अब स्पैन्डेक्स के अन्य उत्पादकों को आपूर्ति किया जा रहा है। घरेलू उद्योग का उत्पाद दिखावट, रंग, जल सामग्री, शुद्धता और कार्बनिक अशुद्धता सहित सभी निर्दिष्ट मानकों को पूरा करता है, और बिना किसी नई मशीनरी के ग्राहक की आवश्यकताओं के आधार पर विनिर्देशों को संशोधित किया जा सकता है। उन्होंने प्राधिकरण से प्रकटीकरण विवरण में प्रस्तावित अनुसार विचाराधीन उत्पाद के दायरे की पुष्टि करने का भी अनुरोध किया है।
- ii. कि प्राधिकरण को अंतिम निष्कर्षों में पुष्टि करनी चाहिए कि विषय देशों से डंपित आयातों ने घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति पहुंचाई है।
- iii. कि ग्राहकों ने अपनी खरीदारी को तेजी से विषय देशों से उत्पन्न आयातित वस्तुओं की ओर स्थानांतरित कर दिया है, क्योंकि उनकी कीमतें कम हैं। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य आगे यह प्रदर्शित करते हैं कि वाणिज्यिक बातचीत के दौरान ग्राहकों द्वारा आयात कीमतों को नियमित रूप से बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है, जो बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए घरेलू उद्योग की कीमतों पर महत्वपूर्ण नीचे की ओर दबाव डालता है।
- iv. कि प्राधिकरण ने सही रूप से नोट किया है कि जापान, कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात सामूहिक रूप से कुल आयात का 6% से भी कम है और इसलिए, इसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान देने वाला कारक नहीं माना जा सकता है। प्राधिकरण ने आगे पाया है कि किसी अन्य ज्ञात कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है। इन परिस्थितियों में, घरेलू उद्योग ने दोहराया कि हुई क्षति पूरी तरह से विषय देशों से डंपित आयातों के कारण है, और कम कीमत वाले डंपित आयातों में उछाल और घरेलू उद्योग के मात्रा, मूल्य और वित्तीय प्रदर्शन मानकों में गिरावट के बीच एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष कारणात्मक संबंध मौजूद है।
- v. कि उपयोगकर्ता पिछले वर्षों में काफी अधिक कीमतों पर आयातित उत्पाद खरीद रहे थे। चूंकि जांच की अवधि में कीमतों में तेजी से गिरावट आई है, इसलिए समान प्रतिस्पर्धी स्तर बहाल करने वाले प्रतिप्रतिषेध शुल्क के आरोपण का डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं पर कोई भौतिक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि ईडीए डाउनस्ट्रीम उत्पादों की लागत का केवल एक छोटा सा हिस्सा बनाता है - एपाँक्सी क्योरिंग एजेंटों के लिए लगभग 30%, मैन्कोजेब के लिए 15%, और इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के लिए 1% से भी कम - जिसका अंतिम उत्पादों की कीमत पर तदनु रूप सीमित प्रभाव पड़ता है। 20% की काल्पनिक शुल्क का अंतिम उत्पाद की कीमत पर प्रभाव 0.18% से 5.96% तक है, जो नगण्य है।
- vi. प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने से विषय देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होगा, बल्कि यह सुनिश्चित होगा कि आयात उचित कीमतों पर उपलब्ध हों। इससे भारत में विषय वस्तुओं की कमी नहीं होगी। घरेलू उद्योग

से महत्वपूर्ण डंपिंग के सामने अपनी क्षमता बढ़ाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, और उपयोगकर्ता उद्योग ने डंपित आयातों तक निरंतर पहुंच की उम्मीद में अपने परिचालन स्थापित नहीं किए थे।

- vii. घरेलू उद्योग भारत में ईडीए का एकमात्र उत्पादक है और उत्पाद की डंपिंग ने अन्य संभावित उत्पादकों को क्षमताएं स्थापित करने से हतोत्साहित किया है। यदि प्रतिप्रतिषेध शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो संयंत्र बंद होने का वास्तविक जोखिम है, जो रोजगार, आजीविका और सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के उद्देश्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।
- viii. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षमता बढ़ाकर 37,350 मीट्रिक टन करने की मंजूरी प्राप्त कर ली है। पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग को अपने नुकसान से उबरने, क्षमता विस्तार करने और आगे और निवेश करने के लिए आवश्यक स्थिरता और वित्तीय सहायता मिलेगी।
- ix. घरेलू उद्योग प्राधिकरण से अनुरोध करता है कि वह पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने की सिफारिश करे। जब तक शुल्क पांच वर्षों के लिए नहीं लगाया जाता, तब तक घरेलू उद्योग डंपित आयातों के परिणामस्वरूप हुई महत्वपूर्ण क्षति से पर्याप्त रूप से उबर नहीं पाएगा। घरेलू उद्योग के निदेशक मंडल ने डंपित आयातों के कारण हुए नुकसान के कारण प्रस्तावित क्षमता विस्तार निवेश को मंजूरी देने में अनिच्छा दिखाई है, और पांच वर्षों के लिए प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने से ऐसे निवेश के लिए आवश्यक स्थिरता मिलेगी।

ट.3 प्राधिकरण द्वारा परीक्षण

128. प्राधिकरण ने हितबद्ध पक्षों द्वारा की गई प्रकटीकरण-पश्चात् प्रस्तुतियों का परीक्षण किया है। यह देखा गया है कि इनमें से अधिकांश प्रस्तुतियाँ पहले से ही परीक्षण किए गए तर्कों और दावों की पुनरावृत्ति हैं और इसलिए इन्हें इन अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैराग्राफों में आवश्यक समझे जाने तक संबोधित किया गया है। संक्षिप्तता के लिए, प्राधिकरण ने इस प्रकटीकरण-पश्चात् परीक्षण में ऐसे मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं को दोहराने से परहेज किया है। हालाँकि, प्रकटीकरण-पश्चात् प्रस्तुतियों में पहली बार उठाए गए किसी भी नए मुद्दे, साथ ही पहले संबोधित किए गए लेकिन आगे परीक्षण करना आवश्यक समझे गए मुद्दों को यहाँ संबोधित किया गया है।
129. प्राधिकरण प्रकटीकरण विवरण में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के दायरे और घरेलू उद्योग के रूप में आवेदक की पात्रता की पुष्टि करता है।
130. प्राधिकरण ने सामान्य मूल्य, शुद्ध निर्यात मूल्य, लैंडेड मूल्य और गैर-हानिकारक मूल्य के प्रस्तावित निर्धारणों के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षों को प्रकटीकरण की गोपनीय प्रति जारी की। प्रकटीकरण विवरण जारी करने के बाद किसी भी हितबद्ध पक्ष से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है; इसलिए, प्राधिकरण विषय देशों के विभिन्न उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्धारित डंपिंग मार्जिन की पुष्टि करता है।
131. जापान, यूएसए और कोरिया आरपी से आयात के संबंध में प्रस्तुति पर, प्राधिकरण ने डीजी सिस्टम से सत्यापित लेन-देन-वार आयात आंकड़ों की जांच की है और नोट किया है कि जांच की अवधि के दौरान इन देशों से आयात सामूहिक रूप से कुल आयात का 6% से भी कम है। कम मात्रा वाले स्रोत देशों को शामिल करने के लिए नियमों के नियम 14(डी) के तहत निर्धारित 7% की सीमा पूरी नहीं हुई है। वर्तमान जांच के दायरे में इन देशों को शामिल करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।
132. इस दावे पर कि प्रकटीकरण विवरण में गैर-विषय देशों के आयात आंकड़ों में नीचे की ओर संशोधन असममित था, प्राधिकरण स्पष्ट करता है कि संशोधन सभी स्रोत देशों के आंकड़ों पर समान रूप से लागू होता है और यह सत्यापन अभ्यास का परिणाम है जो दोहराव, गलत-कोडित लेनदेन और गैर-ईडीए प्रविष्टियों को हटा देता है। यह आरोप किसी भी विशिष्ट लेन-देन-स्तरीय साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

133. कारणात्मक संबंध पर प्रस्तुतियों के संबंध में, प्राधिकरण ने देखा है कि जिन स्थितियों को अब डंपित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को तोड़ने वाला बताया गया है, जैसे आयातित कच्चे माल पर निर्भरता, कैप्टिव उत्पादन या बैकवर्ड इंटीग्रेशन का अभाव, स्थान संबंधी नुकसान, और अन्य संरचनात्मक विशेषताएं, पूरी क्षति अवधि के दौरान मौजूद थीं और उन वर्षों के बीच अपरिवर्तित रहीं जब घरेलू उद्योग लाभ कमा रहा था और जांच की अवधि जब उसे नुकसान हुआ। इन्हीं स्थितियों के बावजूद घरेलू उद्योग 2021-22 और 2022-23 में लाभदायक था। तदनुसार, ऐसे कारकों को घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट का कारण नहीं माना जा सकता है। जांच की अवधि के दौरान एकमात्र भौतिक परिवर्तन हानिकारक कीमतों पर डंपित आयातों में पर्याप्त वृद्धि थी, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण मूल्य दमन और अवसाद हुआ। इसलिए, घरेलू उद्योग को हुई क्षति स्पष्ट रूप से विषय देशों से डंपित आयातों के कारण है, न कि हितबद्ध पक्षों द्वारा उद्धृत संरचनात्मक विशेषताओं के कारण।
134. प्राधिकरण ने विषय देशों से आयातों का सामूहिक मूल्यांकन किया है, क्योंकि नियमों के अनुलग्नक II के तहत निर्धारित सभी शर्तें पूरी होती हैं। प्रत्येक विषय देश से डंपिंग मार्जिन और आयात मात्रा निर्धारित सीमाओं से अधिक हैं, और प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ सामूहिक मूल्यांकन को उचित ठहराती हैं। किसी विशेष विषय देश से आयात में मात्र गिरावट उसे सामूहिक क्षति विश्लेषण में शामिल करने में बाधा नहीं डालती है।
135. प्राधिकरण देखता है कि अधिसूचना संख्या 12/2026-सीमा शुल्क के तहत बुनियादी सीमा शुल्क की वापसी और प्रतिप्रतिषेध शुल्क का आरोपण विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत काम करते हैं। इसलिए, बुनियादी सीमा शुल्क की वापसी प्राधिकरण को प्रतिप्रतिषेध शुल्क की सिफारिश करने से नहीं रोकती है, जहाँ डंपित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं।
136. व्यापारिक मोड़ (ट्रेड डायवर्जन) के संबंध में प्रस्तुति के संबंध में, प्राधिकरण देखता है कि प्रतिप्रतिषेध शुल्क आयात को प्रतिबंधित या निषेधित नहीं करता है, यह केवल भारतीय बाजार में समान प्रतिस्पर्धी स्तर सुनिश्चित करता है। व्यापारिक मोड़ की संभावना अनुमानित है और सिद्ध डंपिंग और क्षति को संबोधित करने से इनकार करने का आधार नहीं है।
137. डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रभाव के संबंध में, प्राधिकरण ने देखा है कि ईडीए डाउनस्ट्रीम उत्पादों की लागत का केवल एक छोटा सा अनुपात बनाता है, और 20% की काल्पनिक प्रतिप्रतिषेध शुल्क पर भी, तैयार उत्पादों की कीमतों पर प्रभाव न्यूनतम होगा। प्राधिकरण ने आगे कहा कि किसी भी डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ता ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि इस तरह की वृद्धि उसके परिचालन को अव्यवहारिक बना देगी। इसके अलावा, 2022-23 के दौरान डाउनस्ट्रीम उद्योग लाभदायक बना रहा, जब ईडीए आयात की कीमतें वर्तमान स्तरों से काफी अधिक थीं। तदनुसार, प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने का डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई भौतिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
138. मांग-आपूर्ति अंतर के संबंध में, यह नोट किया गया है कि प्रतिप्रतिषेध शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है, बल्कि केवल घरेलू उत्पादकों और आयातित उत्पादों के बीच समान प्रतिस्पर्धी स्तर सुनिश्चित करता है। चूंकि घरेलू उद्योग वर्तमान में अपनी स्थापित क्षमता के केवल 36% पर काम कर रहा है और उसके पास आगे विस्तार के लिए आवश्यक मंजूरी है, इसलिए मांग-आपूर्ति अंतर विषय देशों से निरंतर डंपित आयातों का आधार नहीं हो सकता है। क्षमता का कम उपयोग मुख्य रूप से कम कीमत वाले डंपित आयातों की उपस्थिति के कारण है, और इसलिए, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बहाल करने और घरेलू उद्योग को उत्पादन बढ़ाने और क्षमता विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाना आवश्यक है।
139. प्राधिकरण हितबद्ध पक्षों द्वारा आयात आंकड़ों के प्रकटीकरण और माननीय सीईएसटीएटी के निर्णय एक्सोटिक डेकोर पर निर्भरता के संबंध में की गई प्रस्तुतियों को नोट करता है। हालाँकि, प्राधिकरण नोट करता है कि डीजी सिस्टम से प्राप्त आयात जानकारी को नियमों के नियम 7 में निहित गोपनीयता प्रावधानों के अनुसार माना जाता है।

हालाँकि, प्राधिकरण ने वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए अपनाई गई आयात मात्रा, लैंडेड मूल्यों, रुझानों और कार्यप्रणाली सहित विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों का खुलासा किया है। हितबद्ध पक्षों को सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण करने और प्राधिकरण द्वारा भरोसा की गई जानकारी पर टिप्पणी करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। प्राधिकरण इसलिए संतुष्ट है कि प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताओं और नियमों के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया है।

140. प्रतिप्रतिषेध शुल्क की अवधि के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ए(5) पाँच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने का प्रावधान करती है, जो कि प्रतिप्रतिषेध जांचों में अपनाई जाने वाली मानक अवधि है। प्राधिकरण आगे नोट करता है कि किसी भी हितबद्ध पक्ष ने मानक पाँच-वर्षीय अवधि से विचलित होने और उपाय को दो वर्षों तक सीमित करने के लिए कोई ठोस कारण या असाधारण परिस्थितियाँ प्रदान नहीं की हैं। घरेलू उद्योग द्वारा सहन की जा रही निरंतर भौतिक क्षति और छोटी अवधि के लिए किसी औचित्य की अनुपस्थिति को देखते हुए, प्राधिकरण को दो-वर्षीय शुल्क अवधि की मांग करने वाली प्रस्तुतियों में कोई दम नहीं दिखता है और वह पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।
141. निर्यात प्रदर्शन पर, प्राधिकरण ने इस प्रस्तुति की जांच की है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री में 92% की गिरावट स्वयं वैश्विक रूप से दबी हुई मूल्य वातावरण का परिणाम है जिसमें डंपित आयातों ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। जब घरेलू उद्योग हानिकारक कीमत वाले आयातों के कारण घरेलू बाजार में लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में असमर्थ होता है, तो निर्यात बाजारों में उसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति एक साथ कमजोर हो जाती है। तदनुसार, निर्यात प्रदर्शन में गिरावट क्षति का एक स्वतंत्र कारण नहीं है - यह डंपित आयातों के कारण हुई उसी क्षति का एक लक्षण है। इस कारक को क्षति के गैर-डंपिंग कारण के रूप में आरोपित नहीं किया जा सकता है।
142. इसके अलावा, 15 मीट्रिक टन का एकल घरेलू लेनदेन, सदारा के उत्पादन और भारत को उसके निर्यात के पैमाने के मुकाबले विचार करने पर, एक प्रतिनिधि घरेलू बाजार मूल्य स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीमा को पूरा नहीं करता है। अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास और अनुच्छेद 2.2 का पाठ दोनों ही मान्यता देते हैं कि घरेलू बिक्री को अनदेखा किया जा सकता है जहाँ मात्रा उचित तुलना की अनुमति देने के लिए अपर्याप्त है। दोनों स्वतंत्र आधार - ऑफ-ग्रेड गुणवत्ता और अपर्याप्त मात्रा - अलग-अलग सामान्य मूल्य के निर्माण को उचित ठहराते हैं। प्रकटीकरण विवरण में निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है।
143. मूल्य अंडरकटिंग और मूल्य प्रभावों पर, प्राधिकरण अंतिम निष्कर्ष में निर्धारित मूल्य प्रभावों पर अपने निष्कर्षों की पुष्टि करता है। आयात की कीमतों में क्षति अवधि के दौरान लगभग 41% की गिरावट आई, जबकि कच्चे माल की कीमतों में केवल 17% की गिरावट आई। यह असमानुपातिक गिरावट स्थापित करती है कि आयात की कीमतों ने केवल फीडस्टॉक लागत आंदोलनों का अनुसरण नहीं किया है। विषय देशों में मूल्य अंडरकटिंग 7% से 16% तक है, जिसका भारत औसत 11% है। एक पतले मार्जिन वाले उद्योग के संदर्भ में, जहाँ जांच की अवधि के दौरान आयात की कीमतें घरेलू उद्योग की परिवर्तनीय उत्पादन लागत से भी नीचे गिर गईं, अंडरकटिंग का यह स्तर हानिकारक है। यह प्रस्तुति कि 10-11% अंडरकटिंग 'नाममात्र' है, स्वीकार नहीं की जाती है।
144. प्राधिकरण स्वीकार करता है कि जांच की अवधि के दौरान रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी ने सकारात्मक रुझान दिखाया है। हालाँकि, नियम 11 के साथ नियमों के अनुलग्नक II के तहत क्षति निर्धारण के लिए सभी प्रासंगिक आर्थिक संकेतकों की समग्र जांच की आवश्यकता होती है। रोजगार और मजदूरी में सकारात्मक गतिविधि उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में तीव्र गिरावट से कहीं अधिक है - ये सभी प्रमुख संकेतक हैं। घरेलू उद्योग ने गंभीर वित्तीय नुकसान को अवशोषित करते हुए अपने कार्यबल का विस्तार किया है, जो क्षति की अनुपस्थिति के बजाय क्षति के बावजूद लचीलापन प्रदर्शित करता है।

145. डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रभाव के संबंध में, प्राधिकरण ने देखा है कि ईडीए डाउनस्ट्रीम उत्पादों की लागत का केवल एक छोटा सा अनुपात बनाता है, और 20% की काल्पनिक प्रतिप्रतिषेध शुल्क पर भी, तैयार उत्पादों की कीमतों पर प्रभाव न्यूनतम होगा। प्राधिकरण ने आगे कहा कि किसी भी डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ता ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि इस तरह की वृद्धि उसके परिचालन को अव्यवहारिक बना देगी। इसके अलावा, 2022-23 के दौरान डाउनस्ट्रीम उद्योग लाभदायक बना रहा, जब ईडीए आयात की कीमतें वर्तमान स्तरों से काफी अधिक थीं। तदनुसार, प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने का डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई भौतिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
146. प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग का प्रति 1,000 किग्रा मैन्कोजेब में 250 किग्रा ईडीए का अनुमान असत्यापित है, और उसने उपयोगकर्ताओं के उपभोग डेटा को सत्यापन योग्य सीमा तक ध्यान में रखा है। उपयोगकर्ताओं द्वारा दावा किए गए उच्च ईडीए अनुपात पर भी, ईडीए मैन्कोजेब की उत्पादन लागत का केवल एक सीमित अनुपात बनाता है, और अनुशंसित स्तर पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क का प्रभाव भौतिक नहीं है। 2022-23 के दौरान डाउनस्ट्रीम उद्योग लाभदायक बना रहा, जब आयातित ईडीए की लैंडेड कीमतें काफी अधिक थीं, प्राधिकरण का मानना है कि यह शुल्क के कारण उचित मूल्य सुधार को अवशोषित कर सकता है, और प्रतिकूल डाउनस्ट्रीम प्रभाव की आशंका सिद्ध नहीं है।
147. एकाधिकार जोखिम और आपूर्ति उपलब्धता पर, प्रतिप्रतिषेध शुल्क आयात को प्रतिबंधित या निषेधित नहीं करता है - यह केवल यह सुनिश्चित करता है कि आयात भारतीय बाजार में उचित, गैर-हानिकारक कीमतों पर प्रवेश करें। घरेलू उद्योग वर्तमान में अपनी स्थापित क्षमता के केवल 36% पर काम कर रहा है और उसके पास 37,350 मीट्रिक टन तक आगे क्षमता विस्तार के लिए आवश्यक मंजूरी है। प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग के लिए उत्पादन बढ़ाने, क्षमता विस्तार करने और घरेलू मांग के एक बड़े हिस्से की पूर्ति करने की स्थितियाँ पैदा होंगी। इस दावे का कोई आधार नहीं है कि प्रतिप्रतिषेध शुल्क से आपूर्ति की कमी या एकाधिकारी मूल्य निर्धारण होगा।

ठ. निष्कर्ष

148. हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए दावों, प्रदान की गई जानकारी और की गई प्रस्तुतियों तथा प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उपरोक्त निष्कर्षों में दर्ज है, और डंपिंग, क्षति और घरेलू उद्योग से कारणात्मक संबंध के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण निम्नलिखित निष्कर्ष निकालता है:

क. विचाराधीन उत्पाद एवं समरूप वस्तु के दायरे पर

- वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'एथिलीन डायमाइन' है, जिसे संक्षेप में "ईडीए" कहा जाता है।
- घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तु तथा विषय देशों से निर्यातित विषय वस्तुएं, नियमों के नियम 2(घ) के अर्थ में एक-दूसरे की समरूप वस्तुएं हैं।

ख. घरेलू उद्योग एवं पात्रता पर

- आवेदक एकमात्र उत्पादक है जिसने जांच की अवधि के दौरान उत्पाद का उत्पादन किया है।
- बालाजी स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड, नियम 2(ख) के अर्थ में एक पात्र घरेलू उद्योग है तथा नियमों के नियम 5(3) के संदर्भ में पात्रता की कसौटी को पूरा करता है।

ग. सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य पर

- चीन पीआर, यूरोपीय संघ और सऊदी अरब के उत्पादकों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है। ताइवान से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

- ii. चीन पीआर को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है, क्योंकि चीन पीआर के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 8 में उल्लिखित इस धारणा का खंडन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं।
- iii. चीन पीआर, यूरोपीय संघ और सऊदी अरब के उत्पादकों द्वारा दाखिल प्रतिक्रिया से पता चलता है कि उत्पाद का निर्यात भारत को डंपित कीमतों पर किया गया है।
- iv. प्रत्येक विषय देश से विचाराधीन उत्पाद के लिए डंपिंग मार्जिन डी-मिनिमस से अधिक पाया गया है।

घ. क्षति एवं कारणात्मक संबंध पर

- i. विषय देशों से आयात में निरपेक्ष एवं सापेक्ष दोनों रूपों में वृद्धि हुई है।
- ii. जबकि आधार वर्ष की तुलना में कच्चे माल की कीमतों में 17 सूचकांक अंकों की गिरावट आई है, आयात मूल्य में 38 सूचकांक अंकों की गिरावट आई है।
- iii. विषय आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को अंडरकट कर रहे हैं, और मूल्य अंडरकटिंग सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण है।
- iv. जांच की अवधि में आयातों की लैंडेड कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतें अवसादित रहीं।
- v. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग घटा। घरेलू उद्योग ने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए नुकसान पर बिक्री की है।
- vi. प्रति इकाई लाभ ₹66,592 प्रति मीट्रिक टन से घटकर ₹19,943 प्रति मीट्रिक टन का नुकसान हो गया है। घरेलू उद्योग का नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल इसी प्रकार 2022-23 में घटा और उसके बाद जांच की अवधि में ऋणात्मक हो गया।
- vii. डंपित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।
- viii. जांच से विषय देशों से डंपिंग के अलावा कोई अन्य कारक सामने नहीं आया, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची हो।

ङ. भारतीय उद्योग के हित पर

- i. घरेलू उद्योग भौतिक क्षति सहन कर रहा है, तथा प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाना घरेलू उत्पादक के हित में होगा।
- ii. शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं होगा।

ड. सिफारिशें

149. प्राधिकरण नोट करता है कि जांच प्रारंभ की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षों को सूचित किया गया था तथा डंपिंग, क्षति, कारणात्मक संबंध और अनुशंसित उपायों के प्रभाव के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने का घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। प्रतिप्रतिषेध नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार डंपिंग, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच प्रारंभ और संचालित करने के बाद, प्राधिकरण की राय है कि डंपिंग और क्षति की भरपाई के लिए प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाना आवश्यक है। प्राधिकरण इसे आवश्यक मानता है तथा विषय देशों से विषय वस्तुओं के आयात पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।
150. अनुसरण किए गए अल्पतरु शुल्क नियम (लेसर ड्यूटी रूल) को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण विषय देशों में उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित विषय वस्तुओं के आयात पर, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए, डंपिंग

मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम के बराबर अंतिम प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। तदनुसार, प्राधिकरण इसे आवश्यक मानता है तथा केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए, विषय देशों में उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित विषय वस्तुओं के आयात पर, नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्षक (HS Code)	विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई (मापन इकाई)	मुद्रा
1	29212100	एथिलीन डायमाइन	चीन	चीन सहित कोई भी देश	बीएसएफ-वाईपीसी कंपनी लिमिटेड	350	मीट्रिक टन (एम टी)	अमेरिकी डॉलर (\$)
2	-do-	-do-	चीन	चीन सहित कोई भी देश	क्र. सं. 1 में उल्लिखित उत्पादक के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	575	मीट्रिक टन (एम टी)	अमेरिकी डॉलर (\$)
3	-do-	-do-	चीन, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब और ताइवान के अतिरिक्त कोई भी देश	चीन	कोई भी उत्पादक	575	मीट्रिक टन (एम टी)	अमेरिकी डॉलर (\$)
4	-do-	-do-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई भी देश	बीएसएफ एंटरप्रेन एनवी	464	मीट्रिक टन (एम टी)	अमेरिकी डॉलर (\$)
5	-do-	-do-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई भी देश	क्र. सं. 4 में उल्लिखित उत्पादक के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	739	मीट्रिक टन (एम टी)	अमेरिकी डॉलर (\$)
6	-do-	-do-	चीन, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब और ताइवान के अतिरिक्त कोई भी देश	यूरोपीय संघ	कोई भी उत्पादक	739	मीट्रिक टन (एम टी)	अमेरिकी डॉलर (\$)

7	-do-	-do-	सऊदी अरब	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	सदारा केमिकल कंपनी	230	मीट्रिक टन (एम टी)	अमेरिकी डॉलर (\$)
8	-do-	-do-	सऊदी अरब	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	क्र. सं. 7 में उल्लिखित उत्पादक के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	375	मीट्रिक टन (एम टी)	अमेरिकी डॉलर (\$)
9	-do-	-do-	चीन, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब और ताइवान के अतिरिक्त कोई भी देश	सऊदी अरब	कोई भी उत्पादक	375	मीट्रिक टन (एम टी)	अमेरिकी डॉलर (\$)
10	-do-	-do-	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	301	मीट्रिक टन (एम टी)	अमेरिकी डॉलर (\$)
11	-do-	-do-	चीन, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब और ताइवान के अतिरिक्त कोई भी देश	ताइवान	कोई भी उत्पादक	301	मीट्रिक टन (एम टी)	अमेरिकी डॉलर (\$)

नोट 1 - ऊपर उल्लिखित सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है।

नोट 2 - उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित उत्पादकों के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का आवेदन सीमा शुल्क प्राधिकारियों को एक वैध वाणिज्यिक चालान प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन होगा। उक्त चालान पर चालान जारी करने वाली इकाई के किसी अधिकारी द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित एक घोषणा अंकित होनी चाहिए, जिसमें अधिकारी का नाम और पदनाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो। घोषणा निम्नानुसार होगी:

“मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस चालान के अंतर्गत भारत को निर्यात हेतु बेची गई एथिलीन डायमाइन, जिसे संक्षेप में ‘EDA’ कहा जाता है, की (मात्रा) का निर्माण (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा [संबंधित देश] में किया गया है। मैं घोषित करता/करती हूँ कि इस चालान में दी गई जानकारी पूर्ण एवं सही है।”

यदि ऐसा कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क दर लागू होगी। यह आवश्यकता लागू सीमा शुल्क कानूनों और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं करेगी।

ढ. आगे की प्रक्रिया

151. इस अंतिम निष्कर्ष से उत्पन्न प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार ,निर्दिष्ट प्राधिकरण

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

[DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES]

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2026

FINAL FINDINGS

Case No. AD (OI)- 05/2025

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Ethylene Diamine” originating in or exported from People’s Republic of China (“China PR”), European Union, Kingdom of Saudi Arabia and Taiwan.

F. No. 6/05/2025-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Anti-Dumping Rules” or “Rules”) thereof,

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Balaji Speciality Chemicals Limited (hereinafter referred to as the “applicant” filed an application, before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the Anti-Dumping Rules for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of ‘Ethylene Diamine’ (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods” or “EDA”) from the People’s Republic of China (“China PR”), European Union, Kingdom of Saudi Arabia and Taiwan (hereinafter referred to as the “subject countries”).
2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicant, the Authority issued a public notice *vide* Notification F. No. 6/05/2025-DGTR, dated 25th March, 2025, published in the Gazette of India, initiating anti-dumping investigation into imports of the product under consideration from China PR, European Union, Saudi Arabia and Taiwan in accordance with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the product under consideration and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

3.1 **Initiation**

- i. In accordance with Rule 5(5), the Authority notified the embassy of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation.

- ii. Upon examination of the application, the Authority found *prima facie* evidence of dumping and consequent injury. Therefore, in accordance with Rules 5 and 6, *vide* Notification F. No. 6/05/2025-DGTR dated 25th March, 2025, the Authority initiated the present proceedings.
- iii. The period of investigation (POI) was considered as 1st October, 2023 to 30th September, 2024 (12 months). The injury period was set to cover the period 1st April, 2021 to 31st March, 2022, 1st April, 2022 to 31st March, 2023, 1st April, 2023 to 31st March, 2024 and the period of investigation.
- iv. A request was made to the Directorate General for Systems and Data Management (“DG Systems”) for transaction-wise import data of the product under consideration for the injury period. The Authority received the data and has relied upon this data for the necessary analysis after due examination of the transactions.

3.2 Circulation of non-confidential version of the application

- v. In accordance with Rule 6(2), the Authority informed the interested parties of the initiation of investigation by sharing a copy of the initiation notification with the embassy of the subject country in India, known producers and exporters of the product under consideration in the subject country, known importers of the subject goods in India and other interested parties, as per the information made available in the application.
- vi. In accordance with Rule 6(3), the Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the government of the subject country through their embassy in India, known exporters of the subject imports and to other interested parties who requested in writing for a copy of the application.
- vii. The Authority sent questionnaire to the government of the subject countries through their embassy in India. The government of the subject country was requested to forward the initiation notification and the questionnaires to the producers of the product under consideration in their country and advise them to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- viii. The Authority sent exporter questionnaires to the following known producers/exporters of the subject goods calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
- ix. The Authority sent importer questionnaires to the known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

3.3 Participation by exporters of subject countries and importers/users from India

- x. The following producers and exporters have registered themselves as interested parties in the present investigation:

S. No.	Name of interested party
a.	M/s BASF Antwerpen NV, Belgium
b.	M/s BASF EOOD, Bulgaria
c.	M/s BASF Espanola SLU, Spain
d.	M/s BASF France S.A.S., France
e.	M/s BASF Hong Kong Ltd., Hongkong
f.	M/s BASF Hungaria Kft., Hungary
g.	M/s BASF-YPC Company Limited, China PR
h.	M/s BASF Ireland DAC, Ireland
i.	M/s BASF Italia S.p.A., Italy
j.	M/s BASF Nederland B.V., Netherlands
k.	M/s BASF SE, Germany
l.	M/s BASF spol s.r.o., Czech Republic
m.	M/s BASF India Limited
n.	M/s Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited, Dubai Branch, UAE
o.	M/s Dow Saudi Arabia Product Marketing Arabia B.V. Dubai Branch, UAE

p.	M/s Dow Chemical International Private Ltd, Dubai Branch, UAE
q.	M/s Sadara Chemical Company, Kingdom of Saudi Arabia
r.	BASF Belgium Coordination Centre, Belgium
s.	BASF Oy, Finland
t.	BASF SRL, Romania

- xi. In response to the initiation of the subject investigation, the following importers/users have registered themselves as interested parties in the investigation.

S. No.	Name of interested party
a.	M/s Cardolite Specialty Chemicals India LLP
b.	M/s Coromandel International Limited (CIL)
c.	M/s Dow Chemical International Private Limited (DCIPL)
d.	M/s Indorama Industries Pvt. Ltd
e.	M/s Hyosung India Pvt. Ltd.
f.	M/s Indofil Industries Limited

- xii. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire (EIQ) to assess public interest and impact of the duties on the wider economy. A copy of the EIQ was sent to the embassy of the subject country, all the known exporters, importers and users and the applicant. The EIQ was also shared with the administrative line ministry. The following interested parties have filed submissions:

S. No.	Name of interested party
a.	Balaji Speciality Chemicals Limited
b.	Coromandel International Limited
c.	Cardolite Specialty Chemicals India LLP

- xiii. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of all their submissions in the present proceedings with all other interested parties.

3.4 Further procedures

- xiv. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 7th October 2025. Subsequently, due to change in the Designated Authority, another oral hearing was held on 18th December 2025. The parties presenting their views in both the oral hearings were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions. In accordance with the accepted practice of the Authority, non-confidential versions of the rejoinder submissions by the parties were not circulated.
- xv. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings based on the facts available.
- xvi. In accordance with Rule 7, information provided by the interested parties on a confidential basis was examined by the Authority with regard to the sufficiency of the confidentiality claimed. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide a non-confidential summary of the information filed on confidential basis.
- xvii. In accordance with Rule 8, the Authority conducted verification of the data provided by the applicant and other interested parties to the extent considered necessary for the present proceedings. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis in the present case.
- xviii. The Authority calculated the non-injurious price (NIP) for the product under consideration so as to ascertain whether duties lower than the dumping margin would be sufficient to remedy the injury being

- suffered by the applicant. The NIP has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce & sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the applicant and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).
- xix. The Authority examined the issues raised, information provided, and submissions made by the interested parties during the course of the proceedings, to the extent they were supported by evidence and considered relevant to the present purpose, in making the final finding.
 - xx. A disclosure statement containing the essential facts of the investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 16th June 2026 and the interested parties were asked to provide comments on the disclosure statement. The submissions made by the interested parties, arguments raised, and the comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, non-repetitive and supported with evidence in this final finding notification.
 - xxi. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹ 84.27.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Submissions by other interested parties (exporters, importers and users)

4. The other interested parties have made the following submissions with regard to the product under consideration and like article.
 - i. Indorama Industries Private Limited has submitted that the applicant does not produce Ethylene Diamine used in the production of spandex yarn and therefore to such an extent warrants a user-based exemption from the scope of product under consideration.
 - ii. Indorama requires high-purity ethylene di amine for producing spandex Yarn, where even trace impurities affect product performance. The ethylene di amine must meet precise purity and water content specifications.
 - iii. Despite multiple correspondences and testing, the applicant has been unable to supply EDA meeting these specifications. In their own test reports submitted, Balaji admitted that while they could meet other parameters, their EDA had a water content of 0.28%, exceeding Indorama's required level.
 - iv. Hyosung India Pvt Ltd. has requested exclusion of product under consideration for the manufacture of Elastomeric Filament Yarn on the ground that export price competitiveness of Elastomeric Filament Yarn producers will be affected.
 - v. Authority has previously recognized similar specialized raw material requirements for spandex manufacturers in the Mid-Term Review of Dimethylacetamide (DMAC) from China PR and Turkey (14.10.2020), where product exclusions were granted based on actual user needs.
 - vi. DGTR has also routinely allowed exclusions for bona fide users, such as in the initiation notification dated 29.09.2025 in the case of "Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel 300 and 400 Series," where certain widths were excluded for specific applications.
 - vii. Should the applicant oppose this exclusion, the Authority may require them to provide an undertaking confirming their ability to supply ethylene di amine of the required specification. If they are unable to do so, the Authority should waive the one-year cooling-off period under the relevant Trade Notice to allow imports without restriction.

C.2 Submission by the applicant

5. The applicant has made the following submissions with regard to the product under consideration and like article:
 - i. The product under consideration is 'Ethylene Diamine' and is also known as 'EDA'.
 - ii. The product under consideration is a chemical with two reactive amine groups, making it an essential ingredient in various industrial processes. It is primarily used in the production of chemicals such as specialty compounds, fungicides, agrochemicals, coatings, and polymers. The product is widely utilized in industries such as agrochemicals, pharmaceuticals, and etc.
 - iii. There is no known difference in the like article produced by the applicant and the imported product.
 - iv. The reliance of the other interested parties on anti-dumping investigation on imports of Dimethylacetamide (DMAC) from China PR and Turkey and Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel are incorrect. In both instances, product exclusions were granted only where users furnished clear,

- verifiable, and demonstrable evidence of functional non-substitutability, supported by testing and certification. No such evidence exists in the present case.
- v. On the submission that the applicant is unable to supply the product based on the specification, the domestic industry has submitted that the specification sheet relied on by the users are outdated. The domestic industry has undertaken significant research and development efforts, after 2020-21 to enhance the product in order to meet the technical requirements, and the high purity ethylene di amine is now being supplied to other producers of spandex. As regards relying HPLC (High Performance Liquid Chromatography) test report, the domestic industry has submitted that HPLC test report relied by the users were never shared with them despite request.
 - vi. On the request for the user-based exclusion, it has been submitted that such request is unwarranted as the domestic industry is capable of producing and supplying EDA meeting the requirements provided that Indorama places order. The domestic industry is supplying the product to the other Spandex users.
 - vii. A comparison of specifications would show that the domestic industry's product meets all required parameters. Moreover, specifications can be customized to meet customer requirements without additional machinery, using the same plant. If required, the domestic industry is willing to provide an undertaking to the Authority.

C.3 Examination by the Authority

6. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as under:

“3. The product under consideration (PUC) in the present investigation is 'Ethylene Diamine', abbreviated as “EDA”. The product is a clear colour less liquid. It has a freezing point at 11 'C and a boiling point of 117 'C.

EDA is a chemical with two reactive amine groups, making it an essential ingredient in various industrial processes. EDA is primarily used in the production of chemicals such as specialty compounds, fungicides, agrochemicals, coatings, and polymers. Further, the product is widely utilized in industries such as agrochemicals, pharmaceuticals, etc.

EDA is classified under Chapter 29 viz., “Organic chemicals” of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-heading 2921 21 of the tariff classification. The applicant has stated that EDA is imported under the HS code 2921 21 00. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

7. With regards to the exclusion of the ethylene diamine used in production of Spandex Yarn, the domestic industry has submitted that it has undertaken significant research and development to enhance the product quality. The domestic industry has admitted that while it could not meet specifications in past, it can now supply the product as per the requirements of the downstream industry. The domestic industry has also submitted that it has supplied EDA to other spandex producers, and the product meets all the technical requirements of the user industry. The specifications of the product can be modified based on the customer requirements. No new machine is required, and the entire process can be undertaken at the same plant. The domestic industry has also provided technical certificate of analysis which shows that it can provide the domestic like product with required specifications. Only differences in one of the technical parameters alone do not suffice that the two products are non-substitutable when the domestic industry has itself sold the product to other producers of Spandex. The interested parties claim of exclusion are purely based on the ground of water absorption. However, the Authority notes that the domestic industry has adduced sufficient evidence that it produces the product under consideration that can be used in the manufacturing of Spandex Yarn and the product supplied by the domestic industry is a like article to the imported product. In view of the same, it is not found appropriate to grant any end user-based exemption as well.
8. In view of the foregoing, the Authority confirms the scope of the product under consideration as defined at the stage of initiation, which is reproduced below.

The product under consideration in the present investigation is 'Ethylene Diamine' also known as 'EDA'

9. The manufacturing process of the product under consideration includes the reaction of mono ethanolamine and ammonia under the hydrogen atmosphere in a catalyst at a pressure of around 150 to 200 Kg/Cm² and temperature between 150 to 225 degrees centigrade. This is converted to a mixture of ethylene diamine, diethylene triamine, piperzine, amino ethyl piperzine, hydroxyl ethyl piperzine and amino ethyl ethanolamine. The reaction occurs in a continuous flow reactor. The reaction mixture obtained from the reactors are then subjected to a series of distillations for recovery of the products. The excess raw materials are recycled back to the reaction stage for conversion of desired products.

10. The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff, under the heading “Organic Chemicals”. Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under the HS code 2921 21 00. The Authority has considered the customs classification as indicative only and not binding on the scope of the subject investigation. There are no restrictions on the import of the product under consideration in India as it falls under open general license. The basic customs duty applicable to product under consideration is 7.5%. The prescribed unit of measurement for the product under consideration is metric tons (MT), and the same has been adopted for this investigation.
11. Rule 2(d) of the Rules provides the definition of like article as under:

“like article” means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation.”
12. The Authority notes that from the definitions cited above, it flows that for two articles to be considered like, it is not necessary for them to be identical in all respects. If two articles have closely resembling characteristics, such resemblance is sufficient for the articles to be considered alike. For determining whether two articles have closely resembling characteristics, the Authority considers technical and commercial substitutability of the products as the relevant tests. Two products may look different in terms of technology of production, design, style, quality, etc., yet they could be considered alike for the purpose of investigation as long as they are functionally substitutable and replaceable in the market, due to similar end use and consumer preference.
13. The Authority notes that there is no known difference between the product under consideration exported from the subject countries and the like article supplied by the domestic industry. The product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics. Consumers are using domestic material and imported material interchangeably and the exporter and the domestic industry have sold the same product to same set of customers. The Authority therefore holds that the product produced by the domestic industry is a like article to the imported product.
14. The Authority notified the scope of the product under consideration and the PCN methodology in the notice of initiation. The interested parties were asked to provide their comments on the PUC-PCN methodology, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.
15. The Authority considered the comments of the interested parties on the scope of the product under consideration and the PCN methodology. However, the Authority was of the opinion that there was no sufficient ground for any exclusions or to make PCN in the present investigation. Accordingly, the scope of the product under consideration and the PCN methodology for the purpose of filing of response was notified as same as notified in the initiation notification dated 25th March, 2025.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Submission by opposing interested parties

16. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to the scope of the domestic industry and its standing.
 - i. The applicant has claimed the existence of another domestic producer but did not disclose its name or production details, raising serious doubts about the accuracy of its standing claim.

D.2 Submission by the applicant

17. The applicant has made the following submissions with regard to the scope of the domestic industry and its standing:
 - i. The applicant is the sole producer in India of the product under consideration, Ethylene Diamine (EDA).
 - ii. Other than the applicant, Diamines & Chemicals Limited is another producer of the like article with the capacity of 2500 MT. However, it is the applicant’s understanding that the producer is not undertaking any production.
 - iii. The applicant has not imported the product under consideration in the period of investigation from any of the subject countries.
 - iv. The applicant is not related to any exporters in the subject countries or importers of the product under consideration into India.

D.3 Examination by the Authority

18. Rule 2(b) of the Rules defines the term ‘domestic industry’ as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

19. The application has been filed by Balaji Speciality Chemicals Limited. As per the information on record, there is one other producer of the subject goods in India viz., Diamines & Chemicals Limited. The Authority had sent communication to Diamines & Chemicals Limited before the initiation of this investigation. However, the producer did not respond to it. The domestic industry has claimed that the producer was not producing the product under consideration during the injury period.

20. The Authority has examined the DG System transaction wise data, and it is seen that Balaji Speciality Chemicals Limited has not imported the product under consideration in the period of investigation. It is also seen that Balaji Speciality Chemicals Limited is not related to any exporters of the product under consideration from the subject countries or any importer in India.

21. Based on the information on record, the Authority has determined the Indian production and share of Balaji Speciality Chemicals Limited in Indian production for the period of investigation as follows:

S. No.	Particulars	Production (MT)	Share (%)
1	Production of Applicant	***	100
2	Total/gross Indian production	***	100

22. Balaji Speciality Chemicals Limited is an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules. Hence, the Authority holds that Balaji Speciality Chemicals Limited constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY AND MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**E.1 Submission by opposing interested parties**

23. The opposing interested parties have made the following miscellaneous submissions:

- i. All confidentiality claims made in their responses are consistent with Rule 7 of the Anti-Dumping Rules and the Trade Notice No. 10/2018 dated 27th September 2018 issued by the Authority as these have been made only for proprietary business information, disclosure of which would result in significant commercial harm and may adversely affect the competitive position of the company.
- ii. Disclosure of list of products is not a requirement under Annexure II of Trade notice No. 10/2018. However, the list of products is available at the company website.
- iii. The companies have duly disclosed the names of all related parties involved in the production of product under consideration.
- iv. The disclosure of information regarding financial and accounting system is not available in the public domain and the same is not required to be disclosed according to Annexure II of Trade Notice.
- v. Sadara Chemical Company submits that the manufacturing process of the product under consideration is highly proprietary and forms a core component of the producer's know-how and trade secrets. Still the company provided the non-confidential summary of the production process.
- vi. With regard to the claim of non-disclosure of adjustments to the export price, the adjustments claimed by the opposing parties in calculating the export price are transparently disclosed in the non-confidential version of Appendix 3A/3B of the questionnaire response. The adjustments pertain to company-specific commercial data, including financial and transactional details that are confidential in nature. While the full methodology and quantum of adjustments have been kept confidential, the type of adjustment have been adequately summarized in the non-confidential version in the appendices.
- vii. Applicant failed to adhere to Trade Notice 10/2018. Failed to disclose NIP and net sales realization.

- viii. Reliance placed on Exotic Décor Pvt. Ltd. judgment and Trade Notice No. 07/2018, to request access to import data in the same format used by the Authority to ensure transparency and due process.

E.2 Submission by the applicant

24. The applicant has made the following miscellaneous submissions:
- i. Excessive confidentiality is claimed by the opposing parties concerning the production process, list of products produced, list of related companies and the financial and accounting system used by the companies. Related parties should be disclosed in accordance with trade notice.
 - ii. The exports have not provided the adjustments claimed for the calculation of normal value and net export price. Information on list of adjustments in the normal value and export price is ultimately disclosed by the Authority in the final findings. As such, the producers/exporters have submitted information that will eventually be made public. Therefore, the claim of confidentiality in this regard is completely baseless.
 - iii. The distribution channels have been kept completely confidential.
 - iv. Related importers have claimed entire exhibits and annexures as confidential without even disclosing trends, thereby preventing the applicant's ability to comment meaningfully.
 - v. The purchase of the product under consideration, total sales turnover, details of utilization of PUC, cost breakup and production has not been disclosed by Cardolite and Indorama. Further, production process is also claimed confidential by Indorama.
 - vi. The other interested parties alleged that the domestic industry failed to adhere to the trade notice 10/2018, however, the domestic industry has disclosed all relevant information, including the NIP (in range) and net sales realization (in indexed/trend form), in the non-confidential version of the application.

E.3 Examination by the Authority

25. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7). With regard to confidentiality of the information submitted by the interested parties, Rule 7 of the Rules provides as follows:

“7. Confidential Information:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub -rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the interested parties providing information on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

26. It is seen that the domestic industry and interested parties have claimed confidentiality on information, such as production, capacity, capacity utilization, sales volumes, market share, stocks, selling price, costs, profits, cash profits, return on investment, non-injurious price, cost of production related information, normal value, export price, dumping margin, landed price, injury margin, price adjustments, profit related information, sales channels, sales & purchase documents, customers and suppliers names, etc. It is also seen that wherever information is for injury period, the same has been provided on indexed basis. Wherever information pertains to single year, the same has been disclosed in range, if such disclosure does not compromise confidentiality of information. The interested parties have claimed confidentiality in various supporting documents & information, wherever such information has not been publicly disclosed by them. In those cases where an interested party has not publicly disclosed its annual reports and financial statements, the same has been claimed confidential. Wherever the interested parties have claimed a document as confidential, it is noted that these interested parties have claimed that these documents are not susceptible of summary and have given

reasons why summarization is not possible. The interested parties claimed that the domestic industry did not disclose range of non-injurious price. It is noted that the same information was subsequently disclosed.

27. The Authority has consistently allowed interested parties to claim confidentiality on such information and documents provided by domestic industries, foreign producers and other interested parties in all investigations. The Authority notes that all the interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties.
28. As regards disclosure of transaction-wise data by the applicant or DGTR, the Authority notes that the relevant information prescribed for the applicant is volume and value of imports and the source of the information. The information relevant to the Authority under the rules is the volume and price of imports. The transaction-wise data only constitutes information in the nature of supporting information relevant to the adequacy and accuracy of claims made by the applicant. Similarly, the information collected from the DG System is only for the purpose of quantifying volume and value of imports, and the same has been appropriately disclosed in the present disclosure statement. The interested parties have had enough opportunity to defend their interests on the information relevant to the investigation and determination.

F. ASSESSMENT OF DUMPING AND DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F.1 Submission by other interested parties

29. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to assessment of dumping and determination of normal value, export price and dumping margin.
- i. Sadara Chemical Company is a cooperating producer and exporter of the subject goods from Saudi Arabia, exporting to India through its related traders. It is claimed that the dumping margin must be determined based on actual records and information provided by cooperating producers/exporters.
 - ii. The alleged dumping margin for Saudi Arabia (75-85%) is grossly inflated and lacks a credible basis because it is derived from a flawed Normal Value calculation.
 - iii. The Normal Value claimed by the domestic industry is artificially high because it is benchmarked against its own inefficient and uncompetitive cost structure. The domestic industry's costs are inflated due to several structural disadvantages: it is a new entrant (commenced production in 2019) without economies of scale; it is not vertically integrated and depends on imported raw material (MEA); and its plant's location in Solapur incurs significant inland logistics costs. This cost structure is not representative of an efficient global producer like Sadara.
 - iv. The dumping margin must be calculated based on the actual, verified data concerning normal value and export price provided by the Respondents in their questionnaire responses.

F.2 Submission by the applicant

30. The applicant has made the following submissions with regard to assessment of dumping and determination of normal value, export price and dumping margin:
- i. China PR should be considered a non-market economy.
 - ii. Should it be contended that Article 15(a)(ii) of China PR's Accession Protocol has already ceased and therefore the same cannot be applied to the present case, Article 15(a)(i) is still applicable and must be considered for determination of normal value for China PR.
 - iii. The obligation under 15(a)(i) of China PR's Accession Protocol require the criterion stipulated in para 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied by the exporter.
 - iv. Since Chinese producers are not entitled to market economy treatment, the Designated Authority should follow para 7 of Annexure I of the Rules for the determination of Normal Value.
 - v. The applicant could not determine normal value based on actual selling price or on cost of production in a market economy in third country since no verifiable evidence of the actual selling price was publicly available.
 - vi. The applicant could not determine normal value based on the price from a third country to another country, including India since while the subject good has a dedicated code in India, it does not have a dedicated code globally.
 - vii. The applicant had determined normal value according to 'any other reasonable basis' on the basis of its export price to other countries since these exports are sufficient in volume and profitable in nature and

- on the basis of cost of production of the applicant including addition of reasonable profits. For determining cost of production, international price of raw materials was considered.
- viii. If the Authority considers that all the provisions of Article 15 of China's Accession Protocol are not available any longer and the normal value is required to be determined in accordance with the provisions of Para 1-6 of the Rules, the Chinese domestic costs and prices nevertheless cannot be accepted unless multiple standards are passed by the Chinese exporters, namely (i) the absence of state interference in the determination of costs and prices, (ii) the prices of major inputs substantially reflect market values, (iii) the exporters books are audited in line with Chinese Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and international accounting standards and (iii) the appropriateness of costs due to organizational structure of the exporter.
 - ix. Even after taking due efforts, applicant could not find any evidence with regard to actual transaction price of producers in European Union.
 - x. Applicant has considered the intra EU prices, which is the price at which the product is traded for consumption in European Union to determine the normal value.
 - xi. There is no evidence publicly available with regard to actual transaction price of producers in Taiwan. As the product has a dedicated code in the country, the applicant has determined the normal value on the basis of Imports into Taiwan.
 - xii. Even for Saudi Arabia, there is no evidence publicly available with regard to actual transaction price of producers or actual cost of production in the country. Though the product has a dedicated code in the country, in the absence of any published data the applicant has determined the normal value on the basis of cost of production of applicant with reasonable additions of margins.
 - xiii. The dumping margins and injury margins of the subject countries are not only above de-minimis but unprecedented significant in the period of investigation.

F.3 Examination by the Authority

31. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers and exporters from the subject countries, along with their related exporter and importer in India, have filed the prescribed questionnaire responses.

S. No.	Name of interested party
a.	M/s BASF Antwerpen NV, Belgium
b.	M/s BASF EOOD, Bulgaria
c.	M/s BASF Espanola SLU, Spain
d.	M/s BASF France S.A.S., France
e.	M/s BASF Hong Kong Ltd., Hongkong
f.	M/s BASF Hungaria Kft., Hungary
g.	M/s BASF-YPC Company Limited, China PR
h.	M/s BASF Ireland DAC, Ireland
i.	M/s BASF Italia S.p.A., Italy
j.	M/s BASF Nederland B.V., Netherlands
k.	M/s BASF SE, Germany
l.	M/s BASF spol s.r.o., Czech Republic
m.	M/s BASF India Limited
n.	M/s Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited, Dubai Branch, UAE
o.	M/s Dow Saudi Arabia Product Marketing Arabia B.V. Dubai Branch, UAE
p.	M/s Dow Chemical International Private Ltd, Dubai Branch, UAE
q.	M/s Sadara Chemical Company, Kingdom of Saudi Arabia

32. The normal value and export prices for all the producers/exporters from the subject countries have been determined as below,

F.4 Determination of normal value and export price

a. Normal value and export price from China PR.

• Normal value

33. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provision of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

34. The applicant had relied upon Article 15(a)(i) of China's the Accession Protocol as well as para 7 of the Annexure I and claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicants that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules.
35. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-dumping Agreement read with the obligation under Article 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in paragraph 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming market economy treatment. It is noted that since the responding producers/exporters from China PR have not submitted response to the supplementary questionnaire the normal value computation is required to be done as per the provisions of paragraph 7 of Annexure I of the Rules, which reads as under:

“7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

36. Para 7 lays down a hierarchy for the determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to any other country, including India, or where it is not possible, on any reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like article, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Para 7.
37. The Authority also notes the existing jurisprudence on constructing the normal value in the case of a non-market economy is contained in the various judgements. These judgements provide directions regarding the implementation of Para 7 of Annexure I of the Rules concerning the choice of an appropriate option, and associated obligations thereof.
38. The Authority notes that none of the interested parties has provided any information regarding the domestic price or constructed value of the product in an appropriate market-economy third country. The Authority further notes that it is required to select an appropriate country on the basis of the information and evidence placed on record by the interested parties. It has been claimed that the product under consideration does not have a dedicated code in most countries. Since the product does not have a dedicated code in most countries, the Authority has not determined the normal value on this basis.
39. The Authority has determined normal value for China PR based on price actually paid or payable in India for the like article. The normal value has been determined considering the cost of production in India, duly adjusted, after addition for the selling, general & administrative expenses, and the reasonable profits. The constructed normal value so determined is mentioned in the dumping margin table.

- **Export price**

- **BASF-YPC Company Limited**

40. BASF-YPC Company Limited is a producer of the product under consideration and has reported *** MT as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has indirectly exported the product to India through related trader to related Indian customer, which resold the same to unrelated Indian customers. The producer has claimed adjustment on account of ocean freight, inland transportation etc.
41. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by the respondent. The adjustments claimed by the respondent have been allowed after desk verification. The net export price so determined is given below in the dumping margin table.

- **Non-cooperative producers of China PR**

42. The Authority has determined the net export price for non-cooperative producers/exporters on the facts available. The ex-factory export price as determined is shown in the dumping margin table below.

- **Normal value and export price from European Union**

- **BASF Antwerpen NV and its related traders (called as BASF Group)**

- **Normal value**
43. BASF Antwerpen NV is a producer of the subject goods in European Union. The producer along with its related exporters and importer have submitted Exporter's Questionnaire response furnishing the required information. The Authority notes that the producer/exporter has reported domestic sales of *** MT in the period of investigation to related customers, which resold the same to unrelated customers or used captively.
44. In order to determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit

making transactions are more than 80% then the authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Based on the ordinary course of trade test, it is noted that the subject producer has not been able to qualify the ordinary course of trade test as *** of the sales are profit making, and therefore, the Authority has considered it appropriate to determine normal value in the present case on the basis of profitable transactions.

45. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by the respondent including adjustments related to inland freight, ocean freight etc. The claims made and as verified after desk verification have been accepted. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

- **Export price**

46. BASF Antwerpen NV is a producer of the product under consideration in European Union. BASF Antwerpen NV has exported the product directly to the related importer and through its related exporters namely BASF Belgium Coordination Center CommV, BASF EOOD, BASF Espanola SLU, BASF Oy, BASF France S.A.S., BASF Hungaria Kft., BASF Ireland DAC, BASF Italia S.p.A., BASF Nederland B.V., BASF S.R.L., BASF spol s.r.o., BASF SE, BASF Hong Kong Ltd. The related exporters further resold the product to their related importer namely BASF India Limited, who in turn sold the subject goods to unrelated customers in India.

47. BASF Antwerpen NV is a producer of the product under consideration and has filed a questionnaire response. The producer has reported *** MT as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has indirectly exported the product to India through related traders to related Indian customer, which resold the same to unrelated Indian customers. The producer has claimed adjustment on account of ocean freight, inland transportation etc.

48. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by the respondent. The adjustments claimed by the respondent have been allowed after desk verification. The net export price so determined is given below in the dumping margin table.

Non-cooperative producers of European Union.

49. The Authority has determined the net export price for non-cooperative producers/exporters on the facts available. The ex-factory export price as determined is shown in the dumping margin table below.

c. Normal value and export price from Saudi Arabia

Sadara Chemical Company, Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited, Dubai Branch, Dow Saudi Arabia Product Marketing Arabia B.V., Dow Chemical International Private Ltd

- **Normal value**

50. Sadara Chemical Company (“Sadara”) is the producer of subject goods in Saudi Arabia. Sadara submitted its response in the prescribed exporter questionnaire format furnishing the requisite information. The Authority notes that during the POI, Sadara made only one domestic sale transaction of the subject goods (off grade) of *** MT, to an unrelated customer in the domestic market. As this one domestic sale transaction was of off-grade quality and not in sufficient quantity, the same cannot be considered for the purpose of determination of the normal value.

51. In view of the above, the Authority has constructed the normal value based on the cost of production of the product under investigation as reported by Sadara in Appendix-8 and duly verified during the course of investigation, with an addition of reasonable profit margin. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table.

- **Export price**

52. Sadara Chemical Company is a producer of the product under consideration in Saudi Arabia. During the POI, Sadara has sold the subject goods to its related exporter, Dow Saudi Arabia Product Marketing Arabia B.V (“Dow Marketing”). Dow Marketing, in turn, sold the subject goods to another related trader, Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited, Dubai Branch (“Dow Singapore”). Dow Singapore subsequently sold the subject goods to related importer in India, Dow Chemical International Pvt Ltd (“DCIPL India”). DCIPL India finally sold the subject goods to unrelated customers in India.

53. One export transaction has also been made by Dow Marketing to Dow Chemical International Pvt Ltd, Dubai Branch (“DCIPL Dubai”). DCIPL Dubai has subsequently sold this one transaction of the subject goods to unrelated customer in India. All the 5 entities, Sadara, Dow Marketing, Dow Singapore, DCIPL Dubai and DCIPL India have participated in the present investigation and provided the relevant information in the prescribed questionnaire format.

54. The Authority notes from the responses submitted by Dow Marketing, Dow Singapore, and DCIPL Dubai that the subject goods manufactured and exported by Sadara were resold at a profit by the Dow Group as a whole during the POI.
55. Sadara claimed adjustments towards ocean freight, insurance, inland transportation, port-related expenses, credit cost and marketing fee. These adjustments have been examined and allowed by the Authority after due verification.
56. The ex-factory export price so determined has been considered for the purpose of calculating the dumping margin and is reflected in the Dumping margin table below.

Non-cooperative producers of Saudi Arabia.

57. The Authority has determined the net export price for non-cooperative producers/exporters on the facts available. The ex-factory export price as determined is shown in the dumping margin table below.

d. Normal value and export price from Taiwan.

58. As none of the producers/exporters have participated in the subject investigation, the normal value and export price for all producers / exporters from Taiwan have been determined based on the best available in terms of Rule 6(8) of Anti-Dumping Rules, 1995.

e. Dumping margin

59. The normal value, export price and dumping margin determined in the present investigation are as follows

S. No.	Particulars	CNV/ NV USD/MT	NEP USD/MT	Dumping margin USD/MT	Dumping margin %	Dumping margin range
A	China					
1	BASF-YPC Company Limited	***	***	***	***	20-30
2	Any other producer	***	***	***	***	40-50
B	European Union					
1	BASF Antwerpen NV	***	***	***	***	80-90
2	Any other producer	***	***	***	***	120-130
C	Saudi Arabia					
1	Sadara Chemical Company	***	***	***	***	10-20
2	Any other producer	***	***	***	***	20-30
D	Taiwan					
1	Any producer	***	***	***	***	30-40

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submission by other interested parties

60. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to assessment of injury and causal link:
- Imports have increased only to bridge the demand-supply gap, while the applicant's reduced production and sales is due to their operational inefficiencies.
 - The downstream users rely on imports primarily due to domestic supply shortages and not due to price preference. The applicant's low-capacity utilization and intermittent production suspensions during the period of investigation has left users with no choice but to import the product under consideration from the other countries.

- iii. EDA is a standardized commodity whose price movements mirror fluctuations in key feedstocks such as Ammonia and Monoethanolamine (MEA). The periodic price gaps between imported and domestic products are market-driven and do not constitute undercutting.
- iv. The applicant's higher cost structure is due to its own inefficiencies and external raw material dependence. Lower import prices reflect global producers' backward integration, not injurious pricing.
- v. The decline in prices during 2023-24 and the POI coincided with a fall in the decline in international prices of product under consideration.
- vi. Global supply and demand drive product under consideration prices. Prices increased in 2021-22 and 2022-23 due to plant closures in China and EU and fell in 2023-24 when production normalized. The applicant's price decline matches this global trend, not impacted by the imports.
- vii. The applicant acknowledged that the increase in production in 2022-23 was driven by higher exports, and the subsequent drop in production reflects a strategic choice rather than any structural inability to produce.
- viii. The applicant has also referred to a notional "loss of revenue" at fair prices. This calculation is hypothetical and not supported by detailed workings or verifiable data.
- ix. The landed price of imports shows significant variation among countries, with nearly Rs. 17,000 per MT difference between the highest and lowest prices, indicating that imports do not compete at identical price levels.
- x. The applicant's capacity utilization decreased sharply, which increased per-unit fixed cost.
- xi. Raw material prices changed substantially during the period, altering cost margins.
- xii. The 2023-24 Chairman's Address highlighted challenges such as geopolitical tensions, supply chain disruptions, and climate risks, without mentioning dumping as a major concern.
- xiii. The applicant is entirely dependent on imported Monoethanolamine (MEA), which has highly volatile prices. This dependence and price fluctuation have substantially increased the applicant's input and inventory costs. Unlike global producers who are backward integrated, the applicant operates a non-integrated plant, resulting in a significant cost disadvantage.
- xiv. The applicant's facility in Solapur, Maharashtra, is far from ports and petrochemical hubs, leading to high logistics and inland freight costs that inflate production costs independent of imports.
- xv. The applicant began commercial production only in June 2019. The injury period coincides with its initial years of operation, marked by start-up inefficiencies such as process stabilization, workforce training, and supply chain establishment.
- xvi. Higher ethylene di amine costs would affect investment and innovation in the agrochemical sector, weakening India's global competitiveness.
- xvii. In the present case, non-subject countries Japan, USA, and Korea RP have individual shares below 3%, but their combined share is 7.28%, exceeding the threshold. These countries should therefore have been included in the investigation.
- xviii. Excluding these countries constitutes discrimination, contravenes WTO principles, and undermines the effectiveness of any anti-dumping measures.
- xix. The principal source of any alleged injury to the applicant is imports from China PR, not from Saudi Arabia.
- xx. The injury analysis must consider all relevant economic factors, including export performance of the applicant. The applicant export volumes have declined during the period of investigation. The export prices also declined by 35%, indicating severe pressure in international markets.
- xxi. Salaries and wages during the period of investigation are over 2.4 times higher than in 2021-22.
- xxii. Capital employed has increased by 13% over the same period, even though no capacity expansion has occurred.
- xxiii. The imposing anti-dumping duties on the subject countries will benefit only non-subject countries and provide no meaningful relief to the applicant. A significant gap exists between domestic demand and supply, making imports essential.

- xxiv. Prices from non-subject countries such as Japan, the USA, Korea RP, Singapore, and the UAE are comparable or even more competitive, meaning that any restriction on subject-country imports will simply shift the source of imports without alleviating price pressure.
- xxv. The applicant will continue to face the same competitive challenges regardless of duties.
- xxvi. The domestic industry's claim of suffering injury is unsubstantiated and based on an exaggerated injury margin (claimed to be 50-60% for Saudi Arabia) derived from a flawed premise.
- xxvii. The entire injury analysis relies on a Non-Injurious Price (NIP) that is unreasonable and artificially inflated. The claimed NIP is significantly higher than the landed price of imports from every single exporting country, including all non-subject countries.
- xxviii. This proves that the domestic industry's cost of production is inherently unviable and that its financial strain is a consequence of its own structural inefficiencies, not fair import competition.
- xxix. Furthermore, any injury is self-inflicted. The DI's expenditure on salaries and wages surged by nearly 2.5 times and its capital employed increased by 13% in the POI compared to 2021-22, all while its production capacity remained unchanged and production declined. This disproportionate and questionable escalation in costs is a primary cause of its financial strain and must be examined.
- xxx. There is no causal link between imports from Saudi Arabia and the alleged injury. The volume of imports from Saudi Arabia has declined by more than 20% during the injury period, from 13,587 MT in 2021-22 to 10,773 MT in the POI.
- xxxi. The market share of imports from Saudi Arabia in total Indian imports has also sharply declined from 42.01% in 2021-22 to 25.27% in the POI.
- xxxii. The actual cause of injury is the massive surge in imports from China PR, which grew over seven-fold during the injury period and now constitutes the largest source of imports (36.50% share). The entire increase in subject country imports is attributable solely to China PR.
- xxxiii. There is a significant and growing demand-supply gap in India for EDA. The domestic industry's capacity is insufficient to meet even half the demand, making imports essential for downstream industries.
- xxxiv. The significant decline in the domestic industry's own export sales volumes and prices points towards declining global prices as the reason for price pressure, not dumped imports from Saudi Arabia.

G.2 Submission by the applicant

61. The applicant has made the following submissions with regard to assessment of injury and causal link:
- i. Producers in China have installed capacity exceeding its domestic demand. This excess production capacity is more than the entire demand of the Indian market, indicating that it has been developed for export.
 - ii. The pattern of excessive and aggressive imports from both China and Taiwan clearly shows that their business model to run a business is to capture the market of other country by unfair trade practices and their surplus capacities will be diverted to India in case of non-imposition of anti-dumping duties.
 - iii. The legal requirements for cumulative assessment are met in the present case. As none of the opposing parties have disputed the cumulative assessment, Authority is requested to consider the cumulative assessment of the effects of imports.
 - iv. There is significant increase in the volume of dumped imports of the product under consideration from the subject countries. The imports from subject countries have increased more than the increase in demand over the injury period.
 - v. The import price has not moved in line with the changes in the cost of production. The exporters have reduced their prices more than the reduction in cost to capture the Indian market.
 - vi. The domestic industry is unable to operate optimally inspite of having installed capacity sufficient to cater 60% of domestic demand due to influx of low-priced imports.
 - vii. The export price in other countries is higher than the prices in the Indian market. The producers from the subject countries are engaged in selective dumping and offers low prices in the Indian market when compared to other export markets.
 - viii. Ethylene di amine prices in the Indian market are neither reflective of the import price of MEA into India nor global MEA prices. The domestic industry has also established that the prices are selectively lower in the Indian market.

- ix. There is significant positive price undercutting as well as cost undercutting despite domestic industry selling at losses.
- x. Import price is even below the variable cost of the domestic industry. The dumped imports are depressing the prices of the domestic industry.
- xi. There is significant unutilized capacity with the domestic industry.
- xii. Capacity utilization of the domestic industry declined during the period of investigation. The production and domestic sales of the domestic industry have declined consistently over the injury period.
- xiii. The decline in selling price exceeded the decline in cost of sales leading to severe price suppression and losses. This is due to dumping and resultant injury and not due to internal injury.
- xiv. Significant dumping from the subject countries has prevented domestic industry to break even. With the contribution being negative, the domestic industry is not even in a position to recover its fixed costs and therefore, there is no incentive to produce the product.
- xv. The domestic industry has been forced to intermittently suspend its production due to low priced imports from the subject countries.
- xvi. The inventories of the domestic industry increased significantly.
- xvii. Domestic industry has suffered significant losses. The cash profits and return on investments declined.
- xviii. The profitability of the domestic industry declined with the increasing dumped imports from the subject countries.
- xix. The overall growth is negatively impacted by the dumped imports from the subject countries affecting domestic industry's ability to raise capital investment.
- xx. The export price of the domestic industry is higher than the domestic price and export profitability establishes the competitiveness of the domestic industry.
- xxi. The domestic industry's cost structure is fully reflective of prevailing market conditions and input prices in India. While import prices of raw material declined during the injury period, the import price of ethylene di amine fell more than twice the decline in the cost of inputs.
- xxii. The domestic industry was profitable when the import price was high. The abnormal fall in import prices, far beyond cost, clearly demonstrates injurious pricing by foreign producers rather than any internal inefficiency of the domestic industry.
- xxiii. On the submission that Japan, USA, and Korea RP individually have shares below 3%, their combined share exceeds the threshold. The imports from Japan and Korea RP are priced higher and account for only [4.5%] of demand, compared to Saudi Arabia's [21%], indicating that injury is attributable to the subject countries and not the non-subject countries.
- xxiv. While downstream industries have claimed they rely on imports due to supply shortages, the domestic industry has maintained sufficient capacity to meet a major portion of demand. Users have acknowledged that imports were procured primarily due to significantly lower prices offered by foreign producers. These low-priced imports often used by customers as a negotiation tool to pressure the domestic industry to reduce prices below sustainable levels.
- xxv. On the submission that the domestic industry's price movement does not align with global trends, it is submitted that during the injury period the landed price of imports declined sharply by Rs 1,46,778 per MT, while MEA import prices fell by only Rs 25,338 per MT, forcing the domestic industry to reduce its prices and incur losses.
- xxvi. It is alleged that the domestic industry's higher cost structure is due to inefficiencies and lack of backward integration. However, the cost structure reflects prevailing market conditions and input prices in India. If the high-cost structure were a cause of injury, the domestic industry would have incurred losses even before the period of investigation.
- xxvii. On the submission that the "loss of revenue" is hypothetical, under anti-dumping rules, the adverse impact of dumped imports must be assessed based on actual and potential sales decline, and the law does not distinguish between sales volume and value.
- xxviii. During the period of investigation, the domestic industry incurred an actual loss of Rs [***] crores, as actual sales were restricted Rs [***] crores against potential sales of Rs [***] crores at fair prices.

- xxix. On the submission that the injury to the domestic industry is due to high logistics and start-up costs, it is submitted that these conditions persisted throughout the injury period. These factors existed in earlier years, during which the domestic industry remained stable and profitable.
- xxx. In response to the claim that the annual report highlights other challenges affecting the domestic industry, it is submitted that the 2024-25 annual report clearly states that the domestic industry's performance was impacted due to dumped imports. Thus, the injury cannot be attributed to any other factor.
- xxxi. On the submission that the salaries and wages have increased and which are a cause of injury, salaries and wages during the period of investigation were lower than in 2023-24, when the domestic industry earned profits, therefore, the losses cannot be attributed solely to salaries and wages.
- xxxii. The submission that capacity employed increased despite no expansion is misplaced, as working capital is not solely dependent on the product under consideration. An increase in net fixed assets does not necessarily mean higher capacity, as it may relate to other essential components that do not enhance capacity. Both net fixed assets and working capital declined during the period of investigation for the product under consideration as a whole. Allocation between domestic and export operations is made based on sales value.

G.3 Examination by the Authority

62. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles...". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.
63. It has been claimed that the domestic industry is not backward integrated which is leading to high cost and the losses suffered by the domestic industry are due to absence of backward integration. The authority notes that the domestic industry was profitable in the year 2020-21 and 2021-22. Had the absence of backward integration been a factor affecting the performance of the domestic industry, the domestic industry would have suffered losses in past as well. The Authority notes the decision of the Appellate Body in European Union – Biodiesel (Argentina), wherein it was held that an Authority is not required to conduct a non-attribution analysis with respect to features that are inherent to an industry and have remained unchanged over the injury period. It has been found from the questionnaire response filed by the participating producers that the product has been exported into India at dumped prices. Similarly, the fact that the applicant's facility in Solapur, Maharashtra, is far from ports and petrochemical hubs, leading to high logistics and inland freight costs that inflate production costs does not justify losses in the period of investigation and profits in past. Therefore, the Authority does not consider that the claimed injury is due to the fact that the domestic industry is not backward integrated or due to the location.
64. With regard to the submission that the domestic industry's production has declined, leading to an increase in the cost of production and, consequently, injury, the Authority notes that the decline in production is itself a direct consequence of the dumping of the subject goods in the domestic market. When the domestic industry is experiencing adverse volume effects due to dumped imports, it would not be appropriate to attribute the resulting losses or increased costs to internal inefficiencies or reduced production alone. Such adverse volume effects are intrinsically linked to the presence of dumped imports, which have displaced domestic production and suppressed capacity utilisation. The Authority further takes note that the import prices of the subject goods were below the cost of production of the domestic industry, thereby aggravating the injury suffered. In view of the above, the Authority finds that the decline in production and the consequent increase in costs cannot be dissociated from the impact of dumped imports.
65. It has been contended that, in its annual report, the domestic industry attributed the injury suffered primarily to factors such as geopolitical tensions, supply chain disruptions, and climate-related risks, without identifying dumped imports as a significant cause of injury. The Authority observes that the interested parties have made selective references to the annual reports, upon examination of the domestic industry's Annual Report for the year 2024-25, it is evident that the domestic industry has also stated that its performance has been adversely affected due to dumped imports. In view of the above, the Authority finds that the contention of the interested parties is not substantiated and, therefore, does not merit acceptance.

66. On the submission that the imports from Japan, Korea and United States of America cumulatively account for 7% share in total imports, the import data has been examined and it is seen that cumulative share of these imports is less than 6% of total imports.
67. On the submission that the salaries paid have increased which could have caused injury to the domestic industry, the Authority notes that the domestic industry's wages have increased till 2023-24 but has declined in the period of investigation. The salaries and wages in the period of investigation are lower than the year 2023-24 and the domestic industry has recorded higher losses in the period of investigation. The degree of the financial losses suffered by the domestic industry cannot be attributed to the wages and salaries alone.
68. Para (iii) of Annexure II of the Rules deals with cumulative analysis of imports. It reads as follows:
(iii) In cases where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to antidumping investigation, the designated authority will cumulatively assess the effect of such imports, only when it determines that, -
(a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent. expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three per cent. of the import of like article or where the export of individual countries is less than three per cent., the imports collectively accounts for more than seven per cent. of the import of like article; and
(b) a cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic product
69. In order to ascertain whether cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles, the following parameters have been examined: -
- Products supplied by different parties are like articles and are comparable in properties.
 - Domestically produced products and the imported products are interchangeable.
 - There is direct competition between the domestic product and the imported product and inter-se between the imported product.
 - Consumers are using domestic material and imported material interchangeably and the exporter and the domestic industry have sold the same product to same set of customers.
 - Import price from the subject countries have moved in tandem.
70. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the product under consideration from the subject countries on the domestic industry.

G.3.1 Assessment of demand/apparent consumption

71. For the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the like article in India has been defined as the sum of domestic sales of the domestic industry, domestic sales of the other India producer and imports of product under consideration from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

S. No.	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	95	90	66
3	Sale of the other Indian producer	MT	-	-	-	-
4	Trend	Indexed	-	-	-	-
5	Imports from subject countries	MT	24,304	19,729	27,583	36,207
6	Trend	Indexed	100	81	113	149
7	Imports from other countries	MT	1,545	952	1,682	2,302
8	Trend	Indexed	100	62	109	149

9	Demand/consumption	MT	***	***	***	***
10	Trend	Indexed	100	85	106	124

72. It is seen that demand declined in 2022-23 in comparison to 2021-22. Demand increased in 2023-24 and further increased in the period of investigation. The demand has increased over the injury period.

G.3.2 Volume effect of the dumped imports

73. With regard to the volume of imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports from the subject country, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The same is analyzed in the table below.

S. No.	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Subject countries	MT	24,304	19,729	27,583	36,207
2	Other countries	MT	1,545	952	1,682	2,302
3	Imports from the subject country in relation to:					
a	India production	%	***	***	***	***
b	Trend	Indexed	100	63	152	236
c	Indian demand	%	***	***	***	***
d	Trend	Indexed	100	96	107	120
e	Total imports	%	94%	95%	94%	94%

74. Imports in relation to Indian production declined in 2022-23, however, increased in 2023-24. Imports further increased in the period of investigation. Similarly, the imports in relation to Indian demand declined in 2022-23, but increased in 2023-24 and thereafter further increased in the period of investigation. It is seen that the imports in relation to production and demand have increased over the injury period. The Authority therefore considers that the increase in the imports was more than the increase in the demand in India.

75. Imports from subject countries in relation to total imports has remained at the same range during the injury period.

G.3.3 Price effect of the dumped imports

76. With regard to the effect of the dumped imports on prices of the domestic industry, the impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports of the subject goods from the subject country.

a. Evolution of import price

77. The table below shows the import price and the raw material price movement. The major raw material required in the production of the product under consideration is Monoethanol Amines and the domestic industry has provided information on the import prices of these products into India.

S. No.	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Monoethanol Amines	Rs/MT	1,23,463	1,48,801	1,00,006	1,02,139
2	Trend	Index	100	121	81	83
3	Import price (CIF)	Rs/MT	2,22,039	3,49,881	1,69,299	1,30,886
4	Trend	Index	100	158	76	59

78. It is seen that the raw material prices increased in 2022-23 and the import price also increased in this period. The raw material prices declined in 2023-24 and remained static in the period of investigation. However, the import price declined in 2023-24 and has thereafter declined further in the period of investigation.

79. While the raw material prices declined by 17% over the injury period, the import prices have declined by 41% in the period of investigation. The Authority considers that the import prices have not moved in line with the raw material prices, and has declined much more than fall in the raw material prices. Therefore, the submission that the price movement of the product under consideration mirror fluctuations in key feedstocks such as Ammonia and Monoethanolamine (MEA) does not hold true.

b. Price undercutting

80. For the purpose of price undercutting analysis, the net selling price of the domestic industry has been compared with the landed price of imports from the subject countries. Accordingly, the price effects of the dumped imports from the subject countries are as follows:

S. No.	Particulars	Unit	China PR	European Union	Saudi Arabia	Taiwan	Weighted average
1	Import volume	MT	12,414	11,615	10,691	1,486	36,207
2	Net sales realization	Rs/MT	***	***	***	***	***
3	Landed price	Rs/MT	1,43,206	1,45,544	1,34,946	1,47,265	1,41,684
4	Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
5	Price undercutting	%	10%	8%	16%	7%	11%

81. The Authority notes that the subject imports are undercutting the prices of the domestic industry and the price undercutting is positive and significant. The price undercutting is positive despite the domestic industry selling the product at losses.

c. Price suppression/depression

82. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in the normal course, the changes in the costs and prices over the injury period are compared as below:

S. No.	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	125	68	59
3	Change	Rs/MT	***	***	***	***
4	Cost of sales	Rs/MT	***	***	***	***
5	Trend	Indexed	100	121	90	89
6	Change	Rs/MT	***	***	***	***
7	Landed price	Rs/MT	2,40,358	3,78,746	1,83,266	1,41,684
8	Trend	Indexed	100	158	76	59
9	Change	Rs/MT	-	1,38,388	-1,95,480	-41,582

83. It is seen that,

- In 2022-23, while the cost of sales increased by 21 index points and the selling price also increased by 25 index points.
- In 2023-24, while the cost of sales declined by 31 index points, the selling price declined by 57 index points. The domestic industry suffered marginal losses in the year.
- In the period of investigation, while the cost of sales has declined by 1 index points, the selling price has declined by 9 index points.
- While the landed price of imports remained above the domestic industry's cost and selling price during 2022-23 and 2023-24, it declined drastically during the Period of Investigation (POI). Specifically, the landed price plummeted from ₹2,22,342 per MT in the first half of 2023-24 to ₹1,37,460 per MT in the second half of the same year (which serves as the first half of the POI, creating an overlapping period). Conversely, during the second half of the POI, the landed price saw a marginal recovery, increasing to ₹1,43,965 per MT.
- When compared to the immediately preceding year, while the selling price declined in the period of investigation, the landed price declined at a higher rate. The selling prices of the domestic industry are depressed.

84. The Authority notes that the landed price of imports has prevented the domestic industry from charging adequate remunerative prices in the period of investigation. Therefore, the landed price of imports has both suppressed and depressed the prices of the domestic industry. The Landed price during the first half of 2023-24 (Apr-Sep) is significantly higher than the second half of 2023-24 (Oct-Mar), which is part of POI. The selling price remains below landed price during this period, thus aggravating the injury.

G.3.4 Economic parameters of the domestic industry

85. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

a. Production, capacity, capacity utilization and sales volumes.

86. The capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period are given in the following table:

S. No.	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Capacity	MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	100	100	100
3	Production	MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	130	75	63
5	Capacity utilization-Plant	%	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	129	75	64
7	Domestic sales	MT	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	96	90	66
9	Export sales	MT	***	***	***	***
10	Trend	Indexed	100	244	12	8

87. It is seen that:

- The capacity of the domestic industry remained the same throughout the injury period. It is seen that the capacity is not dedicated in the product under consideration alone.
- When operating at full utilisation, the plant of the applicant can produce the product under consideration to the extent which can cater 60% of the demand in the domestic market. The domestic industry has provided evidence to show that while it has obtained environmental clearance to set up new plant, the plan has been put on hold due to the losses suffered.
- The production and the capacity utilization of the domestic industry increased in 2022-23 compared to 2021-22. The production and capacity utilization of the domestic industry declined in 2023-24 with the volume of imports from the subject country increasing. Production and capacity utilization have further declined in the period of investigation as compared to 2023-24.
- The domestic sales of the domestic industry declined in 2022-23 in comparison to 2021-22. Domestic sales declined further in 2023-24 and in the period of investigation. While the demand has increased, the domestic sales have declined. It is seen that the domestic industry has suffered decline in the domestic sales despite operating with significant idle capacities.
- The production and domestic sales of the domestic industry have declined over the injury period.

- f. The export sales of the domestic industry too have declined but continue to remain profitable. The Authority notes the domestic industry's contention that it is not reliant on export sales and that the same is being done only out of its inability to sell in the domestic market.

b. Market share of all suppliers

88. The market share of the domestic industry, other producers in India and imports of the products into India are shown in the table below:

S. No.	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Domestic industry	%	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	113	85	53
3	Other domestic producer	%	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	-	-	-	-
5	Imports from subject countries	%	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	96	107	120
7	Imports from other countries	%	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	73	102	120

89. Based on the above, the Authority notes that:

- The market share of the domestic industry increased in 2022-23, declined in 2023-24 and has thereafter declined again in the period of investigation.
- The market share of subject imports declined marginally in 2022-23, thereafter increased in 2023-24 and further increased in the period of investigation.
- Despite having the capacity to cater [***] of demand, the domestic industry is only able to cater [***] % of domestic market.
- The domestic industry has submitted that although it has obtained necessary approvals for capacity expansion, such expansion has not been undertaken, as the existing capacity remains grossly underutilized.

c. Inventories

90. Information with regard to inventory is given below.

S. No.	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Opening inventory	MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	92	228	109
3	Closing inventory	MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	248	254	509
5	Average inventory	MT	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	167	240	301

91. It is seen that the average inventory of domestic industry has increased over the injury period. The average inventory of the domestic industry increased in the period of investigation even when there was increase in demand of the product under consideration. The domestic industry has submitted that the inventories with the domestic industry shot up by 200% in the period of investigation as compared to base year.

d. Profitability, cash profits and return on capital employed.

92. Profitability, return on capital employed and cash profits of the domestic industry over the injury period are given in the table below: -

S. No.	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Profit/(Loss)	Rs/MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	137	-1	-30
3	Profit/(Loss)	Rs Lakhs	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	132	-0	-20
5	PBIT	Rs Lakhs	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	123	3	-15
7	Cash profit	Rs Lakhs	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	128	11	-7
9	Return on investment	%	***	***	***	***
10	Trend	Indexed	100	116	2	-14

93. It is seen that,

- The domestic industry's profit per unit increased in 2022-23 when the imports declined. The profits declined sharply and turned into losses in year 2023-24 and the losses have further aggravated in the period of investigation.
- The profitability increased in 2022-23 and thereafter declined till the period of investigation where it turned into severe losses.
- The domestic industry's profit before interest and taxes and cash profit have also increased in 2022-23 and thereafter declined till the period of investigation with the domestic industry recording cash losses and losses before interest in the period of investigation.
- The return on investment of the domestic industry increased in 2022-23, declined steeply and turned negative in 2023-24, thereafter further declined in the period of investigation.
- The current prices of domestic industry are below cost of production resulting in losses.

e. Employment, productivity and wages

94. Employment, productivity and wages of domestic industry over the injury period are given in the table below.

S. No.	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	No. of employees	No.	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	131	142	144
3	Productivity per day	MT/Days	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	113	113	111
5	Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
6	Trend	No.	100	99	42	44
7	Wages	Rs Lacs	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	158	312	241

95. It is seen that:

- The number of employees with the domestic industry increased over the injury period.
- The productivity per day increased in 2022-23, but has declined thereafter.
- The productivity per employee has declined continuously over the injury period.
- Wages paid by the domestic industry have increased in POI over 2021-22.

f. Growth

96. The following table shows the growth parameters of the domestic industry over the injury period.

S. No.	Particulars	UOM	2022-23	2023-24	POI
1	Production	%	30%	-42%	-16%
2	Capacity utilization	%	29%	-42%	-14%
3	Domestic sales	%	-4%	-6%	-28%
4	PBT per unit	%	37%	-100%	-5718%
5	Cash Profit per unit	%	33%	-91%	-186%
6	PBIT per unit	%	28%	-98%	-876%
7	ROI	%	16%	-98%	-844%
8	Inventory	%	67%	44%	25%

97. In the period of investigation, the volume parameters as well as all the price parameters including profit, cash profit, profit before interest and taxes and return on capital employed of the domestic industry have shown significant negative growth. These parameters continued to remain nowhere near the level they should have been. The domestic industry has experienced negative growth both in volume and price parameters first in 2023-24 which has continued in the period of investigation.

g. Ability to raise capital investment

98. The Authority notes that the domestic industry had recorded losses in the period of investigation. It is also seen that the return on capital employed by the domestic industry is negative, which would affect its ability to raise capital investments.

99. Considering the growing demand for the product, the domestic industry had obtained approval of expanding its total capacity to [***] MT (including non-product under consideration). The domestic industry wants to increase its capacity by investing huge amount. With such significant financial losses, the ability to raise capital for working capital needs has also been affected.

h. Factors affecting prices

100. The Authority notes that the landed price of subject imports was below the cost of sale and selling price of the domestic industry in the period of investigation. The landed price of subject imports has depressed the prices of the domestic industry, leading to the domestic industry suffering significantly on both volume and price parameters. Therefore, the dumped imports are the predominant factors affecting the prices of the domestic industry. The domestic industry has provided communication with the customers evidence that customers have quoted import price as a basis to negotiate with the domestic industry, pressuring it to reduce its prices to match the import levels.

i. Magnitude of dumping

101. The magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped into India. The investigation has shown that the dumping margin is positive and significant during the period of investigation.

G.3.5 Conclusions on injury

102. The examination of the imports of the product under consideration and performance of domestic industry shows that:

- The imports from the subject countries have increased from 24,304 MT in the base year to 36,207 MT. The imports have increased in absolute terms.
- The imports in relation to production increased from ***% in the base year to ***% in the period of investigation. The imports in relation to consumption increased from ***% in the base year to ***% in the period of investigation. The imports have increased in relative terms.
- The landed price is below the selling price of the domestic industry, resulting in positive price undercutting.
- The landed price has remained below the cost of sales of the domestic industry in the period of investigation. As a result, the domestic industry has been unable to adjust its prices in line with the changes in the cost. The prices of the domestic industry were depressed in the period of investigation.
- The production, domestic sales and capacity utilization of the domestic industry declined in the period of investigation.
- The market share of the domestic industry has declined over the injury period.
- The average inventory increased over injury period.

- h. Profitability of the domestic industry has declined in 2022-23 and turned negative in the period of investigation. The profit per unit has declined from Rs *** per MT to loss of Rs *** per MT.
- i. Cash profit and return on capital employed of the domestic industry similarly declined in 2022-23 and thereafter turned negative in the period of investigation.
- j. The domestic industry suffered in the growth of both volume and price parameters in the period of investigation.
- k. The domestic industry's ability to raise capital has been adversely impacted.
- l. The dumped imports have affected the prices of the domestic industry.
- m. The dumping margin is positive and significant during the period of investigation.

H. NON-ATTRIBUTION AND CAUSAL LINK

103. As per the Rules, it is, inter alia, required to be examined any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry. The Authority initially notes neither the Act nor the Rules require dumping to be the sole cause of injury to the domestic industry for anti-dumping duty to be applied.

a. Volume and price of imports from third countries

104. The Authority notes that apart from the subject countries, the imports from Japan, Korea and United States of America cumulatively account for less than 6% of total imports.

b. Contraction of demand

105. The Authority notes that demand has increased over the injury period and therefore injury to the domestic industry is not attributed to the contraction of demand.

c. Changes in pattern of consumption

106. The Authority notes that there has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

d. Trade restrictive practices

107. The Authority notes that sales of the product under consideration are not restricted in any manner and no restrictive practices have been brought to the notice of the Authority.

e. Developments in technology

108. The Authority notes that there has been no known material change in the technology for the production of the product under consideration.

f. Productivity

109. With the decline in production, the per employee production has also declined.

g. Export performance

110. The Authority notes that the injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of the domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry. The Authority notes that export sales have declined in the period of investigation comparison to the previous year. However, the exports continue to remain profitable. Therefore, the claimed injury in the domestic market cannot be due to export performance.

h. Performance of other products

111. The Authority has only considered data relating to the performance of the subject goods. Therefore, the performance of other products produced and sold is not a possible cause of injury to the domestic industry.

i. Factors affecting causal link between the dumped imports and injury to the domestic industry

- a) The dumping margin is above de minimis, and is significant from subject countries.
- b) The imports have increased in absolute and relative terms.
- c) The imports of subject goods from subject countries have led to adverse price effect, and the domestic industry has suffered significant price undercutting and price depression.

- d) On account of volume and price effect, the operating performance of the domestic industry deteriorated in terms of sales, production, capacity utilization, market share of the domestic industry, profits, cash profits and ROCE.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

112. The Authority has determined Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses are charged to the cost of production. A reasonable return @22% on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the subject goods was followed towards interest, tax and profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.
113. Landed price for the cooperating exporters has been determined based on the response filed. Applicable customs duties have been added to determine landed price of imports. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.
114. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters for the subject countries has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

S. No.	Producer/exporter	NIP	Landed	Injury margin		
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range
A	China					
1	BASF-YPC Company Limited	***	***	***	***	20-30
2	Any other producer	***	***	***	***	30-40
B	European Union					
1	BASF Antwerpen NV	***	***	***	***	20-30
2	Any other producer	***	***	***	***	50-60
C	Saudi Arabia					
1	Sadara Chemical Company	***	***	***	***	10-20
2	Any other producer	***	***	***	***	20-30
D	Taiwan					
1	Any producer	***	***	***	***	10-20

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

J.1 Submission by opposing interested parties

115. The opposing interested parties has made the following submissions with regard to Indian industry's interest and other issues:
- The downstream users rely on imports primarily due to domestic supply shortages. The applicant's low-capacity utilization and intermittent production suspensions during the period of investigation left users with no choice but to source from abroad.
 - Higher EDA costs would affect investment and innovation in the agrochemical sector, weakening India's global competitiveness.
 - EDA is a critical input for many industries, including pharmaceuticals, agrochemicals, water treatment, textiles, and adhesives. Imposing anti-dumping duties on EDA would raise input costs for downstream

- manufacturers, including mancozeb producers, who cannot pass on the increased costs to farmers, affecting their competitiveness.
- d. Quantitative evidence shows that ADD of 20–30% would significantly harm downstream users, eroding profitability, production, and export market share.
 - e. The imposition of anti-dumping duties will lead to trade diversion. Imports from subject countries will be replaced by imports from non-subject countries like Japan, the USA, and Korea RP, which are already supplying at competitive prices.
 - f. This will provide no benefit to the domestic industry, which will continue to face the same competitive pressures, rendering the duty ineffective.
 - g. The opposing parties are of the opinion that the investigation is legally flawed and discriminatory as it fails to include Japan, the USA, and Korea RP as subject countries. While individually below the 3% import share threshold, these countries collectively account for 7.28% of total imports, exceeding the 7% threshold mandated for inclusion under Rule 14(d) of the Anti-Dumping Rules.
 - h. The import prices from these non-subject countries are comparable to subject countries and significantly below the domestic industry's NIP, indicating they are also a source of dumped and injurious imports. Their exclusion violates the non-discriminatory principle of the WTO Anti-Dumping Agreement.

J.2 Submission by the applicant

116. The applicant has made the following submissions with regard to Indian industry's interest and other issues:
- a. The product is used in agrochemical and pharmaceutical applications such as Mancozeb and Sitagliptin. EDA consumption in Mancozeb production is very limited, and over 80% of Mancozeb output is exported and not subject to duty.
 - b. Sitagliptin is used to treat type 2 diabetes patients. The doctor prescribes per dosage of Sitagliptin of around 25-50 MG. Since the anti-dumping duty on Sitagliptin is only 0.002%, the anti-dumping duty on the end consumer would not have any impact.
 - c. The impact of proposed measures on downstream industries is negligible.
 - d. Prices in the past were higher. Even after inclusion of the proposed anti-dumping duty, the landed import price would remain below these historical levels. Therefore, the imposition of anti-dumping duty is unlikely to have any material impact on users.
 - e. Despite increase in the import price in 2022-23, the domestic industry refrained from raising prices in view of public interest.
 - f. Import prices surged in 2022-23 due to higher Ammonia and MEA costs, resulting in negative price undercutting of 13%, yet the domestic industry in view of public interest, did not raise its prices proportionately.
 - g. The product is primarily used in the agrochemical and pharmaceutical sectors, which operate as pass-through industries. Any cost increase due to anti-dumping duties is likely to be passed on to end consumers with minimal impact on demand.
 - h. Exporters from the subject countries would not have long-term commitment to the Indian market and may divert supplies to more profitable markets. In contrast, the domestic industry ensures stable supply, along with consumer interests, and allows lower inventory and working capital requirements.
 - i. As the sole Indian producer, the domestic industry is facing serious sustainability concerns, having already curtailed production for a substantial period. In the absence of anti-dumping duties, there is a real risk of plant shutdown, which would adversely affect employment and livelihoods.
 - j. The current performance of the domestic industry does not justify fresh investment in the country and its not financially viable for other Indian producers to enter into this business.
 - k. The domestic industry has allocated Rs 2.88 Cr. towards CSR in 2023-24 for benefiting the society by taking various activities in interest of public.

J.3 Examination by the Authority

117. The Authority examined whether the imposition of the anti-dumping duty would be against public interest. This determination is based on consideration of information on records and interests of various parties, including the domestic industry, foreign producers and consumers.

118. The Authority issued a gazette notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users to provide the relevant information with regard to the present investigation, including the possible effect of the anti-dumping duty on their operation. The Authority sought information on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by the various suppliers from different countries, ability to switch sources, the effect of the antidumping duty on the consumers, and the factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the imposition of the anti-dumping duty.
119. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market.
120. The Authority had prescribed an economic interest questionnaire, which was sent to all interested parties in this investigation. Coromandel International Limited, Indorama Industries Private Limited, Cardolite Speciality Chemicals India LLP and domestic industry have filed economic interest questionnaire. The users have claimed that anti-dumping duties will adversely affect the operations. The users have quantified the impact of anti-dumping duty as below.

User		Cardolite	Coromandel	Indorama
Product		Epoxy Curing Agent	Mancozeb	Elastomeric Filament Yarn
Cost of PUC in FG	Rs/KG	***	***	***
Total Cost of FG	Rs/KG	***	***	***
Selling price of FG	Rs/KG	***	***	***
Profitability	Rs/KG	***	***	***
Share of PUC in price of FG	%	***	***	***
Notional price increase in PUC	%	***	***	***
Increase in cost of PUC	Rs/KG	***	***	***
Impact of increase on price of FG	%	5.96%	2.91%	0.18%

121. The Domestic industry has quantified the impact of anti-dumping duty as below.

S. No.	Particulars	UOM	Mancozeb
1	Mancozeb Technical 85% min.	Rs/Kg	250
2	EDA for 1 KG of downstream product (estimate)	Kg	0.20
3	EDA price for 1 kg	Rs/Kg	134
4	ADD on EDA (Notional 20%)	Rs/Kg	26.80
5	Cost increase for downstream industry (API producer)	Rs/Kg	5.36
6	Impact of ADD for technical producer	%	2.14%
7	Mancozeb formulation price for 1 KG	Rs	571
8	Mancozeb concentration	%	75%
9	Cost increase for formulation producer	Rs	4.02
10	Impact of ADD on formulation producer	%	0.70%
11	Area which 1 KG of mancozeb can cover	Acre	1.25
12	Impact per acre	Rs	5

S. No.	Particulars	UOM	Sitagliptin
1	Average price of 1 KG of the product	Rs/Kg	7,500
2	EDA for 1 KG of downstream product (estimate)	Kg	0.15
3	EDA price for 1 kg	Rs/Kg	134
4	ADD on EDA (Notional 20%)	Rs/Kg	26.80
5	Cost increase for downstream industry (API producer)	Rs/Kg	4.02
6	Impact of ADD for tablet producer	%	0.05%
7	Price of 1 strip	Rs	85
8	Price of 1 tablet	Rs/strip	8.50
9	Sitagliptin dosage per tablet (MG)	MG	50
10	Price of 1 MG	Rs/MG	0.17
11	Price of 1 KG	Rs/KG	1,70,000
12	Cost increase for tablet producer (assuming entire cost increase passed on)	Rs/KG	4.02
13	Impact of ADD for tablet producer	%	0.002%
14	Impact per strip	Rs	0.002

122. Upon examination of the data filed by the domestic industry and the user industry, it is noted that EDA forms only a small part of the cost of the downstream products, with a correspondingly limited impact on the price of the end-products.

123. The table below shows the landed price of imports.

S. No.	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Landed price	Rs/MT	2,40,358	3,78,746	1,83,266	1,41,684

124. It is seen that the landed price was higher in past and has only declined in the period of investigation. The domestic industry has submitted that the landed price of imports including proposed anti-dumping duty will be lower than the prices in past. Therefore, when these high prices did not impact the user, the imposition of anti-dumping duty are not likely to have material impact. The Authority notes that though in the event of imposition of anti-dumping duties the price level of product in India may be affected but fair competition in the Indian market will not be reduced by such anti-dumping measures. On the contrary, the anti-dumping measures may mitigate the unfair advantage gained by dumping practices, which would arrest the decline of the domestic industry both material injury and would help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. Furthermore, the investigation has not shown that the downstream industry has been unable to align its prices in line with the increase in the cost.

125. As regards the imports necessitated due to the demand and supply gap, the information on record shows that the domestic industry is operating with significant idle capacity and has obtained necessary approval for expanding capacity. While there still exists a demand and supply gap, the Authority considers it cannot be expected that a producer would make significant investments despite suffering huge losses. The Authority further notes that the imposition of anti-dumping duty will not lead to scarcity of the subject goods in India. It is noted that anti-dumping duty does not restrict imports into the country but ensures that imports are available at fair prices. The imposition of duty would, therefore, not affect the availability of the product. The Authority observes that domestic market investments were made based on fair market principles. The domestic industry cannot expand when there is significant dumping and at the time user industry did not set up operations expecting access to dumped imports.

K. POST-DISCLOSURE COMMENTS

K.1. Submissions by the other interested parties

126. The other interested parties have made the following submissions on the disclosure statement:

- i. It is submitted that the Authority has not independently verified the standing of the domestic industry by seeking information from the concerned line ministries, which is the consistent practice followed in past investigations. This process is essential to ensure that the information regarding the standing of the domestic industry is correct and prevents any material risk of distorted data being considered by the Authority. Reference is invited to the WTO Appellate Body ruling in EC-Fasteners (China), which held that the competent authority bears the obligation to ensure that the way in which it defines the domestic industry does not introduce a material risk of skewing the economic data and, consequently, distorting its analysis of the state of the industry.
- ii. It is submitted that the 'major proportion' test is not a purely mathematical test and has both quantitative and qualitative connotations. A test that would be purely quantitative would not necessarily ensure that the domestic industry defined on that basis substantially reflects the total domestic production. The application fails to satisfy the qualitative aspect of the 'major proportion' test since the existing established producer in the market has been excluded from the scope of the domestic industry. The WTO Panel in China – Anti-Dumping and Countervailing Duty Measures on Broiler Products from United States held that an investigating authority is not allowed to ignore the situation of other domestic producers in its injury determination.
- iii. It is submitted that imports from Japan, USA, and Korea RP, while individually below the 3% threshold, collectively exceeded 7.28% of total imports as per the data provided in the application. Under WTO Anti-Dumping Agreement Article 5.8 and Rule 14(d) of the Anti-Dumping Rules, such imports ought to have been cumulatively assessed and included in the scope of this investigation. The exclusion of these countries from the scope of investigation disregards mandatory legal thresholds, renders the injury analysis materially incomplete and defective, and is contrary to the principle of non-discrimination embodied in the Most Favoured Nation treatment clause.
- iv. Imports from non-subject countries such as Japan and the USA are priced competitively, often below the constructed non-injurious price. By omitting these imports, the injury analysis ascribes the entire injury burden improperly to the subject countries, leading to an inflated injury margin and an erroneous causal link. Imposing anti-dumping duties only on subject countries will inevitably cause trade diversion to those excluded countries, nullifying the protective intent of the duty.
- v. It is submitted that any injury allegedly suffered by the domestic industry is attributable to factors other than the subject imports. The domestic industry operates with significant structural disadvantages, including dependence on imported Monoethanolamine (MEA) as its principal raw material, lack of backward integration, higher logistics costs arising from its location in Solapur, Maharashtra, and the absence of economies of scale due to its relatively small production capacity. Further, having commenced commercial production only in June 2019, the domestic industry was still facing initial operational inefficiencies, process stabilization issues, and elevated production costs during the injury period. These factors, individually and collectively, have materially impacted the domestic industry's performance and cannot be attributed to imports from the subject countries.
- vi. It is submitted that imports from China PR have witnessed an exponential growth of over seven-fold during the period of investigation as compared to the base year, and China PR has emerged as the single largest exporter of the product under consideration to India. Without the surge from China PR, aggregate imports from subject countries would have in fact declined. In contrast, the volume of imports from Saudi Arabia has declined during the injury period. Accordingly, the injury analysis must carefully distinguish between the individual contributions of subject countries, and cumulation of imports from Saudi Arabia along with China PR would lead to an erroneous attribution of injury.
- vii. It is submitted that the import data of EDA from non-subject countries has been revised downwards in the disclosure statement to a significantly higher extent than the revision in subject country import data. As a consequence of this disproportionate downward revision, the share of imports from non-subject countries in total imports has reduced from more than 7% to less than 7% in the period of investigation. No explanation has been provided for this asymmetric revision. The Authority is requested to re-examine the import data from non-subject countries as this issue directly affects the determination of whether those countries ought to have been included in the scope of the investigation.
- viii. It is submitted that the basic customs duty on imports of EDA under HS Code 29212100 has been withdrawn vide Customs Notification No. 12/2026 dated 1st April 2026, evidently in view of the prevailing geopolitical situation and consequential price pressures. In such a situation, recommending anti-dumping duty on EDA would directly counteract the policy objective underlying these Government measures. The Authority ought not to recommend a measure that neutralises the effect of the Government's own tariff liberalisation steps taken in the public interest.

- ix. It is submitted that there exists a significant and growing demand-supply gap in India for EDA. The domestic industry's capacity is demonstrably insufficient to satisfy even half of the total Indian demand. Imports from non-subject countries such as Japan, USA, Korea RP, Singapore, and UAE are already entering the Indian market at prices comparable to or more competitive than those from the subject countries. Any restriction on imports from subject countries will simply trigger a shift in the source of imports, with no discernible benefit to the domestic industry.
- x. The true and sustainable remedy for the domestic industry lies not in trade protection but in undertaking fundamental structural improvements, including vertical integration, capacity expansion, and achieving economies of scale to bring its cost structure to globally competitive levels.
- xi. It is submitted that EDA serves as a vital intermediate for numerous essential agrochemical products including Mancozeb. The imposition of anti-dumping duties on EDA imports will inevitably lead to increased raw material costs cascading through the value chain, raising prices for downstream agrochemical formulations. Such increased costs would impose a direct burden on farmers by raising the prices of critical crop protection chemicals, potentially undermining agricultural yields and farm incomes, and would be contrary to the country's broader economic and public interest objectives.
- xii. It is further requested that the import data be provided in the same format and manner in which the same was taken on record for the purpose of investigation, in line with the judgement of the Hon'ble CESTAT in Exotic Decor Pvt. Ltd. vs. Designated Authority (Anti-Dumping Appeal No. 52233 of 2018) dated 12th June 2020.
- xiii. If the Authority determines that imposition of anti-dumping duty is warranted, it is submitted that such duty ought to be recommended for a limited period of two (2) years only, so that an unwarranted measure does not remain in force for an unduly prolonged period.
- xiv. It is submitted that the Authority unjustifiably rejected the sole domestic sale transaction of a producer on the grounds of 'off-grade quality' and 'not in sufficient quantity', without conducting the analysis required under Article 2.2 of the ADA and Rule 10 of the Rules. The mere characterisation of a product as 'off-grade' does not, without further inquiry, render it outside the ordinary course of trade.
- xv. It is further submitted that imports from Saudi Arabia declined by more than 20% during the POI, and the domestic industry was profitable when Saudi import volumes were higher, negating any causal link. The DGTR has failed to conduct a proper non-attribution analysis under Article 3.5 of the ADA with respect to: (a) the 92% decline in export performance of the domestic industry; (b) MEA price fluctuations; and (c) geopolitical tensions, supply chain disruptions, and climate change as acknowledged in the Annual Report for 2024-25. Accordingly, the investigation should be terminated insofar as it relates to Saudi Arabia.
- xvi. It has been submitted by certain downstream importers/users that cumulative assessment is inappropriate as imports from different subject countries compete under different conditions, at different price levels, through different trade channels.
- xvii. The weighted average price undercutting of approximately 10-11% is nominal and is not evidence of significant price injury. The price decline coincided with a broad correction in global EDA prices post-COVID.
- xviii. The domestic industry showed positive trends in employment (up 44%), productivity per day (up 11%), and total wages (up 141%) during the POI, which are inconsistent with a finding of material injury.
- xix. The Authority's impact analysis of ADD on Mancozeb is based on incorrect consumption assumptions. Verified production records show different actual consumption ratios. An ADD of 20-30% would erode profitability in thin-margin industries.
- xx. The imposition of ADD would create supply shortages and grant undue pricing power to the sole domestic producer, risking a monopolistic outcome, with inflationary effects and weakening India's export competitiveness.

K.2. Submissions by the Domestic industry

127. The domestic industry has made the following submissions on the disclosure statement:

- i. That the Authority has rightly proposed in the disclosure statement not to exclude ethylene diamine used for the production of spandex yarn. The specifications relied on by the other interested parties were based on a sample supplied to them in 2020-21. After 2020-21, the domestic industry has undertaken significant research and development efforts to enhance the product to meet the technical requirements, and the product is now being supplied to other producers of spandex. The domestic industry's product satisfies all the specified parameters, including appearance, colour, water content, purity and organic impurity, and the specifications can be modified based on customer requirements without any new machinery. They have

also requested the Authority to confirm the scope of the product under consideration as proposed in the disclosure statement.

- ii. That the Authority should confirm that the dumped imports from the subject countries have caused material injury to the domestic industry in the final findings.
- iii. That the customers have increasingly shifted their purchases to imported goods originating from the subject countries on account of their lower prices. The evidence on record further demonstrates that import prices are routinely used by customers as a benchmark during commercial negotiations, exerting significant downward pressure on the domestic industry's prices in order to retain market share.
- iv. That the Authority has rightly noted that imports from Japan, Korea and the United States of America cumulatively account for less than 6% of total imports and, therefore, cannot be regarded as a contributing factor to the injury suffered by the domestic industry. The Authority has further found that no other known factor has caused injury to the domestic industry. In these circumstances, the domestic industry reiterated that the injury suffered is solely attributable to the dumped imports from the subject countries, and that a clear and direct causal link exists between the surge in low-priced dumped imports and the deterioration in the domestic industry's volume, price, and financial performance parameters.
- v. That the users were buying imported product at substantially higher prices in previous years. Since prices have declined steeply in the period of investigation, the imposition of anti-dumping duty, restoring level playing field is not likely to have any material impact on downstream users. It is also submitted that EDA forms only a small part of the cost of the downstream products approximately 30% for epoxy curing agents, 15% for Mancozeb, and less than 1% for elastomeric filament yarn with correspondingly limited impact on the price of end-products. The impact of a notional 20% duty on the price of the final product ranges from 0.18% to 5.96%, which is negligible.
- vi. The imposition of anti-dumping duty will not restrict imports from the subject countries but will ensure that imports are available at fair prices. It will not lead to scarcity of the subject goods in India. The domestic industry cannot be expected to expand its capacity in the face of significant dumping, and the user industry did not establish its operations expecting continued access to dumped imports.
- vii. The domestic industry is the sole producer of EDA in India and the dumping of the product has discouraged other potential producers from setting up capacities. If anti-dumping duty is not imposed, there is a real risk of plant shutdown, which would adversely affect employment, livelihoods, and the objectives of the Government's Atmanirbhar Bharat initiative.
- viii. The domestic industry has obtained approval for expansion of capacity to 37,350 MT for the product under consideration. The imposition of anti-dumping duty for a period of five years would provide the necessary stability and financial support to the domestic industry to recover from its losses, undertake capacity expansion, and make further investments.
- ix. The domestic industry requests the Authority to recommend imposition of anti-dumping duty for a period of five years. Unless the duty is imposed for five years, the domestic industry will not be able to adequately recover from the significant injury suffered as a result of dumped imports. The domestic industry's Board of Directors has been reluctant to approve the proposed capacity expansion investment owing to the losses incurred due to dumped imports, and the imposition of anti-dumping duty for five years would provide the requisite stability for such investment.

K.3. Examination by the Authority

128. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties. It is observed that the majority of these submissions are reiterations of arguments and contentions that have already been examined and are therefore addressed to the extent deemed necessary in the relevant paragraphs of these final findings. For the sake of brevity, the Authority has refrained from repeating responses to such issues in this post disclosure examination. However, any new issues raised for the first time in the post disclosure submissions, as well as those previously addressed but deemed necessary to examine further, are addressed hereunder.
129. The Authority confirms the scope of the product under consideration and eligibility of the applicant as Domestic Industry as defined in the disclosure statement.
130. The Authority issued confidential copy of disclosure to the various interested parties regarding determinations of Normal value, Net export price, landed value and non-injurious price. No comments have been received from any of the interested parties after the issuance of disclosure statement; hence, the Authority confirms the dumping margin determined for various producers and exporters from subject countries.

131. On the submission regarding imports from Japan, USA and Korea RP, the Authority has examined the verified transaction-wise import data from DG Systems and notes that imports from these countries cumulatively account for less than 6% of total imports during the period of investigation. The threshold of 7% prescribed under Rule 14(d) of the Rules for inclusion of low-volume source countries has not been met. There is no legal basis for inclusion of these countries within the scope of the present investigation.
132. On the contention that the downward revision of non-subject country import data in the disclosure statement was asymmetric, the Authority clarifies that the revision applies uniformly to data from all source countries and is a consequence of the verification exercise that removes duplications, mis-coded transactions, and non-EDA entries. The allegation is not borne out by any specific transaction-level evidence and is rejected.
133. In relation to the submissions on causal link, the Authority has observed that the conditions now alleged to have broken the causal nexus between dumped imports and the injury suffered by the domestic industry, such as dependence on imported raw materials, absence of captive production or backward integration, locational disadvantages, and other structural characteristics, existed throughout the injury period and remained unchanged between the years when the domestic industry was earning profits and the period of investigation when it incurred losses. The domestic industry was profitable in 2021-22 and 2022-23 despite the existence of these very same conditions. Accordingly, such factors cannot be regarded as the cause of the deterioration in the domestic industry's performance. The only material change during the period of investigation was the substantial increase in dumped imports at injurious prices, resulting in significant price suppression and depression. Therefore, the injury suffered by the domestic industry is clearly attributable to dumped imports from the subject countries and not to the structural characteristics cited by the interested parties.
134. The Authority has conducted a cumulative assessment of imports from the subject countries, as all the conditions prescribed under Annexure II of the Rules are satisfied. The dumping margins and import volumes from each subject country are above the prescribed thresholds, and the conditions of competition warrant a cumulative assessment. The mere decline in imports from a particular subject country does not preclude its inclusion in the cumulative injury analysis.
135. The Authority observes that the withdrawal of Basic Customs Duty under Notification No. 12/2026-Customs and the imposition of anti-dumping duty serve different purposes and operate under different legal provisions. Therefore, the withdrawal of BCD does not prevent the Authority from recommending anti-dumping duty where dumped imports are causing injury to the domestic industry.
136. In relation to the submission regarding trade diversion, the Authority observes that anti-dumping duty does not prohibit or restrict imports, it merely ensures level playing field in the Indian market. The possibility of trade diversion is speculative and is not a ground for declining to address proven dumping and injury.
137. In relation to the impact on the downstream industry, the Authority has observed that EDA constitutes only a small proportion of the cost of downstream products, and even on a notional anti-dumping duty of 20%, the impact on the prices of finished products would be minimal. The Authority further noted that no downstream user has demonstrated that such an increase would make its operations unviable. Moreover, the downstream industry remained profitable during 2022-23 when EDA import prices were significantly higher than the current levels. Accordingly, the imposition of anti-dumping duty is unlikely to have any material adverse impact on the downstream industry.
138. In relation to the demand-supply gap, it is noted that anti-dumping duty does not restrict imports but merely ensures level playing field between domestic producers and imports products. Since domestic industry is presently operating at only 36% of its installed capacity and has the necessary approvals for further expansion, demand supply gap cannot be a ground for continued dumped imports from the subject countries. The underutilisation of capacity is primarily due to the presence of low-priced dumped imports, and therefore, the imposition of anti-dumping duty is necessary to restore fair competition and enable the domestic industry to increase production and expand capacity.
139. The Authority notes the submissions made by the interested parties regarding disclosure of import data and the reliance placed on the decision of the Hon'ble CESTAT in Exotic Decor. The Authority, however, notes that import information obtained from DG Systems is treated in accordance with the confidentiality provisions contained in Rule 7 of the Rules. However, the Authority has disclosed all essential facts under consideration, including import volumes, landed values, trends, and methodology adopted for the purpose of the present investigation. The interested parties have been provided adequate opportunity to inspect the public file and offer comments on the information relied upon by the Authority. The Authority is therefore satisfied that the requirements of natural justice and the provisions of the Rules have been duly complied with.
140. In relation to the period of anti-dumping duty, the Authority notes that Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975 contemplates imposition of anti-dumping duty for a period not exceeding five years, which is the standard period followed in anti-dumping investigations. The Authority further notes that none of the interested parties have provided any cogent reasons or exceptional circumstances warranting a departure from the

standard five-year period and limiting the measure to two years. In view of the continued material injury suffered by the domestic industry and the absence of any justification for a shorter duration, the Authority finds no merit in the submissions seeking a two-year duty period and recommends imposition of anti-dumping duty for a period of five years.

141. On export performance, the Authority has examined the submission that the 92% decline in the domestic industry's export sales during the POI is itself a consequence of the globally depressed price environment in which dumped imports have played a central role. When the domestic industry is unable to realise remunerative prices in the domestic market due to injuriously priced imports, its competitive position in export markets is simultaneously eroded. Accordingly, the decline in export performance is not an independent cause of injury it is a symptom of the same injury caused by dumped imports. This factor cannot be attributed as a non-dumping cause of injury.
142. Further, the single domestic transaction of 15 MT, considered against the scale of Sadara's production and its exports to India, does not meet the minimum threshold required to establish a representative domestic market price. International practice and the text of Article 2.2 both recognise that domestic sales may be disregarded where the volume is insufficient to permit a proper comparison. Both independent grounds — off-grade quality and insufficient volume — separately justify construction of normal value. The finding in the Disclosure Statement is confirmed.
143. On price undercutting and price effects, the Authority confirms its findings on price effects as set out in the Final Finding. Import prices declined by approximately 41% over the injury period, against a raw material price decline of only 17%. This disproportionate decline establishes that import prices have not merely tracked feedstock cost movements. Price undercutting ranges from 7% to 16% across subject countries, with a weighted average of 11%. In the context of an industry with thin margins where import prices during the POI fell below even the variable cost of production of the domestic industry, this level of undercutting is injurious. The submission that 10-11% undercutting is 'nominal' is not accepted.
144. The Authority acknowledges that employment, productivity, and wages showed positive trends during the POI. However, the injury determination under Rule 11 read with Annexure II of the Rules requires a holistic examination of all relevant economic indicators. The positive movement in employment and wages is vastly outweighed by the sharp deterioration in production, domestic sales, capacity utilisation, profitability, cash profits, and return on capital employed — all of which are key indicators. The domestic industry has expanded its workforce while absorbing severe financial losses, which evidences resilience despite injury rather than absence of injury.
145. In relation to the impact on the downstream industry, the Authority has observed that EDA constitutes only a small proportion of the cost of downstream products, and even on a notional anti-dumping duty of 20%, the impact on the prices of finished products would be minimal. The Authority further noted that no downstream user has demonstrated that such an increase would make its operations unviable. Moreover, the downstream industry remained profitable during 2022-23 when EDA import prices were significantly higher than the current levels. Accordingly, the imposition of anti-dumping duty is unlikely to have any material adverse impact on the downstream industry.
146. The Authority notes that the domestic industry's estimate of 250 kg of EDA per 1,000 kg of Mancozeb stands unverified, and has taken the users' consumption data into account to the extent verifiable. Even at the higher EDA ratio contended by the users, EDA constitutes only a limited proportion of the cost of production of Mancozeb, and the impact of anti-dumping duty at the recommended level is not material. The downstream industry having remained profitable during 2022-23, when landed prices of imported EDA were significantly higher, the Authority holds that it can absorb a moderate price correction attributable to the duty, and the apprehension of an adverse downstream impact is not substantiated.
147. On monopolistic risk and supply availability, anti-dumping duty does not prohibit or restrict imports — it merely ensures imports enter the Indian market at fair, non-injurious prices. The domestic industry is currently operating at only 36% of its installed capacity and holds necessary approvals for further capacity expansion to 37,350 MT. Imposition of ADD will create conditions for the domestic industry to increase production, expand capacity, and serve a larger share of domestic demand. There is no basis for the contention that ADD will result in supply shortages or monopolistic pricing.

L. CONCLUSION

148. Having regard to the contentions raised, information provided, and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and based on above analysis of the dumping, injury and causal link to the domestic industry, the Authority concludes as follows:

- a. **On scope of product under consideration and like article**

- i. The product under consideration (PUC) in the present investigation is 'Ethylene Diamine', abbreviated as "EDA".
 - ii. The article manufactured by the domestic industry and the subject goods exported from the subject countries are like article to each other in terms of Rule 2 (d) of the Rules.
- b. On domestic industry and standing**
- i. The applicant is the sole producer who has produced the product in the period of investigation.
 - ii. Balaji Speciality Chemicals Limited is an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
- c. On normal value and export price**
- i. Producers from China PR, European Union and Saudi Arabia have participated in the present investigation. There is no response from Taiwan.
 - ii. China PR is presumed as a non-market economy country since none of the producers/exporters from China PR have provided sufficient evidence to rebut this presumption as mentioned in para 8 of Annexure – I of the Rules.
 - iii. The response filed by the producers from China PR, European Union and Saudi Arabia shows that the product has been exported to India at dumped prices.
 - iv. The dumping margin for the product under consideration from each of the subject countries is seen to be more than de minimis.
- d. On injury and causal link**
- i. The imports from the subject countries have increased in absolute and relative terms.
 - ii. While the raw material prices have declined by 17 index points as compared to the base year, the import price has declined by 38 index points.
 - iii. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry, and the price undercutting is positive and significant.
 - iv. The landed price of imports is below the cost of sales of the domestic industry in the period of investigation. The prices of the domestic industry were depressed in the period of investigation.
 - v. The production, domestic sales and capacity utilization of the domestic industry declined in the period of investigation. The domestic industry has sold at losses to increase its sales.
 - vi. The profit per unit has declined from Rs 66,592 per MT to loss of Rs 19,943 per MT. Cash profit and return on capital employed of the domestic industry similarly declined in 2022-23 and thereafter negative in the period of investigation.
 - vii. The dumped imports have affected the prices of the domestic industry.
- The investigation did not show any factor other than dumping from the subject countries which could have caused injury to the domestic industry.
- e. On Indian industry interest**
- i. The domestic industry is suffering material injury, and the imposition of anti-dumping duty will be in interest of domestic producer.
 - ii. The imposition of duties will not be against public interest.

M. RECOMMENDATIONS

149. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers, and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury, causal link and impact of recommended measures. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, and causal link in terms of provisions laid down under the anti-dumping rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset the dumping and injury. The Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.

150. Having regard to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of final anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury on imports of subject goods originating in or exported from the subject countries so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject countries, for a period of five (5) years, from the date of the notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below.

DUTY TABLE

S. No.	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	UOM	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29212100	Ethylene Diamine	China	Any country including China	BASF-YPC Company Limited	350	MT	\$
2	-do-	-do-	China	Any country including China	Any producer other than mentioned in SN 1	575	MT	\$
3	-do-	-do-	Any country other than China, European Union, Saudi Arabia and Taiwan	China	Any producer	575	MT	\$
4	-do-	-do-	European Union	Any country including European Union	BASF Antwerpen NV	464	MT	\$
5	-do-	-do-	European Union	Any country including European Union	Any producer other than mentioned in SN 4	739	MT	\$
6	-do-	-do-	Any country other than China, European Union, Saudi Arabia and Taiwan	European Union	Any producer	739	MT	\$
7	-do-	-do-	Saudi Arabia	Any country including Saudi Arabia	Sadara Chemical Company	230	MT	\$
8	-do-	-do-	Saudi Arabia	Any country including Saudi Arabia	Any producer other than mentioned in SN 7	375	MT	\$
9	-do-	-do-	Any country	Saudi	Any	375	MT	\$

			other than China, European Union, Saudi Arabia and Taiwan	Arabia	producer			
10	-do-	-do-	Taiwan	Any country including Taiwan	Any producer	301	MT	\$
11	-do-	-do-	Any country other than China, European Union, Saudi Arabia and Taiwan	Taiwan	Any producer	301	MT	\$

Note 1 – Customs classification mentioned above is only indicative.

Note 2 – The application of the individual duty rates specified for the producers mentioned in the above table shall be conditional upon presentation to customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

“I, the undersigned, certify that the (volume) of Ethylene Diamine, abbreviated as “EDA” sold for export to the India covered by this invoice was manufactured by (producer name and address) in [country concerned]. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.”

If no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations.

N. FURTHER PROCEDURE

An appeal against the order of the Authority arising out of this final finding shall lie before the Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Customs Tariff Act.

AMITABH KUMAR, Designated Authority